प्रेरणा

रुदन कमजोर होने की निशानी नहीं है, रुदन को जीवित होने की निशानी माना है। - शार्लेट ब्रॉन्टे

संपादकीय

मनरेगा में बदलाव की आखिर क्या वजहें रही?

वर्ष 2005 में शुरू हुए मनरेगा (नरेगा) का नाम भी बदलेगा और प्रारूप भी। सरकार मानती है कि बदलाव जरूरी हो गया है। नए कानून के बाद कार्यदिवस 100 की जगह अब 125 होंगे, लेकिन कृषि कार्य के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दो माह की अवधि तक इस योजना में काम नहीं होगा। कानून के मसौदे के अलावा एक एफएक्यू जारी करते हुए योजना की वे कमियां भी बताई गईं, जिनके कारण बदलाव जरूरी हो गया। इसकी बिंदु संख्या 6 के अनुसार गरीबी 12 वर्षों में घटकर 25.7% से 4.86% रह गई है। प. बंगाल का नाम लेते हुए बिंदु 10 कहता है कि इसके 19 जिलों में बिना काम पेमेंट और फंड के गलत इस्तेमाल की घटनाएं मिलीं, जबकि वर्ष 2025-26 की मॉनिटरिंग में 23 राज्यों में काम बिलकुल न होने या खर्च से कम होने की घटनाएं पाई गईं और कुल 193 करोड़ रु. का घोटाला (मिसएप्रोप्रिएशन) पाया गया। लेकिन बिंदु संख्या 9 में यह भी बताया गया है कि मनरेगा में समय-समय पर बदलाव से महिलाओं की भागीदारी सवा गुना बढ़ी और करीब 12 करोड़ श्रमिक इस योजना से जुड़े। केंद्र का दावा अगर सच भी मानें तो औसतन एक लाख करोड़ रुपए के व्यय में 1.93% की गड़बड़ी कोई बड़ा कारण नहीं है। दूसरे, कोरोना के बाद माना गया कि इस स्कीम ने पलायन के शिकार में गरीबों को भयंकर भुखमरी से बचाया। वर्ल्ड बैंक ने भी द स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट शीर्षक रिपोर्ट में इस योजना को बेहतरीन बताया। फिर आज यह गलत कैसे हो गई?

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

मनुष्य जितना नीचे गिरेगा, उतना पतित होता जाएगा

कायदे से तो मंदिर में जाकर अहंकार गिराना चाहिए, पर कुछ लोग वहां जाकर आचरण गिरा देते हैं। पानी कितना ही नीचे गिरे, पानी ही रहेगा। लेकिन मनुष्य जितना नीचे गिरेगा, उतना ही पतित और पशुवत होता जाएगा। लोग धार्मिक क्षेत्र में भी भ्रष्ट होने के नए-नए मानक स्थापित कर रहे हैं। इन दिनों मांसाहार, शाकाहार और भ्रष्टाचार- इसकी बड़ी चर्चा होती है। मांसाहार में हम दूसरों का जीवन समाप्त करके अपना पेट भरते हैं। शाकाहार में हम प्रकृति का सम्मान करते हुए अपना उदर तृप्त करते हैं। और भ्रष्टाचार में हम एक व्यवस्था के प्राण ले लेते हैं। इस समय दुनिया मांसाहार के प्रति उदासी बरत रही है। मीटलेस मंडे, वीगन फ्राइडे- इन सबका चलन बढ़ गया है। लोगों को समझ आ गया है कि मांसाहार छोड़ने से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर अनुकूल असर पड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचारी लोग और बिगड़ रहे हैं। देश के सबसे धनाढ्य मंदिर में पहले लड्डू का भ्रष्टाचार किया। अब साड़ी प्रकरण सामने आ गया। ये भगवान के रोटी, कपड़ा, मकान- तीनों पर आक्रमण कर रहे हैं। आस्थावान आहत हैं और अपराधी अदृश्य हैं।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

हमें फॉरेंसिक क्षमता मजबूत करनी होगी

भारत को अपनी साइबर फॉरेंसिक क्षमता को और अधिक मजबूत करना होगा। केवल विदेशी सर्वरों पर निर्भर रहना सही नहीं। इसके बजाय देश में ऐसे तकनीकी ढांचे विकसित करने होंगे, जो रियल-टाइम ट्रैकिंग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तेज कानूनी प्रक्रियाओं को संभव बना सकें। साथ ही वीपीएन और फर्जी ईमेल सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सख्त नियमों और समझौतों की भी जरूरत है। -कांतिलाल मांडोत, सूरत, गुजरात

पीजीआई में रिक्त पद भरे सरकार

संसद में पेश किए डेटा के मुताबिक चंडीगढ़ के बड़े सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे मेडिकल और पैरा-मेडिकल पद खाली हैं। इसका मरीजों की देखभाल पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मरीजों की जान से खेलने के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। आबादी के अनुसार मेडिकल हेल्थ सर्विस को बदहाली से बचाने के लिए सरकारों को सभी श्रेणी के रिक्त पदों को नियमित भरते रहने की जरूरत है। -एसके खोसला, चंडीगढ़

वोटर वर्तमान वार्ड में जुड़वाएं नाम

मतदाता सूची एसआईआर में अनेक मतदाताओं ने अपने वर्तमान वार्ड के बजाय पुराने पते के वार्डों में ही फॉर्म जमा करवाया है। मतदाता सूची शुद्धिकरण के समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि मतदाता अपने वर्तमान वार्ड में ही नाम जुड़वाए। मतदाताओं से अपील है कि वर्तमान पते की सूची में नाम स्थानांतरित करवा लें। पुराने पते पर फार्म भरना वैधानिक रूप से भी सही नहीं है। -मुकेश चौबे, रायपुर, छत्तीसगढ़

यात्री परिवहन में मुनाफाखोरी रुके

इंडिगो संकट का फायदा उठाकर दूसरी एयरलाइंस ने विमान यात्रा के रेट अनाप-शनाप बढ़ा दिए। करोड़ों मध्यमवर्गीय और गरीब लोग रोज ट्रेन और बसों की यात्रा करते हैं। उनके लिए भी इस तरह का अनुभव नया नहीं है। जब ट्रेन लेट, कैंसल होती है या रिजर्वेशन नहीं मिलता तो बस किराए भी इसी तरह बढ़ा दिए जाते हैं। सरकार को यात्री परिवहन साधनों में ऐसी मुनाफाखोरी को रोकना चाहिए।
-सुरेश कासलीवाल, भोपाल, मध्यप्रदेश

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

7 देशों से गुजरती है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत शृंखला

एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत शृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर महाद्वीप के उत्तर से दक्षिणी छोर तक फैली हुई है। पर्वतमाला की कुल लंबाई 7000 किलोमीटर से अधिक है। चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला—सात देशों से होकर गुजरने वाली यह पर्वतमाला जलवायु, जैव-विविधता पर गहरा असर डालती रही है। दुनिया के ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित 99% ग्लेशियर एंडीज पर्वतमाला में ही पाए जाते हैं।

5500 ग्लेशियरों पर हुए एक अध्ययन के आधार पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही चेतावनी दी है कि ये वैश्विक औसत से 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। इससे दक्षिण अमेरिकी देशों में जल संकट पैदा हो सकता है।

बामुलाहिज़ा • सार्वजनिक उपक्रमों वाले पुराने दौर में इंडिगो संकट पर जिम्मेदारों की छुट्टी हो जाती

सवाल निजी क्षेत्र की क्षमताओं पर उठे हैं

गवर्नेंस

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
X @ShekharGupta

भारत में आर्थिक सुधारों के बाद सबसे बड़े ग्लोबल ब्रांड के रूप में उभरे इंडिगो की जो कहानी सामने आई है, उस पर तीन तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और इन तीनों के साथ एक ही तरह की हताशा जुड़ी है।

पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि इंडिगो के संस्थापक और उसके प्रबंधक जरूर बड़े नासमझ, विचारशून्य या अहंकारी होंगे कि उन्होंने इसे इस तरह बिखरने दिया। दूसरी यह हो सकती है कि जो भी सरकार से खासकर उस समय रार ठानने की सोच रहा होगा, जब पुतिन शहर में पधारे हुए थे, वह जरूर गलती कर रहा होगा। और तीसरी प्रतिक्रिया उनकी हो सकती है जो दशकों से यह कहते रहे हैं कि सरकार का उन मामलों में दखल नहीं होना चाहिए, जिनमें निजी क्षेत्र बेहतर सेवा दे सकता है। ऐसे लोग कह सकते हैं कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि इसका उलटा कर बैठें?

इतने वर्षों से निजी विमान सेवा विकास करती रही थी। वह जेट एयरवेज और किंगफिशर के बिखराव को भी झेल गई। एअर इंडिया का निजीकरण हुआ। तब पुरानी हुकूमत में कई लोग अपनी सत्ता छिन जाने से नाराज हो रहे थे। क्योंकि अब आखिर कोई विमान नहीं खरीदा जा रहा था, नौकरियां या ठेके देने का काम नहीं हो रहा था, उपभोग की चीजों की खरीद नहीं हो रही थी। सरकार को कम-से-कम एक मामले में अप्रासंगिक बना दिया गया था। इस मामले में निजी क्षेत्र ने ऐसी सफलता हासिल की थी, जिससे दुनिया ईर्ष्या कर सकती थी। टेलीकॉम सेक्टर में पुराने अधिकारों का कम-से-कम कुछ अवशेष तो सरकार के हाथ में मौजूद है, जैसे स्पेक्ट्रम की बिक्री, बीएसएनएल के रूप में एक सक्रिय 'पीएसयू' और वोडाफोन-आइडिया में 49 फीसदी की इक्विटी। लेकिन नागरिक विमानन में उसके हाथ में महत्वहीन हेलीकॉप्टर चार्टर के सिवा कुछ नहीं है। लगभग सारे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट निजी हाथों में हैं और कई दूसरे भी जल्द ही उन्हीं के हाथों में जाने वाले हैं।

लेकिन अब सरकार फिर से वापस आ गई है और वह भी किस तरह से! मंत्री जी एक टीवी चैनल से दूसरी तक जाकर इंडिगो संकट को दुरुस्त करने के वादे कर रहे, उन सूचीबद्ध कंपनियों का प्रबंध परोक्ष रूप से अपने हाथ में लेने की बात करते रहे, जिनका मूल्य 2 लाख करोड़ (2 ट्रिलियन) रुपए या 24 अरब डॉलर के बराबर है, बावजूद इसके कि करीब 15 फीसदी तो संकट के दौर में ढह जाती हैं। कोई निजी कंपनी घालमेल करे, लेकिन इसके लिए सफाई या सवालों के जवाब उसका सीईओ नहीं, एक मंत्री दे रहा हो, ऐसा तो सिर्फ भारत में ही हो सकता है।

मंत्री ने सीईओ की छुट्टी कर देने की बात कही और उसे इस सेक्टर के रेगुलेटर के हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया। सीईओ ने पहले तो पायलटों के काम के घंटों से संबंधित उन नियमों को वापस ले लिया, जिन्हें लागू करवाने में केंद्रीय मंत्रालय और रेगुलेटर दो साल से ऊपर से नाकाम रहा है। इसके बाद फरवरी 2026 तक अपनी उड़ानों की संख्या में कटौती कर दी। अब वे बड़ी बातें कर रहे हैं कि दो का वर्चस्व (डुओपोली) खराब चीज है इसलिए वे चाहेंगे कि 5 एयरलाइन हों, जिनमें से हर एक के पास 100 विमान हों।

क्या वे इंडिगो और चूंकि यह एयरलाइन भारतीय विमानन का दो तिहाई हिस्सा है, इसलिए भारतीय विमानन को अमेरिका के 'बेबी बेल्स' वाले दौर में ले जाना चाहते हैं? एक समय अमेरिका में एटीएंडटी कंपनी के एकाधिकार को 'रीजनल बेल ऑपरेटिंग' कंपनियों में तोड़ा गया था, लेकिन इस प्रसंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मंत्री अपने स्टाफ को गूगल सर्च करने को कह सकते थे। भारतीय विमानन विशाल दिखता है लेकिन इसके और विकास की संभावनाएं हैं। इंडिगो को ही लीजिए। उसने 1400 और विमानों की खरीद के ऑर्डर दिए हैं। एअर इंडिया ने करीब 570 विमानों और अकासा एयर और स्पाइसजेट ने करीब 200 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर दिए हैं। जब भारत में 500-500 विमानों वाली पांच एयरलाइनों की गुंजाइश है, तब हम केवल 100-100 विमानों वाली पांच एयरलाइनों की बात ही क्यों करें?

'मिनिमम गवर्नमेंट' वाली बात का आखिर क्या हुआ?

असली मुद्दा भारत की नाटकीय सफलता की कहानी के मूल में सरकार की वापसी का है। इंडिगो के कॉर्पोरेट मुख्यालय में फैसले करने वाले प्रमुख पदों पर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का आखिर क्या मतलब हो सकता है? मिनिमम गवर्नमेंट वाली बात का क्या हुआ?

इस अविश्वसनीय सफलता की भारतीय कहानी इसलिए सच साबित हुई थी, क्योंकि सत्ता-तंत्र ने उस बात को आखिरकार अपना लिया था, जिसे प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहे हैं कि सरकार का काम बिजनेस की दुनिया में दखल देना नहीं है। जहां भारतीय विमानन वैश्विक पैमाने के मुताबिक विकास कर रहा है, इसके प्रभारी मंत्री इसे और तोड़ने की बात कर रहे हैं।

लेकिन लगता है कि मंत्री पर नाराजगी जाहिर करके हम दिशा भटक रहे हैं। उन्हें ऐसा 'ग्लैमरस' मंत्रालय दिया गया था, जिसमें फीते काटने से ज्यादा बड़ा शायद ही कोई काम था, लेकिन एक संकट ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। बहरहाल, हम असली मुद्दे पर आएं। असली मुद्दा भारत की नाटकीय सफलता की कहानियों के मूल में सरकार की वापसी का है। इंडिगो के कॉर्पोरेट मुख्यालय में फैसले करने वाले प्रमुख पदों पर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का आखिर क्या मतलब हो सकता है? यह जवाबदेही मुक्त 'माइक्रो-मैनेजमेंट' है। ये उसी रेगुलेटर नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से आते हैं, जिसने विमानों के चालक दल के 'रेस्ट-एंड-रिकवरी' के लिए ऐसे नियम बनाए, जिनसे रूढ़िवादी यूरोपीय लोग भी परहेज करेंगे। लेकिन यह सब उन लोगों की सहमति लिए बिना किया गया, जिन पर दारोमदार है।

इंडिगो को कई दोष दिए जा सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध यह है कि उसने जनाक्रोश का सामना होने पर सरकार को अपना पालनहार बना लिया। जिस सरकार ने एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को एकाधिकार वाली कंपनी बना दिया था, फिर उनका पतन देखा और विमान खरीद के कई घोटालों का सामना किया। और अब यह फिर से मैदान में आ गई है।

आखिर इंडिगो ने यह पतन क्यों होने दिया और इस उम्मीद में खंदक में क्यों जा छिपी कि संकट खुद दूर हो जाएगा? सोशल मीडिया के इस दौर में, जब हर एक उपेक्षित यात्री की अपनी आवाज है और हरेक भटका हुआ सामान अपनी पहचान रखता है, आप अपनी अक्षमता को छुपा नहीं सकते। सार्वजनिक उपक्रमों वाले पुराने दौर में तो इसके लिए जिम्मेदारों की छुट्टी की जा सकती थी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

विश्लेषण • चुनाव सुधारों की गुंजाइश बनी हुई है

चुनावों में धनबल व बाहुबल पर अंकुश लगाना अब जरूरी

निर्वाचन

संजय कुमार
प्रोफ़ेसर और चुनाव विश्लेषक
sanjay@csds.in

भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई समितियां गठित की गई हैं। इनके तहत समय-समय पर ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिनसे मतदाता की दृष्टि से चुनाव अधिक सहभागी बने हैं, चुनाव आयोग के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आसान हुआ है और उम्मीदवारों की जवाबदेही भी बढ़ी है।

लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अब भी गंभीर ध्यान देने की जरूरत है- पहला, चुनावों को कम खर्चीला कैसे बनाया जाए और दूसरा, आपराधिक या दागी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से कैसे रोका जाए। हाल ही में संसद में हुआ कई घंटों का लंबा विमर्श भी इसी चिंता को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश था। इस चर्चा के दौरान चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने से जुड़े अनेक विषय तो उठे, लेकिन चुनावों में धनबल और बाहुबल पर अंकुश लगाने पर कोई ठोस बहस नहीं हो सकी।

भारत में चुनाव सुधारों की यात्रा की शुरुआत 1974-75 में हुई, जब मतदान की आयु, मतदाता सूचियों की शुद्धता तथा चुनावों में धन और बाहुबल पर अंकुश जैसे मुद्दों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति का गठन किया गया। 1990 में गठित दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव आयोग की शक्तियों, दलबदल विरोधी कानून, उपचुनावों सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार किया। 1993 में बनी वोहरा समिति का उद्देश्य राजनीति और अपराध के गठजोड़ की जांच करना था। 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनावी खर्च से जुड़े प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया।

इसके अलावा, विधि आयोग की कई रिपोर्टों (1999, 2014 और 2015) में भी भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित मुद्दों को रेखांकित किया गया। चुनाव आयोग ने भी 2004 में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपकर चुनाव संचालन की प्रक्रिया में आवश्यक सुधारों का सुझाव दिया था। 2010 की तनखा समिति की रिपोर्ट ने भी चुनाव कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी क्रम में सबसे हालिया पहल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। इस समिति को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यावहारिकता की जांच का दायित्व सौंपा गया।

चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए किए गए लंबे प्रयासों की इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव भी हासिल हुए हैं। बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल, बाद में उनमें वीवीपैट को जोड़ा जाना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अपनी संपत्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने वाला हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य करना, चुनाव प्रचार की अवधि को तीन सप्ताह से घटाकर दो सप्ताह करना, मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग, सेवाओं में कार्यरत लोगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था शुरू करना आदि। इसके बावजूद सुधार की गुंजाइशें बनी हुई हैं।

चुनावों में धनबल और बाहुबल केवल भारत की समस्या नहीं है; यह कई अन्य स्थापित लोकतंत्रों में भी मौजूद है। लेकिन भारत को इस मोर्चे पर भी वैसी ही पहल करनी होगी, जैसी उसने अन्य क्षेत्रों में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए की है।

संसद में जिन मुद्दों को उठाया गया, वे चुनाव सुधारों से अधिक कानूनी सुधारों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सबसे तात्कालिक जरूरत इस बात पर गंभीरता से विचार करने की है कि चुनावों में धन की भूमिका को कैसे कम या नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में चुनाव अत्यंत महंगे हो चुके हैं। इस पर हर कोई चिंता जताता है, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई ठोस और गंभीर प्रयास होते नहीं दिखे हैं। इसी तरह, भारत जैसे देश में, जहां दल-आधारित मतदान का वर्चस्व है और बड़ी संख्या में मतदाता उम्मीदवार के बजाय पार्टी को वोट देते हैं, दागी पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का समाधान कानूनी उपायों से अधिक राजनीतिक दलों के स्तर पर संभव है। यदि पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट ही न दें, तो समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

मुद्दा • अभी तो 100 दिन की गारंटी भी पूरी नहीं है

नाम बदलने की मुहिम में कहीं काम अधूरा न रह जाए

रोजगार गारंटी

प्रियदर्शन
लेखक और पत्रकार
priyadarshan.parag@gmail.com

नाम बदलने की राजनीति दुनिया भर में आम है। मुल्कों, शहरों, सड़कों, इमारतों के नाम बदले जाते हैं। भारत में भी यह प्रक्रिया उत्साह से चलाई गई। एक दौर में जो नाम बदले गए, उनका तर्क स्थानीय परम्परा और पहचान को लौटा लाने का था। इस तर्क से बॉम्बे को मुम्बई किया गया, मद्रास को चेन्नई और कलकत्ता को कोलकाता। ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेज शासकों के नाम पर रखे गए नाम भी बदले गए। कर्जन रोड कस्तूरबा गांधी मार्ग हो गया और कनॉट प्लेस राजीव गांधी चौक। हालांकि मुंह पर चढ़े पुराने नाम आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। कनॉट प्लेस भी बना हुआ है।

वैसे बीते दिनों नाम बदलने की जो मुहिम चली है, उसका वास्ता मजहबी पहचान और साम्प्रदायिक राजनीति के आग्रह से दिखता है। खासकर मुस्लिम पहचानों की स्टीरियोटाइपिंग की भी कोशिश दिख रही है। दिल्ली में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले बादशाह औरंगजेब के नाम पर चलती आ रही सड़क का नाम एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया- यह कहते हुए कि हमें औरंगजेब जैसे नहीं, कलाम जैसे मुसलमान चाहिए। इलाहाबाद को फिर भी प्रयागराज के रूप में कभी जाना जाता था, लेकिन बहुत लोकप्रिय नामों को बहुत अनजान और संस्कृतनिष्ठ नामों से बेदखल किया जा रहा है। इस वजह से हमारे शहर हमारे ही स्मृति-कोश से बाहर होते जा रहे हैं।

नाम बदलने की मुहिम में एक नया उत्साह दिख रहा है। पहले कहा गया कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना किया जाएगा। लेकिन फिर खबर आई कि इसकी जगह एक नया नाम चुना गया है- विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)। हिंदी-अंग्रेजी मिले ऐसे अजीब-से नाम की क्या जरूरत थी? क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप वीबी-जी राम जी बनता है। क्या यह महात्मा गांधी को पहले पूज्य बापू और फिर राम जी से विस्थापित करने की कोशिश है? इसके पीछे छुपी मंशा समझना मुश्किल नहीं है।

लेकिन नाम बदलने की इस राजनीति में मूल मुद्दे और असुविधाजनक सवाल पीछे रह गए हैं। इस नए कानून में रोजगार गारंटी सौ दिन की नहीं, सवा सौ दिन की होगी। इससे संदेश जाता है कि सरकार ने मजदूरों का, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों का बहुत खयाल रखा। लेकिन हकीकत क्या है? शनिवार के 'दैनिक भास्कर' में ही छपी खबर के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में जानकारी दी कि मनरेगा के तहत बीते पांच वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 50.24 दिन का रोजगार मिला है। यानी फिलहाल 100 दिन की गारंटी भी पूरी नहीं की जा रही है, फिर इसे 125 दिन कर देने के दिखावे का क्या मतलब है? सरकार रोजगार दे नहीं पा रही या लोग लेने नहीं आ रहे? दोनों ही सूरतों में 125 दिन की गारंटी का दिखावा तार-तार हो जाता है।

समस्या बस इतनी नहीं है। सरकार का कहना है कि इस योजना पर अमल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, केंद्र का काम बस इसकी समीक्षा करना है। लेकिन राज्यसभा में सरकार यह जानकारी भी दे रही है कि इस 5 दिसंबर तक मनरेगा के मद के 9746 करोड़ से ज्यादा की रकम बकाया है। यह 2025-26 के मनरेगा के बजट का करीब 27 फीसदी है। तो सच्चाई यह है कि बीते करीब दो दशकों में जिस योजना ने इस देश के गरीब मजदूरों का पलायन कुछ घटाया, उद्योग-धंधों में चलने वाला उनका शोषण कुछ कम किया, उसे ठीक से लागू तक नहीं किया जा रहा है।

नाम महात्मा गांधी रखिए, पूज्य बापू या जय राम जी- योजना अमल में आएगी तो लोगों का भला होगा, वरना आखिरी आदमी तक पहुंचने का जो जंतर गांधी ने दिया था, वही नाकाम हो जाएगा और रामराज्य भी अधूरा रह जाएगा।

नाम महात्मा गांधी रखिए, पूज्य बापू या जय राम जी- योजना ठीक से अमल में आएगी तो लोगों का भला होगा, वरना आखिरी आदमी तक पहुंचने का जो जंतर गांधी ने दिया था, वही नाकाम हो जाएगा और रामराज्य भी अधूरा रह जाएगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

सहभागिता • 'लिंक वेस्ट' नीति से 'एक्ट वेस्ट' पॉलिसी तक पश्चिम एशिया में एक स्थायी दस्तक की ओर

पश्चिम एशिया से हमारे संबंधों का एक नया दौर शुरू हो रहा है

वेस्ट एशिया

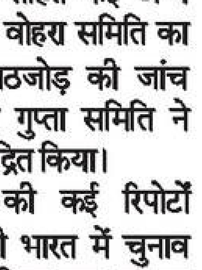

शहजाद पूनावाला
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता

भारत अब पश्चिम एशिया में अपनी मजबूत और लगातार मौजूदगी स्थापित कर रहा है, जिसका ताजा प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी की ओमान और जॉर्डन यात्रा है। 2018 में उनकी जॉर्डन और ओमान की यात्राएं भारत की पश्चिम एशिया नीति में एक बड़ा मोड़ थीं। इन्हीं से इस क्षेत्र के साथ गहरे और लगातार जुड़ाव की बढ़त मिली, जिसने भारत की विदेश नीति को नया आकार दिया। हालांकि भारत की पश्चिम एशिया पहुंच को कूटनीतिक सफलता के रूप में सराहा जाता है, लेकिन असली परीक्षा हमेशा गति को बनाए रखने, राज्य यात्राओं को स्थायी लाभों में बदलने, प्रवासी समुदाय का भरोसा जीतने और विश्वसनीयता निर्माण की रही है।

कई दशकों तक भारत के पश्चिम एशिया से संबंध मुख्य रूप से तेल आयात और प्रवासी भारतीयों की कमाई तक सीमित थे। इजराइल के साथ संबंध घरेलू राजनीति और फिलिस्तीन मुद्दे के कारण सावधानी से चलते थे, जबकि खाड़ी देशों से रिश्ते अधिकतर तेल आयात पर आधारित थे। प्रधानमंत्री स्तर की यात्राएं बहुत कम होती थीं। प्रधानमंत्री मोदी की लिंक वेस्ट नीति ने इस ढर्रे को तोड़ा और पश्चिम एशिया को भारत की रणनीतिक प्राथमिकता के केंद्र में ला दिया। ऐतिहासिक यात्राएं हुईं- 40 साल बाद सऊदी अरब, 34 साल बाद यूएई और 15 साल बाद ईरान। 2023 में भारत द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में यूएई, मिस्र और ओमान को आमंत्रित करना भी इस बात का संकेत था कि भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है।

पश्चिम एशिया संघर्षों और तनावों से घिरा हुआ है। इसके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक स्थिरता लाने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत ने किसी भी सहयोगी को अलग-थलग किए बिना क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियों के साथ साझेदारी बनाई है। 2018 में रामल्ला दौरे ने फिलिस्तीनी आकांक्षाओं के प्रति समर्थन दिखाया, वहीं इजराइल के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना इसका उदाहरण है। आतंकवाद खत्म करने की अपील और साथ ही गाजा शांति योजना का समर्थन- दोनों ने भारत की भू-राजनीतिक संतुलन क्षमता को मजबूत किया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-जीसीसी व्यापार 178.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत को मिलने वाले शीर्ष 10 प्रवासी धन भेजने वाले देशों में से पांच पश्चिम एशिया से हैं। यूएई के साथ सीईपीए और निवेश संधि बड़े व्यापारिक लक्ष्यों को दर्शाते हैं। यूएई अब भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, कतर आदि देशों ने ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़कर विविध क्षेत्रों में निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। भारत का यूपीआई अब ओमान, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब में स्वीकार किया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा को जलवायु कूटनीति से जोड़ते हुए भारत ने सऊदी अरब, ओमान और यूएई के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा साझेदारियां की हैं। आई2यू2 समूह (भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका) खाद्य सुरक्षा, जल तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहा है। कनेक्टिविटी बड़ा साधन बनकर उभरी है, जैसे इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर और ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास।

अबू धाबी में मंदिर, बहरीन-इजराइल के साथ एमओयू और तेल अवीव व खाड़ी देशों में योग दिवस में भागीदारी- ये सभी भारत की सांस्कृतिक पहुंच को दर्शाते हैं। भारतीय भोजन, सिनेमा, परंपराएं सॉफ्ट पावर के साधन बन चुके हैं। मोदी 1.0 ने 'लिंक वेस्ट' की शुरुआत की, मोदी 2.0 ने 'एक्ट वेस्ट' के जरिए इसे दिशा और गति दी और मोदी 3.0 इस पूरी प्रक्रिया को स्थायी रूप से मजबूत कर रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं। सहलेखिका डॉ. विजेता रत्तानी हैं)

बिजनेस ब्रीफ

एमएफ-ब्रोकरेज नियमों में बदलाव पर चर्चा आज

मुंबई | बाजार नियामक सेबी का बोर्ड बुधवार को म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकरेज नियमों में बड़े बदलावों पर चर्चा करेगा। इसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो की स्पष्ट परिभाषा तय करने का प्रस्ताव है। ब्रोकरेज चार्ज की सीमा में बदलाव का सुझाव है। बैठक में सेबी के वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक करने की सिफारिश की गई है।

एचडीएफसी बैंक इंडसइंड में लेगा 9.5% हिस्सेदारी

मुंबई | रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक और उसकी ग्रुप कंपनियों को इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। शर्त ये है कि एचडीएफसी बैंक को यह हिस्सेदारी एक साल में खरीदनी होगी। ऐसा नहीं होने पर अनुमति रद्द हो जाएगी। इंडसइंड बैंक हाल के महीनों में भारी घाटे और गवर्नेंस से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है।

दिसं. में फ्लैश पीएमआई 59 से नीचेः एचएसबीसी

मुंबई | दिसंबर में देश की आर्थिक रफ्तार थोड़ी कम हुई। एचएसबीसी का फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स मासिक आधार पर घटकर 58.9 पर आ गया, जो नवंबर में 59.7 पर था। यह फरवरी के बाद ग्रोथ की सबसे धीमी रफ्तार है। यह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की संयुक्त ग्रोथ को दिखाता है। इसका 50 से ऊपर होना विस्तार दर्शाता है।

नवंबर में भारत से रिकॉर्ड आईफोन का निर्यात

नई दिल्ली | एपल ने नवंबर में भारत से 18,200 करोड़ रुपए मूल्य के आईफोन निर्यात का नया रिकॉर्ड बनाया। यह अमेरिकी कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में एक महीने में किया गया अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात है। अप्रैल-नवंबर के बीच कुल आईफोन निर्यात 1.27 लाख करोड़ रुपए का हो गया।

रिलायंसः 75 साल पुराने फूड ब्रांड की हुई वापसी

मुंबई | रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी कंपनी आरसीपीएल ने 75 साल पुराने फूड ब्रांड एसआईएल को नए स्वाद और नए अंदाज में बाजार में उतारा है। कंपनी ने इसे अपना फ्लैगशिप फूड ब्रांड बनाया है। एसआईएल के तहत नूडल्स, केचप, जैम और सॉस जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। नूडल्स की कीमत 5 रुपए से शुरू होगी।

हम बेफिक्र • भारत में कीमतें बढ़ने की आशंका नहीं, क्रूड 3 माह में 14% तक सस्ते, महंगाई भी 1% से कम

रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 91 से नीचे, पर हमारी करेंसी डॉलर से 3% कम टूटी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

रुपए ने मंगलवार को 36 पैसे गिरकर 91.14 का ऑल टाइम लो बनाया। चौथे दिन लगातार यह सबसे निचला स्तर है। बाद में डॉलर के मुकाबले 90.93 के निचले स्तर पर बंद हुआ। 2025 में अब तक भारतीय करेंसी में 6.3% गिरावट आ चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर इंडेक्स भी 9.5% टूट चुका है। यानी हमारी करेंसी डॉलर से करीब 3% कम टूटी है। करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, रुपया और डॉलर में एक साथ गिरावट कम ही देखी जाती है। लेकिन इस साल इसका कारण ट्रेड वॉर की मजबूरियां और कुछ घरेलू वजहें हैं। भारत में रिजर्व बैंक रुपए को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, जितना आम तौर पर देखा जाता है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अर्थव्यवस्था में नकदी का स्तर बढ़ाने की मुहिम पर चल रहे हैं, जिससे डॉलर पर दबाव बन रहा है। बहरहाल, भारत में आम आदमी के लिए कमजोर रुपए का मतलब आम तौर पर ये होता है कि पेट्रोलियम, खाने के तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ऐसे सामान महंगे होंगे, जिन्हें दूसरे देशों से आयात किया जाता है। अच्छी बात ये है कि बीते तीन महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 13-14% घट चुके हैं। इसके मुकाबले रुपए की कमजोरी मामूली है। यानी रुपया कमजोर होने से पेट्रोलियम उत्पाद महंगे नहीं होंगे।

रणनीतिः करेंसी मार्केट पर बड़ा दांव

ये खासः इस साल उन्हीं देशों की करेंसी टूटी, जो अमेरिकी ट्रेड वार के केंद्र में हैं

करेंसी	कमजोरी/मजबूती
डॉलर-अमेरिका	-9.5%
रुपया-भारत	-6.3%
पेसो-मैक्सिको	-5.1%
येन-जापान	-4.8%
डॉलर-कनाडा	-3.2%
युआन-चीन	-0.25%
यूरो-यूरोपीय संघ	+7.5%
फ्रैंक-स्विट्जरलैंड	+7.2%
पाउंड-ब्रिटेन	+4.7%
डॉलर-ऑस्ट्रेलिया	+5.1%

(कमजोरी, मजबूती 31 दिसंबर-24 से 16 दिसंबर-25 के बीच)

रिटेल निवेशक दूर, सेंसेक्स 533 अंक टूटा

सेंसेक्स 533.5 अंक गिरकर 84,680 और निफ्टी 167 अंकों की गिरावट के साथ 25,860 पर बंद हुआ। फाइनेंशियल और मेटल शेयरों में बिकवाली ने बाजार को नीचे खींचा। जियोजित इंवेस्टमेंट्स में रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'मौजूदा माहौल में रिटेल निवेशक बाजार से दूर हैं। इसके चलते रुझान कमजोर नजर आ रहा है। अभी घरेलू बाजार को म्यूचुअल फंड्स का सपोर्ट है।'

कमजोर करेंसी ट्रेड वॉर का नया हथियार, कम महंगाई दर से भारत मजबूत स्थिति में

भास्कर एक्सपर्ट

अनिंद्य बनर्जी
करेंसी-कमोडिटी रिसर्च हेड, कोटक सिक्युरिटीज

▪ **डॉलर, रुपया, दोनों कमजोर होने का क्या मतलब है?**
भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ तेज है, आर्थिक सुधार भी जारी हैं और महंगाई कम है। दूसरी तरफ डॉलर खुद कमजोर हो रहा है। ऐसे हालात में रुपए में गिरावट कम ही देखने को मिलती है। पिछली बार 2013 में ऐसा हुआ था। ये एक नए आर्थिक समीकरण का नतीजा है, जहां सभी बड़े देश अपने-अपने निर्यातकों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

▪ **रुपया कमजोर होने से रिजर्व बैंक क्यों परेशान नहीं दिख रहा?**
आरबीआई रुपए में गिरावट रोकने का प्रयास कर रहा है और विफल हो रहा है, ऐसा नहीं है। दरअसल रिजर्व बैंक रुपए को कमजोर होने दे रहा है क्योंकि इससे निर्यातकों को फायदा होगा। जिस देश की करेंसी कमजोर होती है वहां के निर्यातकों की आय बढ़ जाती है। भारत के मामले में डॉलर में निर्यातकों की आय एक साल पहले के मुकाबले अब 6% ज्यादा होगी।

▪ **गिरते रुपए से महंगाई बढ़ेगी?**
यही तो रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ी सहूलियत है। रिटेल महंगाई कुछ माह से 1% से भी कम है। कमजोर रुपए के चलते ये 4% तक पहुंचे तो भी रिजर्व बैंक को दिक्कत नहीं आएगी।

▪ **डॉलर क्यों कमजोर हो रहा?**
ट्रम्प की वापसी से वहां राजनीतिक, आर्थिक और नीतिगत रिस्क बढ़े हैं। ये लगभग वैसा ही है, जैसा 2013 में भारत की स्थिति थी। ऐसे में ट्रम्प डॉलर की प्रिंटिंग बढ़ाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा करने से डॉलर कमजोर हो रहा है, लेकिन इससे ट्रम्प को चिंता नहीं है। उन्हें लगता है कि इससे उनके निर्यातकों को फायदा होगा।

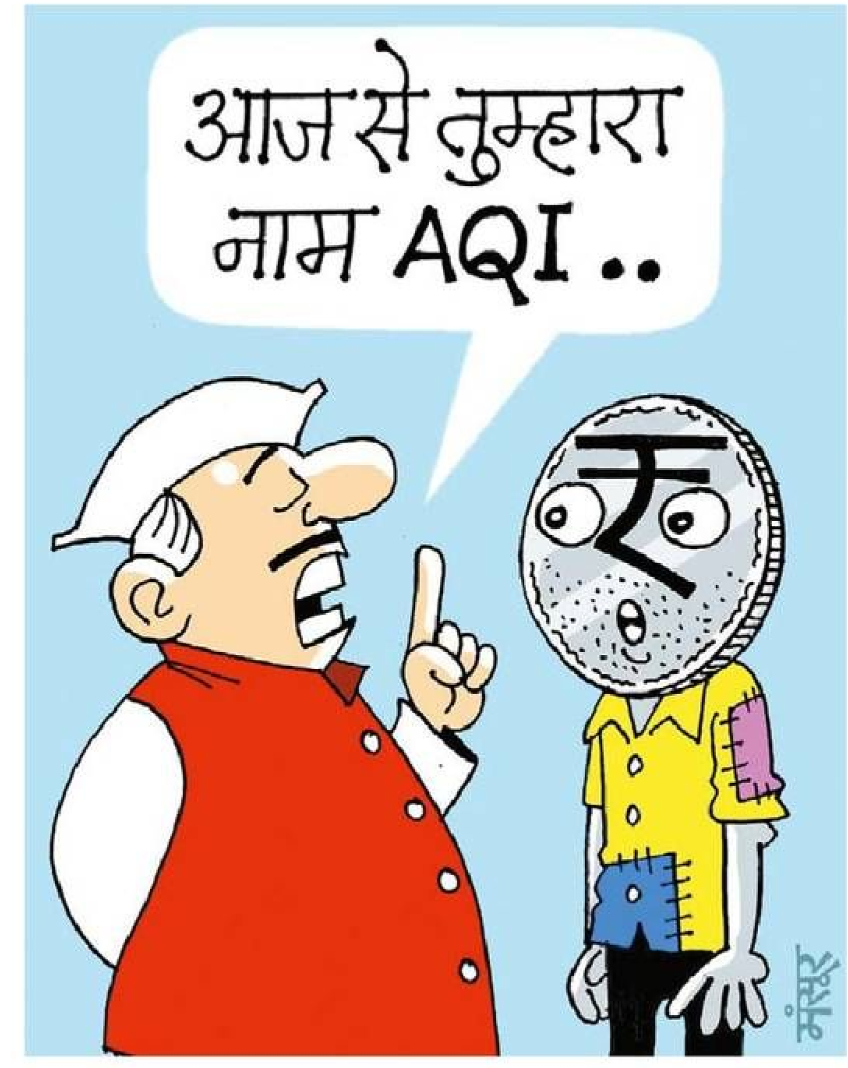

खरा सोना • ₹4,627 प्रति यूनिट खरीद, प्रीमैच्योर रिडम्पशन दाम ₹13,152

गोल्ड बॉन्ड का रिटर्न 184%, पांच साल में 5 लाख का निवेश 14 लाख रुपए हुआ

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

आरबीआई द्वारा जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 सीरीज-III ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 16 जून 2020 को जारी इस बॉन्ड की कीमत ऑफलाइन निवेशकों के लिए 4,677 रुपए और ऑनलाइन के लिए 4,627 रुपए प्रति ग्राम थी। अब 16 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने इसकी प्रीमैच्योर रिडम्पशन कीमत 13,152 रुपए प्रति यूनिट तय की है। यानी जिसने मूल कीमत पर 'एसजीबी 2020-21 सीरीज-III' में 5 लाख रुपए का निवेश किया होगा वह अब करीब 14.2 लाख रुपए हो गया है। इसमें करीब 184% कैपिटल गेन (14.2 लाख) के अलावा सालाना 2.5% ब्याज भी शामिल है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की यूनिट की कीमत और रिडम्पशन प्राइस, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के तीन दिनों के औसत बंद भाव के आधार पर तय होती है।

सुविधाः ये बॉन्ड गिरवी रखकर 75% वैल्यू तक लोन भी ले सकते हैं

- 2.5% सालाना ब्याज, हर 6 महीने में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है।
- एसजीबी को पूरे 8 साल होल्ड करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।
- ब्याज पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स, 3 साल से पहले बेचो तो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगेगा।
- इंडेक्सेशन बेनिफिट भी लंबी अवधि के ट्रांसफर पर मिलता है।
- बॉन्ड स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होते हैं और शेयर की तरह डीमैट खाते के जरिये खरीदे-बेचे जा सकते हैं।
- सेकेंडरी मार्केट में इनकी कीमत सोने की मौजूदा कीमत और डिमांड-सप्लाई के आधार पर तय होती है।
- एसजीबी को गिरवी रखकर इसकी 75 प्रतिशत वैल्यू तक लोन ले सकते हैं।

एसजीबी 2017-18 सीरीज-XI ने दिया था सर्वाधिक 341% रिटर्न

एसजीबी 2017-18 सीरीज-XI को बिना छूट के 2,952 रुपए/ग्राम पर जारी किया गया था। ऑनलाइन कीमत 2,902 रुपए थी। रिडम्प्शन की प्रीमैच्योर तारीख 11 दिसंबर, 2025 को एसजीबी की प्रति यूनिट 12,801 रुपए कीमत निर्धारित थी। इस हिसाब से इसने अभी तक का सबसे ज्यादा 341% रिटर्न दिया है। 2.5% ब्याज अलग है।

2025 के बजट में सरकार ने बंद कर दी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज

नवंबर 2015 में शुरू हुई एसजीबी स्कीम की कुल 67 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। आखिरी सीरीज फरवरी 2023 में जारी की गई थी, लेकिन सरकार ने बजट 2025 में इस योजना को बंद करने की घोषणा कर दी। इसे बंद करने का मुख्य कारण ये था कि सोना महंगा होने की वजह से सरकार को एसजीबी पर बहुत ज्यादा रिटर्न देना पड़ रहा था।

सुविधा • परिवारों को लाभ

भीम एपः लॉन्च हुआ यूपीआई सर्कल

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

भीम पेमेंट्स एप ने यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन नाम की एक नई सुविधा शुरू की है। इसे परिवारों और छोटे बिजनेस के लिए साझा डिजिटल भुगतान आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्राथमिक उपयोगकर्ता विश्वसनीय संपर्कों को अपने बैंक खाते से यूपीआई भुगतान के लिए अधिकृत कर सकता है। इसकी एक मासिक खर्च की सीमा भी तय की जा सकती है। एनबीएसएल की सीईओ, ललिता नटराज ने बताया, 'यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन के साथ, प्राथमिक यूजर द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति (सेकंडरी यूजर) सीधे प्राथमिक यूजर के बैंक खाते से यूपीआई पेमेंट कर सकता है। प्राथमिक यूजर 15,000 रुपए मासिक तक खर्च की सीमा तय कर सकता है। अधिकतम 5 वर्षों की वैधता तय की जा सकती है। मासिक खर्च सीमा खत्म होने के बाद, सेकंडरी यूजर यूपीआई सर्कल फीचर का उपयोग आंशिक डेलीगेशन में जारी रख सकता है।'

महंगाई • ऊंची कीमतों के लिए तैयार रहें

अप्रैल-जून 2026 में 20% तक महंगे हो सकते हैं मोबाइल प्लान

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

दूरसंचार कंपनियां अप्रैल-जून 2026 के बीच एक बार फिर 4जी और 5जी प्लान की कीमतों में 16-20% बढ़ोतरी कर सकती हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, सस्ते प्लान हटाने और स्ट्रीमिंग सेवाओं को केवल प्रीमियम प्लान के साथ जोड़ने जैसे हालिया कदम संकेत देते हैं कि कंपनियां ग्राहकों को ऊंची कीमतों के लिए तैयार कर रही हैं।

इससे पहले मॉर्गन स्टेनली ने अनुमान लगाया था कि देश की टेलीकॉम कंपनियां अपने-अपने टैरिफ प्लान में 2026 के मध्य तक 15% बढ़ोतरी कर सकती हैं। मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषक अब 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड, दोनों तरह के 4G/5G प्लान में 16-20% टैरिफ बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। रिलायंस जियो को छोड़कर, अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड प्लान हाल ही में महंगे किए हैं।

दूरसंचार कंपनियों ने बीते साल बढ़ाए थे 15% दाम

पिछले आठ वर्षों में यह चौथी बड़ी मूल्य वृद्धि होगी। देश की टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ में 2024 के दौरान 15%, 2021 में 20% और 2019 में 30% बढ़ोतरी की थी। अगले साल कंपनियां अपनी-अपनी कमाई की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्लान महंगा कर सकती हैं। सितंबर तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों की आय बढ़ने की औसत घटकर 10% के आसपास आ गई, जो कि इससे पिछली चार तिमाहियों से 14-16% के आसपास थी।

वोडाफोन आइडिया ने 1,999 रुपए के सालाना प्रीपेड प्लान की कीमत 12% बढ़ाई। 509 रुपए के 84 दिन के प्लान की कीमत भी 7% बढ़ाई है। एयरटेल ने एंट्री-लेवल केवल-वॉइस 189 रुपए के प्लान की कीमत 10 रुपए बढ़ा दी। बीएसएनएल ने टैरिफ बदले बिना कुछ निचले-स्तर के प्लान की अवधि घटा दी है।

वाहन • कंपनियों की नई रणनीति

2026 में नई कारों पर कम, फेसलिफ्ट पर ज्यादा ध्यान

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

नए साल की शुरुआत में भारत के कार मार्केट में कई कंपनियां अपनी पुरानी गाड़ियों के फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। ऑटो कंपनियां नए मॉडल की बजाय अपग्रेड और मिड-साइकिल रिफ्रेश पर ज्यादा जोर दे रही हैं। उद्योग के जानकारों का मानना है कि 2026 में उत्पाद विकास में तेजी आने, ग्राहकों की उम्मीदों में बदलाव के साथ ही सख्त होते नियमों की वजह से यह परिवर्तन आएगा।

प्राइमस पार्टनर्स के सलाहकार अनुराग सिंह कहते हैं, 'वाहन उद्योग में उत्पाद विकास बहुत तेजी से हो रहा है। उन्नत डिजाइन सॉफ्टवेयर, विक्रेताओं के साथ करीबी सहयोग और उत्पादन संयंत्रों के डिजिटलीकरण और रोबोटीकरण के चलते किसी उत्पाद के अपग्रेड में कई वर्षों के बजाय अब हफ्तों का समय लग रहा है। विश्लेषकों का भी मानना है कि कनेक्टेड तकनीक, इन्फोटेनमेंट, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडास), कई ड्राइव मोड्स और बेहतर केबिन कम्फर्ट जैसे ग्राहक अनुभव फीचर अब काफी सस्ते हो गए हैं और तेजी से विकसित हो रहे हैं।

महिंद्रा, टाटा, मारुति, ह्युंडई के फेसलिफ्ट कतार में

अगले साल कतार में लगे प्रमुख फेसलिफ्ट मॉडलों में महिंद्रा एक्सयूवी700, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा पंच, मारुति ब्रेजा, ह्युंडई वर्ना, हुंडई एक्सटेरा, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन और किआ सेल्टॉस शामिल हैं। ये अपडेट निर्माताओं को ग्राहकों की दिलचस्पी बनाए रखने और पूरी तरह नए उत्पाद आने के बीच के अंतराल में अपनी उत्पादों की सूची को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं।

जानकारों का मानना है कि यह बदलाव आंशिक रूप से रणनीतिक है और आंशिक रूप से नियामक से जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2027 से लागू होने वाले नए कैफे 3 ईंधन दक्षता मानकों के साथ कंपनियां पूरी तरह नए मॉडलों पर काम करने के बजाय दक्षता और उत्सर्जन बेहतर करने को प्राथमिकता दे रही हैं।

अक्टूबर-नवंबर में बिक्री के आंकड़े अच्छे

जीएसटी 31% से 40% होने पर भी प्रीमियम दोपहिया ज्यादा बिके

अंजलि सिंह | नई दिल्ली

देश में 350 सीसी से ज्यादा दमदार इंजन वाली प्रीमियम मोटरसाइकिलों की बिक्री जीएसटी में बढ़ोतरी के बावजूद बढ़ी है। इस साल 22 सितंबर से इस श्रेणी के दोपहिया पर जीएसटी 31% से बढ़ाकर 40% कर दिया। इसके चलते ये महंगी हो गईं। फिर भी अक्टूबर-नवंबर में इनकी बिक्री 4% बढ़कर 29,951 मोटरसाइकिलों तक पहुंच गई।

अक्टूबर में प्रीमियम दोपहिया की बिक्री 7.2% बढ़कर 19,555 हो गई, जबकि नवंबर में 1.4% घटकर 10,396 रह गई। अक्टूबर की बढ़ोतरी मोटे तौर पर 350-500 सीसी श्रेणी में बढ़ी। इनमें बजाज डोमिनार, रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450, कावासाकी एलिमिनेटर और होंडा मावरिक 440 जैसे मॉडल शामिल हैं। नवंबर में 500-800 सीसी और 800-1600 सीसी इंजन वाली मोटरसाइकिलों की बिक्री में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई।

प्रीमियम मोटरसाइकिलों के ग्राहक दाम नहीं देखते

प्राइमस पार्टनर्स के अनुराग सिंह के मुताबिक, प्रीमियम श्रेणी की मोटरसाइकिलों के खरीदार कीमतों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, इसलिए मांग में गिरावट नहीं आई। हालांकि 350 और 450 सीसी मॉडल्स के बीच दाम का अंतर बिना बड़े फर्क के जायज ठहराना मुश्किल हो रहा है।

ऑडिटर ने उठाए थे सवाल

टाटा ट्रस्ट्स के सिंह को 10 साल में मिले 20 करोड़

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

टाटा ट्रस्ट्स ने अपने ट्रस्टी विजय सिंह के वेतन-भत्तों पर ऑडिटर की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद कानूनी राय ली है। विजय सिंह ने 2013-14 से 2024-25 तक टाटा सन्स और ग्रुप की एयरोस्पेस-डिफेंस कंपनियों से 20.13 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसमें टाटा सन्स से मिले 15.89 करोड़ (ज्यादातर कमिशन) शामिल हैं। हाल के वर्षों में उन्हें सालाना 2.8-3.2 करोड़ रुपए मिले हैं। ऑडिटर ने मई में सिंह को किए गए भुगतान पर कुछ सवाल उठाए थे। इस पर ट्रस्ट्स ने वरिष्ठ वकील पर्सी पारदीवाला की राय ली है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस राय में सिंह के कमीशन और अन्य भुगतान को पूरी तरह कानूनी बताया गया। यह ट्रस्ट के नियमों, नॉमिनी डायरेक्टर की जिम्मेदारियों और लागू कानूनों का उल्लंघन नहीं है।

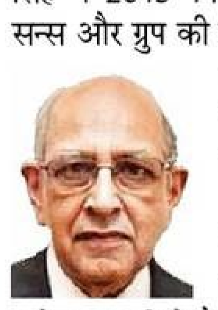

एचडीएफसी, अदाणी टॉप-5 में

एलआईसी का टाटा ग्रुप में ₹88,404 करोड़ निवेश

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने सबसे ज्यादा निवेश टाटा ग्रुप में किया है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि एलआईसी का टाटा ग्रुप में 88,404 करोड़ रुपए निवेश है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक में 80,843 करोड़ और रिलायंस ग्रुप में 60,065 करोड़ रुपए का निवेश है। जवाब के मुताबिक, एलआईसी के पोर्टफोलियो में टॉप-5 में अदाणी ग्रुप चौथे स्थान पर है, जिसमें कंपनी ने 47,634 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। पांचवें नंबर पर एसबीआई है, जिसमें एलआईसी ने 46,622 करोड़ रुपए लगाए हैं। टॉप-5 कॉरपोरेट ग्रुप्स में एलआईसी का कुल निवेश 3.23 लाख करोड़ रुपए है। एलआईसी ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 35 घरेलू कंपनियों या ग्रुप्स में निवेश किया है, जो कुल 7.87 लाख करोड़ रुपए बनता है। इनमें एलएंडटी, आईडीबीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं।

34% हिस्सेदारी बनी रहेगी

ओला के भाविश ने शेयर बेचकर कर्ज चुकाया

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के को-फाउंडर भाविश अग्रवाल ने मंगलवार को 2.6 करोड़ शेयर या 0.6% हिस्सेदारी बेच दी। यह सौदा 34.99 रुपए प्रति शेयर की औसत कीमत पर लगभग 92 करोड़ रुपए में हुआ। इस बिक्री का उद्देश्य प्रमोटर-स्तर का 260 करोड़ रुपए का कर्ज पूरी तरह चुकाना था। इस कदम से प्रमोटर-स्तर पर गिरवी रखे 3.93% शेयर मुक्त हो जाएंगे। साथ ही भाविश अग्रवाल भी प्रमोटर स्तर पर कर्ज-मुक्त हो जाएंगे। सितंबर 2025 तक प्रमोटर्स और प्रमोटर समूह के पास ओला इलेक्ट्रिक में 36.78% हिस्सेदारी थी। शेयर बिक्री के बाद प्रमोटर ग्रुप अब भी ओला इलेक्ट्रिक में करीब 34% हिस्सेदारी बनाए रखेगा। कंपनी का कहना है कि इससे प्रमोटर कंट्रोल या लंबी अवधि की प्रतिबद्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह लोन एआई स्टार्टअप 'कृत्रिम' को फंड देने के लिए लिया गया था। कृत्रिम क्लाउड इंफ्रा प्लेयर के रूप में उभरा है।

बिजनेस, एंकर इस साल कमाई की रफ्तार के मामले में लक्ष्मी मित्तल दूसरे, अदाणी तीसरे नंबर पर

मुकेश अंबानी की दौलत 2025 में 1.4 लाख करोड़ रुपए बढ़ी, 100 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति बनाने वाले दुनिया में एकमात्र भारतीय

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इस साल संपत्ति (नेटवर्थ) बढ़ने के मामले में भारत में सबसे अव्वल रहे। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति इस साल (16 दिसंबर तक) 15.3 अरब डॉलर (करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए) बढ़कर 106 अरब डॉलर (करीब 9.64 लाख करोड़ रुपए) हो गई। मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग की वैश्विक सूची में 18 वें स्थान पर हैं। वे इस साल भारत के इकलौते सेंटिबिलियनेयर यानी 100 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति वाले व्यक्ति हैं। अंबानी की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इस साल अब तक बीएसई सेंसेक्स पर छठा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर बनकर उभरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने इस साल 26% से ज्यादा रिटर्न दिया है। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदाणी की संपत्ति इस साल करीब 60 हजार करोड़ रुपए बढ़ी है। हालांकि लग्जमबर्ग मुख्यालय वाली आर्सेलरमित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल संपत्ति में 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ भारतीय मूल के कारोबारियों में दूसरे नंबर पर हैं। ब्रिटेन के निवासी रहे लक्ष्मी मित्तल ने टैक्स नियमों की वजह से ब्रिटेन छोड़ दिया है और अब वह स्विट्जरलैंड के टैक्स निवासी हैं और दुबई में समय बिता रहे हैं।

60 हजार करोड़ बढ़ी गौतम अदाणी की संपत्ति

नाम	विश्व रैंक	संपत्ति	वृद्धि
मुकेश अंबानी	16	9.64	1.4
गौतम अदाणी	20	7.75	0.6
लक्ष्मी मित्तल	71	2.85	1.0
सुनील मित्तल	76	2.63	0.5
कुमार बिड़ला	116	2.05	0.3
राधाकृष्ण दमानी	162	1.51	0.2

44 हजार करोड़ घटी शिव नाडार की संपत्ति

नाम	विश्व रैंक	संपत्ति	गिरावट
शिव नाडार	54	3.47	0.44
शापूर मिस्त्री	64	3.15	0.36
सावित्री जिंदल	72	2.82	0.10
अजीम प्रेमजी	85	2.45	0.36
दिलीप सांघवी	93	2.39	0.28

(आंकड़े लाख करोड़ रु. में, जनवरी से 16 दिसंबर 25 तक के, स्रोतः ब्लूमबर्ग)

- भारत के शीर्ष 10 अमीरों में से 5 की संपत्ति में इस साल इजाफा हुआ है जबकि 5 लोगों की संपत्ति में इस साल गिरावट आई है।
- देश के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति शिव नाडार की संपत्ति इस साल करीब 44 हजार करोड़ रुपए घट गई।
- शापूर मिस्त्री की संपत्ति 36 हजार करोड़ और सावित्री जिंदल की 10 हजार करोड़ रुपए घटी है।
- अजीम प्रेमजी की संपत्ति भी 36 हजार करोड़ रुपए घटी है। दिलीप सांघवी की संपत्ति करीब 28 हजार करोड़ रुपए घटी है।

ट्रम्प पॉलिसी का असर • हाइब्रिड, पेट्रोल वाहनों पर बढ़ेगा फोकस

फोर्ड बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बनाना बंद करेगी, इससे 1.8 लाख करोड़ रुपए का होगा नुकसान

भास्कर न्यूज़ | न्यूयॉर्क

अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड ने ऐलान किया है कि वह बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की योजनाओं से पीछे हट रही है। कंपनी ने इसकी वजह सुस्त मांग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हाल ही में किए गए नियमों में बदलाव को बताया है। कंपनी अब हाइब्रिड और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के उत्पादन और छोटे, अधिक किफायती ईवी मॉडलों के उत्पादन में निवेश करेगी। फोर्ड ने कहा कि इस रणनीतिक बदलाव की वजह से उसके मुनाफे में करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी। इससे पहले जनरल मोटर्स ने भी अपने ईवी प्लान में कटौती की थी और कहा था कि घटती मांग के बीच उसे 14,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

फोर्ड के सीईओ जिम फार्ले ने एक बयान में कहा, 'यह ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया बदलाव है, जिसका उद्देश्य फोर्ड को अधिक मजबूत, अधिक लचीला और अधिक लाभदायक बनाना है। उम्मीद से कम मांग, ऊंची लागत और नियामक परिवर्तनों के कारण बड़े आकार के ईवी मॉडल बनाना तर्कसंगत नहीं है।' इधर भारत में मंगलवार को लोकसभा में भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि सरकार पूरे देश में ईवी को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है।

भारत में अमेरिका जैसी स्थिति नहींः चेयरमैन, फाडा रिसर्च

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) एकेडमी एंड रिसर्च के चेयरमैन मनीष राज सिंघानिया के मुताबिक भारत में अमेरिका जैसी स्थिति नहीं है। फिलहाल फोर्ड ने भारत लौटने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन अगर वह यहां लौटती भी है तो भारत में उसे अमेरिका जैसी दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका में वैसे भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कम है। जबकि भारत में सरकारी प्रोत्साहन और अन्य वजहों से ईवी अपनाने में तेजी आ रही है।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

अहमदची कृती शांततेच्या दृष्टीने सुचिन्ह

‘**अक्रमने मारले,** अहमदने वाचवले!’ हा अग्रलेख (१६ डिसेंबर) वाचला. जगात फोफावलेल्या दहशतवादाला सहिष्णुतावाद हेच उत्तर आहे. अशांतता माजवून शांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारे अक्रमसारखे दहशतवादी इस्लामचे बंदे असूच शकत नाहीत; जिवाची पर्वा न करता दहशतवाद्यावर झडप घालून त्याला जेरबंद करणारा अहमद हाच खरा इस्लामचा बंदा. इस्लाममधील सहिष्णुतावादी विचारधारेपेक्षा कट्टरतावादी वरचढ झाले आहेत. कट्टरतेतून कट्टरताच जन्माला येते. तिला तोंड देण्यासाठी इतर धर्मांमध्येही कट्टरतावादी विचार डोके वर काढत असल्याचे चित्र जगभर दिसत आहे. त्यामुळेच माणूस किंवा राष्ट्र प्रथम ऐवजी धर्म प्रथम, अशी राजकारणाची धारणा होत चालली आहे. धार्मिक कट्टरतावादातून निर्माण झालेल्या अशांततेचा फायदा नेतान्याहूंसारखे महत्त्वाकांक्षी नेते आपली सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी घेताना दिसतात.

सर्व मुस्लीम अतिरेकी नसतात, पण सर्व अतिरेकी मुस्लीमच का असतात; या नॅरेटिव्हला अहमदने छेद दिला आहे. दहशतवाद्यांचा कारखाना असलेल्या पाकिस्तानला भारतातील संवेदनशील माहिती पुरवणारे शर्मा, वर्मा, कुरुलकर यांसारखे गैरइस्लामी देशद्रोही अनेक सापडले आहेत. कट्टरतेला राजनैतिक आणि आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याने एक कट्टरतावादी समांतर व्यवस्था तयार झालेली आहे. हे दहशतवादी आपल्या धर्माच्या लोकांनाही ठार मारताना दिसतात. त्यामुळे अक्रम या अतिरेक्यावर झडप घालणाऱ्या अहमदच्या जिवाला धोका वाढला आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकार त्याच्या शौर्याचा उचित सन्मान करून त्याला योग्य ते संरक्षण पुरवेलच, पण आता अहमदसारखे शांतताप्रेमी, सहिष्णुतावादी लोक दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी धैर्याने पुढे येत आहेत; हे कट्टरतावादाचा अंत होऊन जगात शांती निर्माण होण्याच्या दृष्टीने सुचिन्ह म्हणावे लागेल.

■ **किशोर थोरात,** नाशिक

नेतान्याहूंचा ‘निवडक’ शोक

‘**अक्रमने मारले,** अहमदने वाचवले!’ हा अग्रलेख (१६ डिसेंबर) वाचला. नेतान्याहू यांचा आक्रोश केवळ हास्यास्पदच नव्हे, तर ठळक नैतिक दुटप्पीपणाचे दर्शन घडवणारा वाटतो. त्या हत्याकांडावर भूमिका घेणे हा ऑस्ट्रेलियाचा सार्वभौम अधिकार आहे. तो देश आपले अंतर्गत प्रश्न न्याय्य आणि संवेदनशील पद्धतीने हाताळण्यास समर्थ आहे. जर नेतान्याहू यहुदी समुदायाबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतके संवेदनशील असतील, तर जगभरातील इस्लामी समाजाने पॅलेस्टाइनच्या बाजूने उभे राहणे हेही तितकेच न्याय्य ठरते!

आजही पॅलेस्टाइनमध्ये स्थैर्य नाही. ऑक्टोबरमध्ये युद्धविरामाचे अधिकृत संकेत मिळूनही प्रत्यक्षात संघर्ष थांबलेला नाही. हिंसा सुरूच आहे. नुकताच हमासचा एक नेता ठार करण्यात आला. इस्रायलने गाझा आणि वेस्ट बँक हे दोन्ही प्रदेश उद्ध्वस्त केले आहेत. या विध्वंसातून उभे राहण्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. आज पॅलेस्टाइनला जागतिक स्तरावरून मदतीची आवश्यकता असताना, नेतान्याहूंच्या यहुदी ‘संवेदनशीलते’मागे असुरी वांशिक अस्मिता ठळकपणे दिसते. निवडक दुःखावर शोक व्यक्त करणे आणि इतरांच्या वेदनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे, हे मुळात कुठल्याच नेतृत्वाला शोभत नाही, एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानास तर नाहीच!

■ **रोहिणी गुट्टे,** धुळे

संसदेच्या वेळेचा अपव्यय सरकारमुळेच

अलीकडे सरकार फक्त नेहरू-गांधी आणि इतिहासातील गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी सभागृहाचा वेळ वाया घालवत आहे. मागील आठवड्यात वंदे मातरमवर चर्चा घडवून सभागृहांचा पूर्ण दिवस वाया गेला. पूर्वीच्या सरकारने केलेली कामे, निर्माण केलेल्या संस्था आणि लोकोपयोगी योजनांची नावे बदलणे हेच विद्यमान सरकारचे विकसित भारताचे स्वप्न दिसते. हे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी आणि सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी २०४७ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असे या सरकारचे म्हणणे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भारतात लोकांना रोजगार मिळत आहे. मनरेगा ग्रामीण भारतात रोजगार देणारी योजना म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यात सरकारने काही सुधारणा केल्या असता तर बरे झाले असते. त्याऐवजी नाव बदलून योजनेचे स्वरूप केंद्र सरकारच्या हिताचे कसे ठरेल, या दृष्टीने प्रयत्न केल्याचे दिसते. असे उद्योग करण्यापेक्षा महागाई, शेती, आरोग्य, शिक्षण, सरकारी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे यादृष्टीने अधिवेशनात चर्चा होणे गरजेचे होते. रुपयाच्या घसरणीवरसुद्धा चर्चा आवश्यक आहे, मात्र सभागृहाचा वेळ बिनमहत्त्वाच्या गोष्टींत वाया दवडण्यात येत आहे.

■ **चंद्रसेन काळखैर,** कल्याण

मुलांमधील वाढती हिंसा चिंताजनक

‘**शिक्षक शिकवत** असताना विद्यार्थ्याची हत्या’ ही बातमी (लोकसत्ता- १६ डिसेंबर) वाचून मन सुन्न झाले. मध्यंतरी छत्रपती संभाजीनगरातील खुलताबाद प्राथमिक शाळेत पाचवीच्या मुलांनी अशीच झुंडीने एका मुलाची दगडाने ठेचून हत्या केली, एका प्राध्यापकाचा त्याच्या मुलानेच खून केला. हे सर्व प्रकार चिंताजनक असून विचार करण्यास भाग पाडणारे आहेत. आजची मुले आक्रमक, हिंसक होण्यामागे चित्रपटांतील वाढती हिंसा (ॲनिमल, धुरंधरसारखे चित्रपट), घरातील हिंसा व सामाजिक बिघडलेले सौहार्द हीच कारणे आहेत. समाजमाध्यमांवर, फ्री फायर, पब्जीसारख्या गेम्समधून हिंसाचाराची बीजे रोवली जात आहेत. हिंसा, रक्तपात बघून तोच मुलांच्या कृतीत उतरत आहे.

■ **कुमार बिरदवडे,** छत्रपती संभाजीनगर

टीका होईल म्हणून पुरस्कार नाकारला?

‘**शशी थरूर** कोणाला फायद्याचे?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (१५ डिसेंबर) वाचला. काँग्रेस आणि थरूर संबंध लक्षात घेता त्यांना सावरकर यांच्या नावाने पुरस्कार जाहीर झाला यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. यासाठी थरूर यांनी संमती दिली असण्याची जास्त शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु त्याचे विपरीत परिणाम होऊन आपले राजकीय अस्तित्वच धोक्यात येईल, याची जाणीव होताच आपण पुरस्कार स्वीकारणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मागे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मातोश्रींनाही संघाने एका कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले होते. त्यावर समाजातील सर्व स्तरांतून टीका होऊ लागताच त्यांनीही आपण असे काही आमंत्रण स्वीकारलेच नाही, असे जाहीर केले होते, याची आठवण यानिमित्ताने झाली.

■ **प्रा. एम. ए. पवार,** कल्याण

रेवड्याही नीट वाटता येत नाहीत

‘**कामगार कल्याण** योजनेत बनावट लाभार्थी’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ डिसेंबर) वाचली. राज्य शासनाच्या इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाद्वारे सुरक्षा किट आणि माध्यान्ह भोजनेचा लाभ बनावट लाभार्थ्यांनी घेतल्याची कबुली कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत दिली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अपात्र बहिणींनी मोठ्या प्रमाणात घेतला. काही पुरुष मंडळींनीसुद्धा या योजनेतील निधी लांबवल्याचा अनुभव महायुतीच्या सरकारच्या गाठीशी असतानाही सरकारच्या कामगार कल्याण योजनेत बनावट लाभार्थ्यांनी सरकारची फसवणूक केलीच.

महाराष्ट्रात बहुमताने निवडून आलेल्या भाजपाच्या सरकारला अनुदानाच्या रेवड्या वाटण्याची प्रक्रिया नियोजनबद्ध रीतीने हाताळता येत नाही. सरकारला गोरगरीब रयतेची खरोखरच काळजी वाटत असेल, तर महिलांसाठी निधीवाटपाचे काम महिलांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या सेवाभावी संस्थांकडे सोपविण्यात आले पाहिजे. तसेच कामगारांना मध्यान्ह भोजन, सुरक्षा किट वाटण्याच्या कामासाठी हमाल पंचायतसारख्या कार्यक्षम संस्थेची मदत घेतली पाहिजे. सरकारच्या तिजोरीतून गोरगरिबांना निधीवाटप करताना नियोजन आणि शिस्त पाळणे महत्त्वाचे आहे. नाहीतर करदात्यांच्या पैशांची नासाडी होत राहील.

■ **प्रशांत कुळकर्णी,** कांदिवली (मुंबई)

कांटचं नीतिशास्त्र

नैतिक व्यवहार कुठल्यातरी नीतिकल्पनांचं नव्हे तर ‘स्वतःतल्या विवेकी आदेशाचं पालन’ करणारा हवा- कारण मनुष्याला कांट स्वायत्त ज्ञाता आणि कर्ता मानतो...

तत्त्व-विवेक

शरद बाविस्कर
जेएनयुतील अध्यापक
sharadcrosshuma@gmail.com

Two things fill the mind with ever-increasing wonder and awe...: the starry heavens above me and the moral law within me.

- Kant

‘**माझ्या मनाला** सदोदित स्तिमित आणि अवाक करणाऱ्या गोष्टी दोनच... वर चांदण्यांनी दाटलेलं आकाश तर माझ्या आतली नैतिकतेची जाणीव’- इमॅन्युएल कांटच्या थडग्यावर कोरलेले हे शब्द त्याच्या समन्वयी तत्त्वज्ञानाचा गाभा नेमकेपणाने मांडतात. मनुष्याच्या द्विधा प्रकृतीचं काव्यात्म वर्णन करणाऱ्या या विधानाचे अनेक अन्वयार्थ लावता येतात. चांदण्यांनी दाटलेलं आकाश म्हणजे विराट भौतिक वास्तव जे मनुष्याला त्याच्या क्षुल्लकतेची, सान्तपणाची (finitude), परायत्ततेची (heteronomy) आठवण करून देतं; तर दुसऱ्या बाजूला अंतरंगात उफाळून येणारी नैतिकतेची भावना, विवेकाचा आवाज म्हणजे स्वातंत्र्याचं, स्वायत्ततेचं, प्रतिष्ठेचं, अनंताचं द्योतक आहे. कांटच्या दृष्टीनं मनुष्याचं चरित्र सान्त असलं तरी त्याच्यातलं विवेकी नैतिक तत्त्व अनंताचा निर्देश करणारं आहे. त्यामुळे मनुष्य फक्त वस्तूंपैकी एक वस्तू ठरत नाही. असणं (being) आणि नसणं (nothingness) मध्ये मनुष्य फक्त घडत नाही, तर बनत (becoming) असतो. त्याच्या विवेकशील बनण्यात तो सक्रिय ज्ञाता, कर्ता म्हणून अतीततेच्या आणि अनंताच्या संपर्कात येत असतो. मनुष्याची ही विवेकशील बनण्याची प्रक्रिया स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेशिवाय मांडता येत नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्याची संकल्पना कांटच्या फिलॉसफिकल ॲन्थ्रपॉलजीचं सारभूत तत्त्व आहे.

कांटच्या थडग्यावर कोरलेल्या या विधानात कांटप्रणीत मानवतेची संकल्पनासुद्धा ध्वनित होते. ही संकल्पना त्याच्या विवेकी नीतिशास्त्राचं अधिष्ठान आहे. उदा.- भौतिक विश्वाविषयी धर्मशास्त्र आणि मिथकशास्त्रांमध्ये मानवी समूहनिहाय अनेकविध धारणा आढळतात, पण आधुनिक विज्ञानात मात्र या भौतिक विश्वाचं समूहनिरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ आणि वैश्विक आकलन असतं. त्याच वैज्ञानिक दृष्टिकोनानं पाहिल्यास, मानवी मनाच्या तळाशी असणारे विवेकी नीतिनियम एकमय मानवता सूचित करतात. त्यामुळे खासगी आणि ऐतिहासिक फरक विवेकी पातळीवर अदृश्य करून सार्वत्रिक वैश्विक नीतिशास्त्राची मांडणी करता येते, असा युक्तिवाद कांट करतो.

मानवी स्वभावातल्या नैसर्गिक, विवेकेतर तत्त्वासोबतच निसर्गातीत विवेकी तत्त्व सूचित करणारं, वैश्विक नीतिशास्त्राचा निर्देश करणारं कांटचं आशयघन अवतरण त्याच्या ‘क्रिटीक ऑफ प्रॅक्टिकल रीझन’ या महत्त्वपूर्ण ग्रंथाच्या शेवटी आढळते.

याआधी आपण पाहिलं की ‘क्रिटीक ऑफ प्युअर रीझन’मध्ये कांट तीन मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतो : मला काय ज्ञात होऊ शकतं? मी कसं वागायला पाहिजे? कशाविषयी आशावादी असणं माझ्यासाठी इष्ट आहे? पहिल्या प्रश्नाची अर्थात मानवी ज्ञानाच्या शक्यता आणि मर्यादांविषयी विस्तृत ज्ञानशास्त्रीय चर्चा करून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी ‘माणूस म्हणजे नेमकं काय?’ हा चौथा प्रश्न कांट ‘क्रिटीक ऑफ प्रॅक्टिकल रीझन’ या ग्रंथात चर्चेसाठी घेतो. ‘क्रिटीक ऑफ प्युअर रीझन’ या पहिल्या क्रिटीकात कांटनं ज्ञाता म्हणून मनुष्याच्या क्षमता, शक्यता, मर्यादांवर बोट ठेवलंय : अनुभवांच्या कक्षेबाहेर पडून जगाचं अंतिम स्वरूप, मानवी स्वातंत्र्य, ईश्वराचं अस्तित्वसारख्या अतीततादर्शक गोष्टींविषयी मानवी बुद्धी ठामपणे ज्ञानात्मक दावे करते तेव्हा आपोआप अंतर्विरोधांमध्ये अडकून पडते. अशा मूलभूत अंतर्विरोधात्मक दाव्यांना कांट ‘ॲन्टिनोमी ऑफ ह्यूमन रीझन’ म्हणतो.

मानवी स्वातंत्र्याविषयी अंतर्विरोधात्मक निष्कर्षांकडे नेणारी तिसरी ॲन्टिनोमी कांटच्या मनुष्यविषयक संकल्पनेच्या केंद्रभागी आहे. भौतिक जगाचं आणि त्याचाच भाग असणाऱ्या मनुष्याचं स्वरूप न-नैतिक (non- rational) असल्यानं वैज्ञानिक ज्ञान कार्यकारणभावाच्या तत्त्वानुसार यांत्रिक पद्धतीनं उलगडा करतं. त्या दृष्टीनं मानवी स्वातंत्र्य अप्रस्तुत ठरतं. याउलट, मनुष्याच्या नैतिक कृतीसाठी मानवी स्वातंत्र्य अनिवार्यच असतं. कारण मानवी स्वातंत्र्याशिवाय मनुष्याला नैतिक कृती करणं, जबाबदार ठरवणं, त्याची स्तुती किंवा दोष देणं अतार्किक ठरेल. वैज्ञानिक ज्ञानव्यवहारातली नैसर्गिक कारणता आणि मानवी नैतिक कृतीसाठी लागणारं स्वातंत्र्य यांमधला पेच सोडविण्यासाठी कांट वास्तवाची विभागणी दोन जगांमध्ये - अर्थात ‘फेनोमेना’ आणि ‘नुमेना’ मध्ये करतो. फेनोमेनन किंवा साधनं म्हणून मनुष्याचा यांत्रिकपणे उलगडा होऊ शकतो. पण नुमेनन किंवा साध्यं म्हणून यांत्रिक स्पष्टीकरणापलीकडे जाऊन स्वातंत्र्याचा विचार करावा लागेल. अशा रीतीने कांट विज्ञानाच्या प्रतिष्ठेला धक्का न लावता नैतिक व्यवहाराचं क्षेत्र निश्चित करतो.

पहिल्या क्रिटीकानंतर सात वर्षांनी लिहलेल्या ‘क्रिटीक ऑफ प्रॅक्टिकल रीझन’मध्ये कांट विवेकी कर्ता म्हणून मनुष्याच्या क्षमता, शक्यता आणि मर्यादांची चर्चा करतो. थोडक्यात, कांटचं समग्रलक्षी तत्त्वज्ञान फक्त ज्ञानशास्त्रीय पैलूपर्यंत मर्यादित न राहता प्रबोधनपर्वाला अनुरूप मानवी स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या कर्तव्यप्रधान विवेकी नीतिशास्त्राची मांडणी करतं. कदाचित त्यामुळं ‘क्रिटीक ऑफ प्रॅक्टिकल रीझन’चा उल्लेख ‘मानवी स्वातंत्र्याचं पुस्तक’ असाही केला जातो. कारण या पुस्तकात कारणतेच्या चौकटीत आकार घेणाऱ्या वैज्ञानिक ज्ञानासोबतच एक विवेकी कर्ता म्हणून मानवी व्यक्तीला प्रतिष्ठा प्रदान करणाऱ्या कर्तव्यप्रधान नीतिशास्त्रासाठी स्वातंत्र्याची शक्यता आणि अनिवार्यतेची तार्किक आधारानं मांडणी करण्यात आली आहे.

कांटची ‘फिलॉसफिकल ॲन्थ्रपॉलजी’

‘माणूस म्हणजे नेमकं काय?’ हा फिलॉसफिकल ॲन्थ्रपॉलजीतील कळीचा प्रश्न प्रत्येक तत्त्वज्ञाच्या मांडणीत अनुस्यूत असतो. त्यात प्राप्त मानवी अवस्थेसोबतच वांच्छित अवस्था आणि त्या दिशेनं जाणारी वाट दर्शवलेली असते. कांटची फिलॉसफिकल ॲन्थ्रपॉलजी आणि त्या अनुषंगानं आकार घेणारं नीतिशास्त्र यांत आंतरिक संबंध आहे. ज्ञानशास्त्रीय चर्चा करताना आपण पाहिलं की कांटच्या दृष्टीनं मानवी ज्ञान हे अनुभवनिरपेक्ष साक्षात्कार किंवा इंद्रियसंवेदनांना नकारात्मक प्रतिक्रिया नसून, ‘रचनात्मक प्रतिसाद’ आहे - मानवी बुद्धीचा सक्रिय सहभाग त्यात अनुस्यूत आहे. त्याचप्रमाणे मानवी कृतीसुद्धा जगण्याच्या अनिवार्यतेला दिलेली फक्त नकारात्मक प्रतिक्रिया नसून रचनात्मक प्रतिसाद ठरतो. त्यामुळे ज्ञान आणि कृतीच्या पातळीवरील मानवी बुद्धीचं रचनात्मक योगदान मनुष्याला स्वायत्त ज्ञाता आणि कर्ता म्हणून प्रतिष्ठा प्रदान करतं. कांटची फिलॉसफिकल ॲन्थ्रपॉलजी निष्क्रिय, स्थितिशील, परायत्त नसून सक्रिय, गतिशील आणि स्वायत्त आहे. अशा मानवी प्रकृतीचा आधार दैवी आदेश, सामाजिक रूढीपरंपरा किंवा विवेकेतर खासगी सुखवादी घटक नसून मानवी विवेक आहे.

लेखाच्या सुरुवातीला नमूद केल्यानुसार, मानवी प्रकृती द्विधा अर्थात विवेकेतर आणि विवेकी तत्त्वांनी बनलेली आहे. या दोन टोकांमधली तारेवरची कसरत करणारा माणूस हा कांटच्या तत्त्वचिंतनाचा विषय. कांटच्या भाषेत सांगायचं तर, अनुभवांतून जाणारा ‘स्व’ (empirical, phenomenal ego) कारणतेच्या मर्यादेत घडतो (gets constituted) तर अनुभवातीत ‘स्व’ (transcendental noumenal ego) स्वातंत्र्याच्या अवकाशात बनत (becomes) असतो. ही दुहेरी रस्सीखेच मानवी द्विधा प्रकृतीचं व्यवच्छेदक लक्षण मानलं जातं. अनुभवातून जाणारा ‘स्व’ साहजिकच खासगी, नैसर्गिक, तात्कालिक गरजा, इच्छा, आकांक्षा, वासनासारख्या विवेकेतर घटकांनी प्रभावित होऊन वागत असतो. तर अनुभवातीत विवेकशील ‘स्व’ सार्वत्रिक वैश्विक चिरकालिक नैतिकतेला बांधील असल्यानं स्वतःतल्या विवेकी आदेशाचं पालन करत कर्तव्यबुद्धीने वागतो. त्यामुळे कांटचं नीतिशास्त्र प्रयोजनवादी, परिणामवादी, उपयुक्ततावादी, सुखवादी नसून विवेकवादी आहे.

कांटच्या मांडणीत मनुष्याचा अंतिम थांबा ज्ञान नसून कृती आहे. कारण कृतिशीलतेतच मनुष्याला त्याच्या मानवतेचा बोध होतो. त्यामुळे फक्त ज्ञानी असणं पुरेसं नाही. कांटच्या दृष्टीनं मानवता फक्त एक अमूर्त कल्पना किंवा अप्राप्य क्षितिज नसून प्रत्येक माणसात अस्तित्वात असणारं वैश्विक तत्त्व आहे. त्यामुळे वागताना आपण कधीही असं कृत्य करता कामा नये जे इतरांनी आपल्या बाबतीत करू नये असं आपल्याला वाटतं. मनुष्यानं असं कृत्य करावं ज्याला आपोआप वैश्विक नियमाचा दर्जा प्राप्त होईल. कांटचं बिनशर्त विवेकी नीतिशास्त्र आदेश देतं : act in such a way that you treat humanity, whether in your person or in the person of any other, never merely as means to an end, but always at the same time as an end.

साधन- साध्य हा भेद कांटच्या नीतिशास्त्राचा गाभा आहे. माणसाचं फक्त साधन असण्यात त्याची परायत्तता दडलेली आहे. तर स्वायत्ततेमुळे साध्य म्हणून त्याला मूलभूत अर्थ प्राप्त होतो. प्रगल्भ सदसद्विवेकबुद्धीच्या मदतीनं मनुष्याला स्वतःमध्ये आणि इतरांमध्ये फक्त साधनच नव्हे तर साध्य अर्थात ‘आत्मप्रतिष्ठा असलेलं स्वायत्त अस्तित्व’ दिसत असतं. कांट स्पष्ट करतो की नैतिक व्यवहारासाठी परायत्तता नैतिकतेचा मृत्यू ठरते. नैतिक वागणुकीला लागणारी अनुभवातीत सामग्री प्रत्येक व्यक्तीच्या अंतरंगात असल्यानं नैतिकता बाहेरून कोंबणं तर्कविसंगत आहे. कांटचा वांच्छित समाज (Reich der Zwecke) म्हणजे असा नैतिकदृष्ट्या प्रबुद्ध समाज जिथं प्रत्येक व्यक्ती स्वनियमनासाठी पात्र ठरतो. अशा प्रबुद्ध समाजाचे सदस्य स्वतः घालून दिलेल्या विवेकी आदेशाच्या अंतर्गत स्वतःला आणि इतरांना साधन म्हणून नव्हे तर साध्य म्हणून पाहतात. थोडक्यात, कांटच्या नीतिशास्त्राचं प्रयोजन ज्ञानी असणं नव्हे तर कृतीतून स्वातंत्र्याचा आविष्कार करणं आहे. अर्थात, इतरांची स्वायत्तता मान्य केल्याशिवाय माणूस स्वतः खऱ्या अर्थानं स्वायत्त ठरत नसतो. Was ist Aufklärung? या छोटेखानी निबंधात कांट नमूद करतो की तत्कालीन समाज परायत्ततेतून पूर्णतः बाहेर पडून स्वायत्त झालेला नसला तरी, मानवतेची कष्टप्रद नागमोडी वळणांची वाटचाल त्याच दिशेनं होत आहे. आधुनिक माणूस प्रबोधनपर्वाच्या आश्वासनानुसार खरंच स्वायत्त झाला की त्याच्या परायत्ततेच अधिक भर पडली याविषयी पुढील लेखात.

कुतूहल

मिथेन संकलन!

मिथेन हा नैसर्गिक वायू आहे. याला मिथाइल हायड्राइड असेही म्हणतात. हा रंगहीन, गंधहीन आणि अत्यंत ज्वलनशील हरितगृहवायू आहे. मिथेन आणि इतर हरितगृह वायू वातावरणातील अवरक्त (इन्फ्रारेड) किरणे शोषून घेतात व त्यामुळे वातावरणातील उष्णता वाढते. यात मिथेनचा सहभाग २५ टक्के आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर वातावरणातील मिथेनचे प्रमाण १६० टक्क्यांनी वाढले. पाण्यातील जीवाणू व विनॉक्सी सूक्ष्मजीव मिथेन तयार करतात. गायी, म्हशींसारख्या प्राण्यांच्या पचनक्रियेदरम्यानही मोठ्या प्रमाणात मिथेन वायू तयार होतो.

बॅकपॅक तंत्रज्ञान

अनेक कृत्रिम रासायनिक क्रियांद्वारे मिथेन नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले जातात. परंतु, मिथेनचे संकलन करून वा मिथेन वापरून त्याचे वातावरणातील प्रमाण कमी करता येईल. यामुळे पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदेही होतील. या उद्देशाने अर्जेंटिना येथील राष्ट्रीय कृषितंत्रज्ञान संस्थेने गायीच्या पचनक्रियेतून निघणारा मिथेन वायू त्याच गाईच्या पाठीवर एका पिशवीत (बॅकपॅक) संकलित केला जाईल, असे तंत्रज्ञान विकसित केले. या तंत्राने प्रतिदिन ३०० लिटर मिथेनचे संकलन होते. २०३० पर्यंत या तंत्रज्ञानाचा वापर करून मिथेनचे उत्सर्जन २०-३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

मिथेनचा पोषणासाठी किंवा ऊर्जास्रोत म्हणून उपयोग करणारे मिथेनोट्रोपिक जीवाणू मिथेन वायूचे वातावरणातील प्रमाण कमी करण्यात भाग घेतात. मिथेनोट्रोपिक जीवाणू पाणथळ जमिनीत, जंगलातील दलदलीच्या जागी वाढतात. अशा दलदलीच्या ठिकाणी मिथेन निर्माण करणारे जीवाणूही असतात. मिथेनोट्रोपिक जीवाणू हे प्राणवायू घेऊन किंवा प्राणवायूशिवायही जगू शकतात. (उदा. गॅमा आणि अल्फा प्रोटिओ बॅक्टेरिया, वेरूकोमायक्रोबिया, मेथायलोकोकस कॅप्शूलॅटस, इत्यादी).

पॉलीहायड्रॉक्सीअल्कॅनोएट्स. पॉलीहायड्रॉक्सीब्युटायरेट हे मिथेनोट्रोपिक जीवाणू प्लास्टिकसदृश नैसर्गिक पॉलिमर तयार करू शकतात. हे नैसर्गिक प्लॅस्टिक सहज विघटनशील, जैवसुसंगत आणि जैवपुनर्निर्मितीसाठी योग्य असते. मिथेनोट्रोपिक जीवाणूंमध्ये खूप विविधता आहे. पाणथळीपासून मिथेनोट्रोपिक जीवाणूंचे विलगीकरण करून त्यावर संशोधन केले जात आहे. सडणाऱ्या सेंद्रिय कचऱ्यापासून मिथेन निर्माण करून त्यापासून ऊर्जा निर्माण करण्याचा प्रयत्न पर्यावरण संरक्षण संस्था, ऊर्जा विभाग व राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाळा इत्यादी विविध संघटना करीत आहेत.

‘मिथेनवायू संकलन’ही कल्पना जरी चांगली असली तरी, खर्चीक आहे. मिथेन पचनयंत्राचे किचकट तंत्रज्ञान आणि मिथेन पचनयंत्रात आवश्यक अशा विशिष्ट कचऱ्याचा करावा लागणारा अविरत पुरवठा; या अडचणींमुळे मिथेनवायू संकलन ही परीकल्पना आहे की काय, असे वाटते.

- डॉ. जयश्री कृष्णा सैनिस
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

बाबा, पण वेंगा नाही!

***दिवसभर प्रचार** करून थकल्याने बिछान्यावर पडताक्षणी पृथ्वीराजबाबांना गाढ झोप लागली. पहाटे बंद डोळ्यांसमोर लख्ख प्रकाशझोत पडू लागला. क्षणकाळानंतर त्यातून काळा वेश धारण केलेली एक आकृती प्रकट झाली व संवाद साधू लागली. ‘मी बाबा वेंगा, माझ्या भविष्यवाणीविषयी तू वाचले असशीलच. माझ्या शरीराचे आत्म्यात रूपांतर होऊन २९ वर्षे झाली तरीही लोक मीच भविष्य वर्तवले असे आजही जगाला सांगत असतात. मग ती फुटबॉलची स्पर्धा असो, करोना वा यंदा होणारी जगबुडी. यामुळे मला मुक्तीच मिळेनाशी झाली आहे. यावर उपाय एकच- माझी विद्या हस्तांतरित करणे. त्यासाठी मी तुझी निवड केली. एक तर तुझ्या नावात बाबा आहे, दुसरे म्हणजे पृथ्वी हा शब्दही आहे, तिसरे, सध्या पराभूत असल्याने व पक्षात फारसे कुणी विचारत नसल्याने तुझ्याजवळ रिकामा वेळ आहे. चौथे तू अभ्यासू असून तंत्रज्ञान खाते सांभाळलेला नेता अशी तुझी ओळख आहे. तुझ्या भविष्य वर्तवण्यावर लोक चटकन विश्वास ठेवतील. पाचवे व महत्त्वाचे म्हणजे तुझे प्रतिपादन तर्कसंगत असते. अशी मांडणी केली की लोक सहज विश्वास ठेवतात. यामुळे मी तुझी निवड केली. आता तात्काळ हो म्हण व माझ्या आत्मामुक्तीला हातभार लाव.’*

हे ऐकल्यावर बाबांच्या तोंडून अभावितपणे ‘हो’ निघून गेले, तशी ती आकृती अंतर्धान पावली. त्याबरोबर ते जागे झाले. उठून संगणक सुरू केला. वेंगाच्या भविष्यकथनाची उजळणी केली. या ज्योतिष क्षेत्रावर प्रतिगामी समजल्या जाणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे वर्चस्व. त्यात घुसखोरी करायची असेल तर सुरुवात सॉलिड करायला हवी म्हणून ते डोके चालवू लागले. काहीच सुचेना म्हणून अस्वस्थ झालेल्या बाबांनी त्या दिवशीच्या प्रचारसभा रद्द केल्या. संगणकावर दिवसभर शोधाशोध केल्यावर सायंकाळी जेफ्री एपस्टीन या नावावर ते थबकलेच. मग भराभर त्यांनी त्याविषयीची माहिती वाचून काढली. पक्षशिस्तीच्या मर्यादेत राहून, महाराष्ट्रधर्माचे पालन करून देशात खळबळ उडवून द्यायची असेल तर लवकरच उघड होणाऱ्या एपस्टीनच्या फाइल्स हेच कथानक योग्य यावर त्यांनी शिक्कामोर्तब केले. या फाइल उघड होताच विश्वगुरू जाणार व नागपूरचा मराठी माणूस देशाचा प्रमुख होणार अशी ‘कॅचलाइन’ ठरल्यावर ते निश्चिंत झाले. नागपूर म्हटले की सध्या दुखावलेला परिवारही सुखावणार हे लक्षात येताच ते हसले.

एकीकडे भविष्यवाणी व दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांमध्ये भ्रम निर्माण करणे हे दोन्ही हेतू यातून सफल होतील, शिवाय या नव्या क्षेत्रात दमदार पदार्पणाचा आपला मार्गही मोकळा होईल असा विचार मनात येताच ते आनंदले. आपल्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वाला अमेरिकेतील वास्तव्याची पार्श्वभूमी आहेच त्यामुळे लोकही विश्वास ठेवतील असे म्हणत त्यांनी मुहूर्त शोधायला सुरुवात केली. लगेच त्यांना काही डाव्या व पुरोगाम्यांनी दिलेले पुस्तक प्रकाशनाचे निमंत्रण आठवले. भविष्यकथनासाठी हेच व्यासपीठ योग्य असे ठरवत ते पिंपरी चिंचवडला निघाले. ठरल्याप्रमाणे सर्वकाही पार पडल्यावर चर्चेला पेव फुटले. समर्थन व टीकेने माध्यमे भरून राहू लागली. तेवढ्यात बाबांच्या डोक्यात विचार आला. १९ तारीख टळली तर काय? मग त्यांनी दिवसरात्र गाढ झोपून वेंगांची आळवणी केली पण ती दर्शन देईना! अखेर त्यांनी या दिवशी कृष्णेकाठच्या एखाद्या ‘सुरक्षित’ स्थळी जाऊन ध्यानसाधना करण्याचा निर्णय घेतला.

तर्कतीर्थ विचार

अमोघ वक्तृत्वाची मोहिनी

‘**तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री** जोशी समग्र वाङ्मय’ प्रकल्पातील १७ वा खंड हा ‘स्मृतिगौरव’ म्हणून संपादित केला आहे. यात १९३७ ते २०२३पर्यंतच्या ८६ वर्षांच्या कालखंडात सुमारे ९० विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी स्मृती, गौरवपर लेख लिहिले आहेत. या लेख शीर्षकांमधील तर्कतीर्थ व्यक्तिमत्त्वाची नुसती गुणवैशिष्ट्ये न्याहाळली, तरी हा माणूस दशांगुळे वर उरतोच. महाराष्ट्राचा सत्पुत्र, उपेक्षितांचा पुढारी, बुद्धिवादी वेदांती, शतकाचा साक्षीदार, प्रकांडपंडित, धर्मसमीक्षक, संस्कृती भाष्यकार, प्रबोधनपुरुष, समाजसुधारक, इहवादी ऋषी, ज्ञानभास्कर, चालता-बोलता ज्ञानकोश अशी विशेषणे बहाल करताना मान्यवर थकत नाहीत. कारण सुमारे सात दशकांच्या सक्रिय जीवनात या माणसाने पायाला भिंगरी लावत जग पालथे घातले! त्यांच्या वक्तृत्वाच्या मोहिनीने विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील महाराष्ट्र एकीकडे फिदा होत होता, तर दुसरीकडे प्रबुद्ध.

अनंत विष्णू पाटणकरांनी १९५३मध्ये ‘मी व माझे वक्तृत्व’ शीर्षक ग्रंथ संपादित केला आहे. यातील तर्कतीर्थांची मुलाखत वाचताना उमजत जाते की, तर्कतीर्थांनी पहिले जाहीर भाषण केले १९२४मध्ये. पश्चिम खान्देशातील सोनगीर (जि. धुळे) येथे संपन्न पंडित परिषदेत अखिल भारतातील सर्व जगद्गुरू (शंकराचार्य), धर्ममार्तंड, संस्कृत पंडित इत्यादी सनातनी पीठाचार्यांसमोर ‘हिंदू धर्म परिवर्तनशील आहे’ असे बजावणाऱ्या एका तरुण संस्कृत पंडिताने (वय वर्षे अवघे २३) धीटाईने केलेले भाषण उपस्थित सर्वांना निरुत्तर नि अवाक करणारे ठरले होते! सन १९५३पर्यंतच्या तीन दशकांत सहस्र भाषणे देणारा हा प्रगल्भ वक्ता; त्याने नंतरच्या चार दशकांत किती भाषणे दिली असतील, त्याची नोंद नाही. परंतु समग्र वाङ्मयात पूर्ण लिखित संहितांच्या रूपात उपलब्ध भाषणे केवळ शंभर-सव्वाशे मिळणे, याचे कारण त्यांच्यातील बोलण्याचा अमाप उत्साह आणि तितकाच लेखनाचा आळसही!

वक्ता म्हणून तर्कतीर्थ तयारी करून बोलत. पूर्वविचार नि स्वाध्याय असायचा. वक्तृत्वात व्यासंगी वाचन, चिंतन आपसूक झरत राहायचं. चपखल दृष्टांत देण्याची हातोटी होती. सनातन संदर्भ घेऊन, मिथक, चरित्र, कथा, आख्यायिकांच्या आधारे त्यांचे आधुनिक परिशीलन करण्याचे कसब हे त्यांच्यातील वक्त्याचे अंगभूत कौशल्य होते. याच वक्तृत्वाच्या कौशल्यावर या माणसाने कायदेभंगाच्या चळवळीत बागलाण (कळवण, मांगीतुंगी, नामपूर) प्रांतातील हजारो आदिवासींचे संघटन करीत केलेल्या जंगल सत्याग्रहात ब्रिटिशांची झोप मोडली होती. वक्तृत्वात तर्क नि तत्त्वज्ञानाचे बेमालूम मिश्रण श्रोत्यांना हमखास आपले करीत असे. वादविवादाची सवय त्यांना वक्ता बनवत गेली. वैचारिक प्रबुद्धता येत गेली, तसे त्यांचे वक्तृत्व फुलत गेले ‘सरमन्स माऊंटन’सारखे! विषय श्रोत्यांवर बिंबविण्याची कला भाषणांच्या रियाजातून समृद्ध होत गेली. कोटी, टीका यांना फाटा देत गंभीर विवेचन म्हणजे त्यांचे भाषण; पण प्रसंगी आचार्य अत्रेंसारख्या पट्टीच्या वक्त्यासही प्रतिवाद करीत निरुत्तर करणारे ठरले.

चांगला वक्ता इतरांच्या वक्तृत्वगुणांचा अभ्यासक असतो. तर्कतीर्थांनी पाटणकरांना दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या समकालीन वक्त्यांच्या वक्तृत्वगुणांची नोंद करीत पुढील निरीक्षणे नोंदविली आहेत- १) आचार्य विनोबा भावे- उच्च भावुकता व प्रासादिकता, २) स्वातंत्र्यवीर सावरकर- प्रतिभाशक्ती व ध्येयनिष्ठ स्वप्नशीलता, ३) बॅरिस्टर मुकुंदराव जयकर- ऐट व इंग्रजीचा झोकदारपणा, ४) प्रा. श्री. म. माटे-वेधक भाषा व विवेचकता, ५) महामहोपाध्याय द. वा. पोतदार- स्वाभाविक वाचाशक्ती (वाचासिद्धी), पुष्कळ अवलोकन (निरीक्षण), ६) आचार्य दादा धर्माधिकारी- ध्येयवादीपणा व खोचक विनोदबुद्धी, ७) न. वि. तथा काकासाहेब गाडगीळ- समयसूचकता, विचारशीलता, कोटिक्रम-कुशलता, ८) प्रा. गोवर्धन पारीख- स्वाभाविक वाचाशक्ती व कोटिक्रम-चातुर्य, ९) आचार्य प्र. के. अत्रे- विनोदबुद्धी, उत्साह व भाषाचातुर्य, १०) यशवंतराव चव्हाण- मर्मज्ञता व समयज्ञता, ११) दिनकरशास्त्री कानडे- गांभीर्य व ओजस्विता, १२) श्रीपाद शंकर नवरे- कोटिक्रम व मुद्देसूदपणा. ज्या वक्त्यास इतर वक्त्यांच्या वक्तृत्वगुणांची पारख असते, तो आपले वक्तृत्व इतरेजनांपेक्षा हटके राहावे, यासाठी नित्य सजग नि सहज साधना करत राहतो.

- डॉ. सुनीलकुमार लवटे
drsklawate@gmail.com

सांगाड्यासाठी साठमारी!

महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुका नक्की कोणत्या मुद्द्यावर लढल्या जाणार, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा बौद्धिक प्रामाणिकपणा एकाही पक्षाकडे आज उरलेला नाही...

प्रदीर्घ काळ विवाहाच्या प्रतीक्षेत राहावयाची वेळ आलेला बोहोल्यावर चढण्यास जेवढा उतावीळ असतो त्यापेक्षाही अधिक हुरहुर राज्यातील उद्याच्या 'विकासगामी' राजकीय नेत्यांच्या मनात होती. महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने तीस एकदाचे तोंड फुटेल. राज्यभरातील तब्बल २९ महापालिकांतून आता विकासगंगा वाहू लागतील आणि तीत हात धुऊन घेण्यासाठी राज्यातील हे विकासेच्छुक वाट्यालोटे घेऊन राजकीय पक्षांचे उंबरठे झिजवू लागतील. राज्यात इतके विकासेच्छू आहेत हे पाहूनच खरे तर समस्त मराठीजनांचे छातीचे पिंजरे अभिमानाने फुलून यायला हवेत. तसे होताना दिसत नाही. याचे कारण आचारी खूप वाढले की ज्याप्रमाणे खाद्यपदार्थाची माती होते त्याप्रमाणे विकासेच्छूंची संख्या वाढली की प्रत्यक्ष विकास मागे पडतो आणि या विकासेच्छूंचाच विकास अधिक होतो या वास्तवाची जाणीव मराठीजनांस गेल्या काही वर्षांत झाली असणार. आता निवडणुका जाहीर झाल्याने राज्यभरातून हजारो विकासेच्छू स्व-विकासार्थ सज्ज होतील आणि तो एकदा सुरू झाला की वर्ष- सहा महिन्यांत या विकासेच्छूंच्या गळ्यात जाडजूड 'चैनी' दिसू लागतील आणि 'चार बांगडी'धारी मोटारी त्यांचा प्रवास सुखकर करतील. तथापि मुद्दा या निवडणुकांमुळे राज्यभरातील सर्वपक्षीय विकासेच्छूंत कसे उत्साहाचे वारे संचारले आहे हा नाही. या सर्वपक्षीय विकासेच्छूंची चिंता अजिबात नाही. चिंता आहे, महाराष्ट्राचे काय होणार याची.

याचे कारण महापालिका चालवू पाहणाऱ्या एकाही राजकीय पक्षाकडे या महानगरांसाठी ते काय करू इच्छितात याचा कार्यक्रम नाही. आहे ते फक्त राजकारण. याला आडवे करणे आणि त्या पक्षाला फोडणे या साठमारीपलीकडे हे राजकीय पक्ष जाण्यास तयार नाहीत. तितकी त्यांची कुवत नाही. निवडणुका म्हटले की त्यात जिंकण्याच्या ईर्षेने राजकीय पक्षांनी उतरणे यात काही गैर नाही. पण जिंकल्यावर आपण या शहरांचे नक्की काय भले करणार, याचे उत्तर नसणे हे अत्यंत गैर. सर्व प्रयत्न जिंकण्याचे आणि यश मिळाल्यानंतर स्वतःची धन करण्याचे मार्ग शोधण्याचे. हा मार्ग म्हणजे शहराशहरांत जीव मुठीत धरून कशाबशा अस्तित्व टिकवून असलेल्या मोकळ्या जागा. त्या बांधकामांस खुल्या करणे हा यांच्यासमोरील एकमेव कार्यक्रम. तो या महापालिकांत लोकनियुक्त प्रशासन नव्हते तेव्हाही राबवला जात होता आणि या निवडणुकांनंतरही त्याची जोमाने अंमलबजावणी होईल. राजकारण करायचे ते पैसे कमावण्यासाठी आणि पैसा कमवायचा तो अधिक व्यापक राजकारण करता यावे यासाठी, हे आजचे आपले राजकीय वास्तव. यास कोणीही आणि कोणताही पक्ष अपवाद नाही. त्यामुळे सर्व राजकीय चर्चा आहे ती कोणाशी आघाडी करावयाची आणि कोणास एकटे पाडायचे इत्यादी. या असल्या क्षुद्र राजकारणाचा परिणाम महाराष्ट्रात सर्वदूर दिसतो. या कटू वास्तवाकडे या राजकारण्यांस डोळेझाक करावयाची असली तरी हे वास्तव समोर आणणे हे जबाबदार माध्यमांचे कर्तव्य ठरते.

दररोज दिवस सुरू होताना हे वास्तव डोळ्यात भरते. धूळ आणि धुरात प्रकाश हरवून बसलेला सूर्य आपल्या शहरांचे भिकार वास्तव समोर ठेवतो. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या शहरांतील हवा श्वासास काय उच्छ्वासासाठी देखील अपात्र ठरावी इतकी वाईट. हवेचा निर्देशांक दिल्लीशी स्पर्धा करेल इतका. यावर यांचा उपाय काय? तर हवेत पाणी उडवणे. आपले नागरिक इतक्या बाळबोध उपायांवर विश्वास ठेवणारे आहेत याची राज्यकर्त्यांस कमालीची खात्री. बरे, आपणास कसेही मूर्ख बनवता येते हे नागरिकांनी वारंवार सिद्ध करून दाखवलेले. त्यामुळे राजकीय पक्षांस तरी दोष कशाला द्या! शहरांतील प्रदूषणाची पातळी दिवसागणिक वाढत असताना नाशिकसारख्या शहरांत १८०० झाडांची कत्तल करण्याचा घाट सरकार घालू शकते ते नागरिकांच्या मूर्ख बनण्याच्या क्षमतेवर विश्वास आहे म्हणून. ठाण्यातही झाडांचे असेच शिरकाण निर्धोकपणे सुरू आहे. याआधी सरकारने १० कोटी झाडे लावण्याची घोषणा केली होती. तिचे काय झाले? ही हिरवाई कोठे तयार झाली? याच्या जोडीला पुनर्विकासाच्या नावाखाली जो काही विकासकांचा धिंगाणा राज्यात सध्या सुरू आहे तोदेखील या मूर्ख बनून घेण्याच्या नागरिकांच्या क्षमतेच्या आधारेच. ज्या रस्त्यांवर आहे ती वाहतूक सुरळीत राहू शकत नाही त्या रस्त्यांच्या कडेला टोलेजंग इमारतींना सर्रास परवानगी दिली जाते आणि कोणालाही काहीही वाटत नाही. अर्थात देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई आणि परिसरात डझनांहून अधिकांचे प्राण केवळ रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे जातात तेव्हा तरी कोणास कोठे काय वाटते, हा प्रश्न आहेच.

> **राजकारण करायचे ते पैसे कमावण्यासाठी आणि पैसा कमवायचा तो अधिक व्यापक राजकारण करता यावे यासाठी, या क्षुद्र राजकीय वास्तवापायी शहरांतला सूर्यप्रकाशही धूळ आणि धुरात हरवून जातो, हवा श्वास घेण्यास लायक उरत नाही...**

तेव्हा या सगळ्यांचे मूळ असलेला प्रश्नः निवडणुका नक्की कशासाठी लढल्या जाणार आणि नागरिकांनी मतदान नक्की कोणत्या कारणांसाठी करावयाचे; हा. या प्रश्नाचे उत्तर सापडले नाही तरी त्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी कारण आपली मरणासन्न शहरे. आज राज्यातील एकही शहर स्वतःच्या पायावर उभे नाही. अर्थात एकमेव अपवाद मुंबई. तथापि या शहराची तिजोरीही इतकी झपाट्याने खंक होऊ लागलेली आहे की ही गती तशीच राहिली तर आगामी वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महापालिकेस पैसे हातउसने घ्यावे लागतील. एकेकाळी संपूर्ण आशिया खंडात धनाढ्य म्हणून गणली जाणारी पिंपरी-चिंचवड महापालिका, मुंबईच्या सावलीतील ठाणे, पुणे आदी अनेक शहरांसमोरील आव्हान आज हेच आहे. वस्तू/सेवा कराच्या आगमनानंतर मुदलात राज्य सरकारांच्या उत्पन्नावर घाला घातला गेला. तेव्हा राज्यांच्या आडातच खणखणाट असेल तर महानगरपालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोहोऱ्यात कोठून ओलावा असणार. अशा परिस्थितीत या शहरांना राज्यासमोर हात पसरण्याखेरीज पर्याय नाही आणि राज्यास केंद्राकडे तोंड वेंगाडणे अपरिहार्य. जमेल तितके सर्व केंद्रीकृत केले जात असताना आपली शहरे स्वायत्त राहतील ही अपेक्षा चुकीची.

म्हणून हा प्रश्न : या निवडणुका नक्की लढल्या जाणार कोणत्या मुद्द्यावर? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा बौद्धिक प्रामाणिकपणा नसल्यामुळे मग बागुलबुवा निर्माण करायचा ''अल्पसंख्य समाजाची व्यक्ती मुंबईचा महापौर बनेल'', असा. म्हणजे सर्व प्रयत्न पुन्हा 'आपण विरुद्ध ते' असा संघर्ष निर्माण व्हावा यासाठी. मुंबई शहराच्या प्रमुखांचे नामकरण 'महापौर' असे झाले त्यास आणखी सहा वर्षांनी १०० वर्षे होतील. या जवळपास शतकभराच्या प्रवासात अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्ती महापौरपदी निवडली गेली नाही, असे अजिबातच नाही. मुंबईचे पहिलेवहिले महापौर सर बोमन बेहराम (१९३१-३२) हे अल्पसंख्य समाजाचे होते आणि दोनच वर्षांनी या पदावर हुसेनअली रहिमतुल्ला हे निवडले गेले. के एफ नरिमन, एस एम चिनॉय, बी एन करंजिया, मिनू मसानी, ए पी साबावाला, ई. ए. बंदूकवाला आदी अनेक अल्पसंख्याक मान्यवरांनी मुंबईचे महापौरपद भूषवले. या काळात महापौरपदी अधिक व्यक्ती अर्थातच बहुसंख्याक समाजातील होऊन गेल्या. पण असे काय या काळात घडले की अल्पसंख्याक समाजाचा महापौर होईल अशी भीती आता घालण्याची निकड राजकीय पक्षांस वाटावी?

याचे कारण राज्यातील शहरांत पुन्हा एकदा प्राण फुंकले जावेत, नागरिकांस शुद्ध हवा, मोकळे-पदपथधारी-खड्डेमुक्त रस्ते, भरवशाची सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्यसेवा पुरवाव्यात इत्यादी मुद्दे राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरच नाहीत. राजकीय पक्षांची शरपंजरी शहरांच्या सांगाड्यांसाठीची साठमारी उद्विग्न करणारी आहे. स्थानिक नागरी संघटनांनी त्यास आव्हान दिले नाही तर मरणासन्न शहरांचे मरण निश्चित.

तंत्रकारण

काळी आई आणि काळभैरव एआय

पंकज फणसे
तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंतःसंबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक
phanasepankaj@gmail.com

> **अचूक शेतीचे नियंत्रण करणाऱ्या 'कोड्स'च्या ओळींपासून ते क्रिस्पर तंत्रज्ञानाने बदललेल्या पिकांच्या जनुकीय साखळीपर्यंत; मानवी हातांची जागा घेणाऱ्या रोबोटिक्सपासून ते पृथ्वीवरील प्रत्येक शेताचा नकाशा बनवणाऱ्या उपग्रह नेटवर्कपर्यंत; अन्न कोण पिकवणार, त्यातून नफा कोणाला मिळणार आणि उपाशी कोण राहणार याचे नियम तंत्रज्ञान नव्याने लिहीत आहे.**

हरितक्रांती आणि शाश्वतता यांचा उत्पादनापलीकडे विचार केल्यास या प्रवासात जमिनींचा कस कमी झाला, भूजल साठे रिकामे झाले आणि खते आणि औषधे यांसाठी त्रयस्थ घटकांवर अवलंबून राहावे लागले. बी-बियाणाच्या तांत्रिक प्रगतीच्या ध्यासातून काही ठरावीक रासायनिक कंपन्यांची मक्तेदारी अस्तित्वात आली आणि प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी अधिक मौल्यवान ठरू लागले. तंत्रज्ञान वर्चस्व गाजवू लागले की प्रत्यक्ष क्षेत्राशी संबंधित नसणाऱ्यांची मक्तेदारी तयार होते याचे हे परिपूर्ण उदाहरण!! आता आपण सुपातून जात्यात आलो आहोत. जनुकीय क्रांतीच्या निमित्ताने कॉर्पोरेटप्रणीत जैव-तंत्रज्ञान पेटंट असलेली बियाणे, खासगी मालकीचे डेटा प्लॅटफॉर्म आणि भरपूर इनपुट लागणाऱ्या शेतीवर भर देत आहे. कॉर्टेव्हा आणि बायरसारख्या कंपन्या जीन-एडिटेड पिके आणि त्याला जोड म्हणून एआय-आधारित अचूक शेती यांचा प्रचार करत आहेत. अल्गोरिदमद्वारे अनुकूल केलेली अति-कार्यक्षम शेते, कोणत्याही नैसर्गिक तणावाचा सामना करण्यासाठी प्रयोगशाळेत विकसित केलेली पिके आणि कॉर्पोरेट भांडवल व कौशल्याच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेले उत्पादन अशी ही भुरळ घालणारी कॉर्पोरेट जगाची आधुनिक शेतीची दृष्टी आहे. शेतीचा मुख्य उद्देश केवळ कॅलरीज आणि व्यापारी मालाचे उत्पादन वाढवणे हा आहे का? की जमिनीचे संवर्धन करणे, उपजीविकेला आधार देणे आणि सांस्कृतिक प्रथा टिकवून ठेवणे हा आहे?

सध्या विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान या परस्परविरोधी दृष्टिकोनांचे प्रतिबिंब आहे. उदयोन्मुख कृषी तंत्रज्ञान हे केवळ कार्यक्षमता वाढवणारे साधन नसून त्याला राजकीय वर्चस्वाचा वास आहे. ते राष्ट्रे आणि कॉर्पोरेट्स यांच्यातील सत्तेची समीकरणे सक्रियपणे बदलत आहे. अचूक शेतीचे नियंत्रण करणाऱ्या 'कोड्स'च्या ओळींपासून ते क्रिस्पर (CRISPR) तंत्रज्ञानाने बदललेल्या पिकांच्या जनुकीय साखळीपर्यंत; मानवी हातांची जागा घेणाऱ्या रोबोटिक्सपासून ते पृथ्वीवरील प्रत्येक शेताचा नकाशा बनवणाऱ्या उपग्रह नेटवर्कपर्यंत; अन्न कोण पिकवणार, नफा कोणाला मिळणार आणि उपाशी कोण राहणार याचे नियम तंत्रज्ञान नव्याने लिहीत आहे.

डेटाची कुंपणे

शेतीचा एक काळ होता जेव्हा जमिनीची प्रत्यक्ष मालकी ही कुळांची नसून जमीनदाराची होती. नव्या व्यवस्थेत अशीच काहीशी यंत्रणा शेतीच्या यंत्रांच्या बाबतीत अवतरत आहे. या डिजिटल सरंजामशाहीमध्ये मूल्य आणि सत्ता ही जमीन कसणाऱ्यांच्या नाही, तर त्या जमिनीविषयीच्या माहितीवर प्रक्रिया करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मच्या मालकांच्या हाती जमा होते.

तुम्ही हजारो डॉलर्स खर्च करून एखादा स्वयंचलित ट्रॅक्टर खरेदी केला. नव्या परिस्थितीमध्ये एवढे पैसे खर्च करूनदेखील तुम्ही त्याचे मालक नसाल. त्यात काही बिघाड झाल्यास या ट्रॅक्टर कंपन्या तुम्हाला त्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखू शकतील आणि केवळ कंपनीचे अधिकृत तंत्रज्ञच दुरुस्ती करू शकतील. आपली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे कंपनीच्या तंत्रज्ञानांकडून दुरुस्त करून घेताना आणि स्थानिक तंत्रज्ञांकडून दुरुस्त करून घेताना किती तफावत असते हे वापरकर्त्यांना ज्ञात आहेच. उद्या ही सुविधा बंद झाली तर दुरुस्तीसाठी सध्याच्या मूल्याच्या दहापट मूल्य द्यावे लागेल. या मनमानीतूनच मुद्द्याचा उद्रेक एका देशव्यापी चळवळीत झाला. शेतकरी स्वतःचीच उपकरणे हॅक करू लागले आणि अमेरिकेत एकामागून एका राज्यांमध्ये दुरुस्तीच्या अधिकारासाठी कायद्याची मागणी करू लागले. ज्याला कंपनी बौद्धिक संपदेचे संरक्षण म्हणते, त्यालाच शेतकरी डिजिटल वेठबिगारी म्हणतात. याचा अर्थ केवळ उपकरणासाठी पैसे मोजायचे नाहीत, तर आपण ज्याचे मालक आहोत, ते वापरण्याच्या परवानगीसाठीही पैसे मोजायचे. हा लढा शेतीच्या पलीकडे पोहोचला आहे.

'डेटाफिकेशन'ची लढाई भू-राजकारणापर्यंत विस्तारलेली आहे. चीनचा डिजिटल सिल्क रोड हा भौतिक पायाभूत सुविधांपासून तांत्रिक परिसंस्था निर्यात करण्याबाबत आहे. अलीबाबा कंपनीचा 'ईटी ॲग्रिकल्चरल ब्रेन' हा एआय प्लॅटफॉर्म पिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवतो, उत्पादनाचा अंदाज वर्तवतो आणि पुरवठा साखळी नियंत्रित करतो. आग्नेय आशियातील भाताच्या शेतांमध्ये अचूकपणे कीटकनाशके फवारणारे 'डीजेआय ॲग्रस' ड्रोनसारख्या उपक्रमांद्वारे, बीजिंग आपले तांत्रिक मानके आणि डेटाचा प्रवाह विकसनशील देशांमध्ये रुजवत आहे. थायलंडसारखा देश चिनी कृषी एआय प्रणाली स्वीकारतो, तेव्हा त्या देशाच्या अन्न उत्पादन क्षमतेचा डेटा हांगझोऊ आणि शेन्झेनमधल्या सर्व्हरवर साठवला जातो. यामुळे बीजिंगला प्रादेशिक अन्न सुरक्षेविषयी धोरणात्मक गुप्त आणि संवेदनशील माहिती मिळते. बायर आणि बीएएसएफसारख्या कंपन्यांचे पाठबळ असलेले पाश्चिमात्य प्लॅटफॉर्मदेखील त्याच बाजारपेठांसाठी स्पर्धा करत आहेत. मात्र पाश्चात्त्य कंपन्या डेटाला कॉर्पोरेट मालमत्ता मानतात तर चीन रणनीतीत्मक राष्ट्रीय संसाधन मानत आहे. विकसनशील देशांसमोरचा प्रश्न आहे की आपण यापैकी कोणता डेटा वसाहतवाद स्वीकारायचा आहे?

जीन एडिटिंग

डेटाफिकेशन हे कृषीच्या माहितीला कुंपणात ठेवत असेल तर जनुकीय अभियांत्रिकी हे खुद्द जीवनालाच बंदिस्त करण्याचे प्रयत्न करत आहे. क्रिस्पर जीन एडिटिंगचे नियामक राजकारण हा संघर्ष समजून घेतल्यास काही गोष्टी स्पष्ट होतात. अमेरिकेत, क्रिस्पर एडिटेड पिकांना नियमनाची गरज नाही असे मानले जाते. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, क्रिस्पर पिके ही सुधारित जनुकीय पिकांपेक्षा (GMO) कमी धोकादायक असतात. या मवाळ धोरणामुळे कल्पकतेची लाट येऊन दुष्काळ-प्रतिरोधक गहू, रोग-प्रतिरोधक कोको आणि जास्त उत्पादन देणारा तांदूळ वगैरे पिकांचा पूर आला आहे. पण यामुळे तीव्र व्यापारी वादही निर्माण झाले आहेत. युरोपियन युनियनचे म्हणणे आहे की, ग्राहकांच्या चिंता लक्षात घेता, जीन-एडिटेड पिकांना जीएमओ इतक्याच कडक मंजुरी प्रक्रियेतून जावे लागेल. २०१८च्या 'युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस'च्या निर्णयाने या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले. यामुळे अमेरिकन आणि चिनी बायोटेक कंपन्या व्यापारीकरणात वेगाने पुढे जात आहेत, तर युरोपियन प्रयोगशाळा अशा संशोधन, लालफितीत अडकल्या आहेत.

कृषी आणि रोजगार

कृषी क्षेत्रात रोबोट्सचा वापर वाढल्याने मजुरांच्या भविष्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मजुरांचा पुरवठा हा स्थानिक प्रश्न नसून औद्योगिक क्रांतिपश्चात शहरकेंद्रित नागरीकरणाच्या मुळाशी मजुरांचा पुरवठा हाच घटक सर्वाधिक कारणीभूत होता. यांत्रिकीकरणाचे समर्थन केल्याने शेतकरी मतदार आणि कृषी लॉबी खूश होऊ शकतात मात्र जे समुदाय शेतमजुरीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत त्यांना यामुळे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यातूनच वर्गभेद, जातीव्यवस्था, प्रादेशिक असमतोल वगैरे या गोष्टीशी संबंधित राजकीय प्रश्नांना उचल मिळणार आहे. त्याचवेळी यांत्रिकीकरणामुळे श्रमाची एक नवीन पदश्रेणी निर्माण होत आहे. जसजशी पारंपरिक शेतीची कामे नाहीशी होत आहेत, तसा उच्च-कौशल्य असलेल्या नोकऱ्यांचा एक छोटा वर्ग उदयास येत आहे. या नवीन भूमिकांमध्ये टॅब्लेटवरून पिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवणारे ड्रोन वैमानिक, सिंचनाचे अल्गोरिदम नियंत्रण करणारे डेटा विश्लेषक आणि कापणी यंत्रांची देखभाल करणारे रोबोटिक्स तंत्रज्ञ वगैरेंचा समावेश होतो. ही अभिजन कामगार वर्गवारी शेतमजुरांच्या फौजफाट्याला विस्थापित करत आहे, ती त्यांच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. शिवाय, या कामांसाठी अशा शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गरज आहे, जे या विस्थापित मजुरांसाठी अभावानेच उपलब्ध होईल. इथे खरा प्रश्न हा आहे की कृषी यांत्रिकीकरणाचे व्यवस्थापन हे विस्थापित कामगारांना आधार देऊन एक संक्रमण म्हणून केले जाईल? की ते अशा प्रकारे लादले जाईल जिथे माणसांना केवळ माणूस म्हणजे केवळ वापरून फेकून देण्यायोग्य घटक उरेल?

इथले प्रत्येक मूल जन्मतःच आई म्हणत एआयशी तोंडओळख करून घेते असले विनोद करणाऱ्या व्यवस्थेने हे जाणून घेतले पाहिजे की, या एआयने काळ्या मातीतदेखील फोफावायला सुरुवात केली आहे. कालभैरव ही जशी तंत्रशास्त्राची प्रमुख देवता मानली जाते, त्याचप्रमाणे नव्या तंत्रज्ञानाचा प्रमुख घटक एआय आहे. त्याला प्रसन्न करून घेण्यासाठी सर्वोत्तम, सर्वांगीण पद्धती कशा निवडायच्या यावर सार्वकालिक विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा सर्वस्व विसरून, 'आई-आई' सोडून 'हरी-हरी' करावे लागेल!!

अन्वयार्थ

नाव पुसून गांधी कसे पुसले जातील?

'मध्यरात्र उलटल्यावर' या कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील चार पुतळे कोणत्या ना कोणत्या जातीपुरते उरल्याची खंत व्यक्त करतात. तेव्हा पाचवा, गांधीजींचा पुतळा म्हणतो की तुमच्या पाठीशी तुमच्या जाती तरी आहेत, माझ्या पाठीशी आहेत त्या फक्त सरकारी कार्यालयातल्या भिंती...पण मोदी सरकार ज्या वेगाने विविध योजनांची नामांतरे करते आहे, ती पाहता या भिंतींवरूनही गांधीजींचे विस्थापन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. योजनांची नावे बदलली तर गांधी हा माणूस इथल्या लोकांच्या मनातून पुसला जाईल, असे खरेच सरकारला वाटत असेल, तर त्याच हेतूने भिंतीवरचे छायाचित्र उतरवायला आणि नव्या 'महात्म्यां'साठी जागा करू द्यायला असा किती वेळ लागणार आहे? त्यामुळे कुसुमाग्रजांच्या कवितेत आहेत, तेवढेही सुदैवी गांधीजी यापुढच्या काळात असतील असे वाटत नाहीत. ते विशिष्ट ठिकाणी प्रातःस्मरणीय असतील, पण लोकांच्या समोर त्यांचे नाव सतत येता कामा नये याचा अट्टहास सतत होत राहील याचीच शक्यता जास्त.

उदाहरण आहे, मनरेगा या योजनेचे. ग्रामीण जनतेला रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) आता 'विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार ॲण्ड आजीविका मिशन' (व्हीबी - जी - राम - जी) असे नामांतर करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे. या नामांतराला आक्षेप घेत काँग्रेसने त्यांच्या काळातील ३२ योजनांची नावे बदलण्यात आल्याची यादीच जाहीर केली आहे.

मोदी सरकारने सुरुवातीलाच नियोजन आयोगाचे नाव बदलून नीती आयोग असे केले. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेत पंतप्रधान कार्यालयाचे नव्याने 'सेवातीर्थ' असे नामकरण केले जाणार आहे. त्याआधी राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या मार्गाचे राजपथ हे नाव बदलून कर्तव्यपथ करण्यात आले. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा ७, रेसकोर्स रोड ऐवजी ७, लोककल्याण मार्ग, असा पत्ता बदलण्यात आला आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळातील 'निर्मल अभियाना'चे स्वच्छ भारत अभियान असे नामांतर करण्यात आले. यूपीए सरकारने शहरांमधील सार्वजनिक परिवहन सेवा अधिक सक्षम करण्याकरिता जवाहरलाल नेहरू नागरी मिशन (जेएनएनयूआरएम) अभियान सुरू करण्यात आले होते. त्याचेही नाव मोदी सरकारने अमृत असे केले. इंदिरा आवास योजनेचे प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचे दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कचे भारतनेट, नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसीचे मेक इन इंडिया, राजीव आवास योजनेचे सरदार पटेल नॅशनल मिशन, राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेचे प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना अशी विविध योजनांची नावे बदलण्यात आली आहेत. दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमचा पुनर्विकास करून त्याचे स्पोर्ट्स सिटी असे नामांतर करण्याची योजना आहे. याशिवाय राजधानी दिल्लीतील औरंगजेब लेनसह काही रस्त्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत. राज्यातही औरंगाबाद, उस्मानाबाद, इस्लामपूर अशी काही शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद, मुगलसराई, फैझाबाद, जलालाबाद अशा काही शहरांची वा जिल्ह्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत.

खरेतर नावे बदलून नेमके काय साध्य होते? औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर हे नामकरण झाले, पण शहराच्या नागरी समस्यांमध्ये तिळमात्र फरक पडलेला नाही. अन्य शहरांमध्ये थोड्या फार प्रमाणात तोच प्रकार. सरकारी योजनांची नावे बदलल्याने त्यातला भ्रष्टाचार कमी झाला, लोकांचा फायदा झाला असेही काही अनुभवास येत नाही. वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याकरिता जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावे असलेल्या योजनेला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले. पण त्यामुळे शहरांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत काडीमात्र फरक पडलेला नाही. रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलल्याने लोकांना सुलभपणे काम मिळेल असे काहीही नाही. उलट या योजनेतील निधी केंद्राने गेल्या दोन वर्षांत कमी केला. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध जातींना खूश करण्याकरिता मंडळे स्थापन करून त्या त्या जातीतील मान्यवरांची नावे दिली. पण या मंडळांना सरकारने निधीच उपलब्ध करून दिला नाही.

तर नावांचे आणि ती देण्याचे वा बदलण्याचे हे असे आहे. एखाद्याचे नाव पुसून टाकल्याने त्याचा इतिहास बदलला जाईल असे नाही. गांधींच्या बाबतीत तर अजिबातच नाही. त्यांचा खून केल्याने त्यांचे नाव संपले नाही, तर त्यांच्या नावे असलेल्या एका योजनेचे नाव बदलल्याने गांधी कसे संपणार? 'असा एक माणूस या भूतलावर होऊन गेला, यावर पुढच्या पिढ्यांना विश्वास ठेवणे कठीण जाईल', असे गांधीजींबाबत खुद्द आइनस्टाइननेच म्हटले होते, ते कसे विसरता येईल?

आइनस्टाइनचे जाऊ द्या, पण जे दुसऱ्याचे नाव पुसू पाहतात, त्यांचेही नाव पुसणारे उद्या कुणीतरी येणार असते, इतिहास उद्या त्यांनाही हाच न्याय लावणार असतो, हे कसे विसरता येईल?

विश्लेषण

रशियाकडून सुखोई-५७, एस-५०० यंत्रणा खरेदीचे काय झाले?

डॉ. प्रसाद श. कुलकर्णी
prasad.kulkarni@expressindia.com

> **चीन-पाकिस्तानचे दुहेरी आव्हान, भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर अमेरिका सातत्याने उपस्थित करीत असलेले प्रश्न आणि रशियातून खरेदीला असलेल्या मर्यादा यावर आत्मनिर्भरता हेच उत्तर असून, मोहीम म्हणून देशपातळीवर ती राबवायला हवी.**

तज्ज्ञांचा अंदाज का चुकला?

कुठल्याही देशाचा राष्ट्रप्रमुख अन्य देशाच्या दौऱ्यावर जातो, त्या वेळी दोन्ही देशांत नेमके कुठले करार होणार, चर्चेत साधारण कुठले मुद्दे असणार यांसह संपूर्ण दौऱ्याची रूपरेषा ठरलेली असते. पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यात एस-५०० किंवा सुखोई-५७ लढाऊ विमानांच्या बाबतीतील हे करार होणार होते आणि ते आल्यानंतर हे करार झाले नाहीत, असे काहीही नाही. या बाबतीत तज्ज्ञांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा अंदाज चुकला, हे मान्य करायला हवे.

सुखोई-५७ साठी रशियाचा आग्रह का?

भारताची लढाऊ विमानांची गरज पाहता रशियाने भारताला सुखोई-५७ लढाऊ विमाने देऊ केली आहेत. दुबई हवाई शो दरम्यान रशियाच्या रॉस्टेक कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्जी केमझोव्ह यांनी तंत्रज्ञान हस्तांतर, देशांतर्गत उत्पादन यांसह भारताच्या ज्या काही मागण्या असतील, त्या रशियाला मान्य आहेत, असे विधान केले होते. पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी १५ दिवस आधीचेच हे विधान. रशियाबरोबरच अमेरिकेनेही एफ-३५ हे लढाऊ विमान भारताने घ्यावे असा आग्रह धरला आहे. मात्र, अमेरिकेच्या अटी-शर्ती आणि विमानाची एकूण किंमत पाहता भारताला हे विमान घेणे परवडणारे नसल्याचे चित्र आहे.

नेमकी समस्या काय?

हवाई दलाने सात वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१८ मध्ये सुखोई-५७ची कामगिरी अपेक्षित होती तशी नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर या विमानांच्या खरेदी प्रकल्पातून भारत बाहेर पडला. भारताच्या हवाई दलाची क्षमता पाहता आणि विशेषतः 'ऑपरेशन सिंदूर' झाल्यानंतर तात्पुरती व्यवस्था म्हणून या विमानांच्या खरेदीचा पुन्हा विचार करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात कुठल्याही प्रकारची खरेदी झाली नाही. रशियाचे युक्रेनबरोबर गेला बराच काळ सुरू असलेले युद्ध, अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर लादलेले निर्बंध आणि रशियातून भारत खरेदी करीत असलेल्या उत्पादनांसंदर्भात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने घेत असलेली जाहीर भूमिका यांची पार्श्वभूमीही भारत-रशियामधील संभाव्य संरक्षण क्षेत्रामधील साहित्य खरेदीला आहे.

अधिकृत, जाहीर भूमिकेची गरज का?

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुंतागुंतीची स्थिती, विविध आयुधांच्या खरेदी करण्यामधील मर्यादा आणि दुसरीकडे देशांतर्गत हवाई शक्ती, हवाई संरक्षण अधिक सक्षम करण्याचे आव्हान यामध्ये संतुलन साधताना आणि या समस्येतून मार्ग काढताना जाहीर भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यातूनच ती कोंडी सुटेल. रशिया हा भारताचा दीर्घ काळ मित्र राहिला आहे. अमेरिकेचा त्या बाबतीतला इतिहास फारसा उत्साहवर्धक नाही. मुत्सद्देगिरीतून राष्ट्रीय गरजा आणि राष्ट्रहिताची जपणूक वेळेत झाली, तरच त्याला अर्थ असतो. अन्यथा त्यावर प्रश्न उपस्थित होत राहतात. आत्मनिर्भरतेची भूमिका आपण घेतली असली, तरी त्याकडे ज्या तऱ्हेचा जोर देण्याची गरज आहे, तितका दिला जात असल्याचे चित्र दिसत नाही. हवाई दलाच्या आणि हवाई शक्तीच्या गरजा या मोठ्या आहेत. यावर सरकारी स्तरावरून जाहीर भूमिका सर्वांसमोर येणे अतिशय गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या दाव्यांतून आणि विविध अंदाजांतून, सूत्रांच्या हवाल्याने त्या समोर येत राहणे हितावह नाही.

आत्मनिर्भरता हेच उत्तर?

आंतरराष्ट्रीय भूराजकीय स्थिती आणि भारताच्या राष्ट्रीय गरजा पाहता आताच्या परिस्थितीत भारतासमोर मोठे धोरणात्मक आव्हान उभे राहिले आहे. राजनैतिक पटलावर यातून मार्ग काढताना तारेवरची कसरत निश्चितच करावी लागत आहे. या सर्व समस्येवर उत्तर हवे असेल, तर ते संरक्षणामध्ये आत्मनिर्भरतेचे आहे. चीन-पाकिस्तानचे दुहेरी आव्हान, भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर अमेरिका सातत्याने उपस्थित करीत असलेले प्रश्न आणि रशियातून खरेदीला असलेल्या मर्यादा यावर आत्मनिर्भरता हेच उत्तर असून, एक मोहीम म्हणून याबाबत देशपातळीवर ती राबवायला हवी. हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या बाबतीतही, देशी बनावटीच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणेला आणखी बळ द्यायला हवे. तेजससारखी आणखी लढाऊ विमानेही स्वदेशात इंजिनासह तयार व्हायला हवीत. त्यासाठी उद्दिष्ट आणि वेळ ठरवून काम होणे गरजेचे आहे.

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

घर गिराने पर रोक

उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग के घर को गिराने की कार्रवाई पर रोक के गहरे अर्थ हैं। अदालत ने इतनी सर्दी में किसी घर को गिराने के कदम को उचित ही अमानवीय माना है। वैसे भी, अवैध रूप से निर्मित इमारतों को गिराने के तय कायदे-कानून हैं, जिनके पालन में चूक नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है, मई में नैनीताल में घटी दुष्कर्म की उस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था और उग्र भीड़ ने कई दुकानों व रेस्तरां में जमकर तोड़-फोड़ कर दी थी। स्थानीय नगरपालिका परिषद ने तब आनन-फानन में आरोपी के घर पर अवैध रूप से बने होने का नोटिस चस्पां कर उसे तीन दिन में खाली करने की चेतावनी जारी की थी, ताकि उसे गिराया जा सके, मगर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से उस समय भी प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। नगरपालिका परिषद के अधिकारियों ने माना था कि अवैध निर्माण को गिराने के जो मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, उनके मुताबिक नोटिस नहीं था और इसलिए उसे वापस ले लिया गया था। उसके बाद जिला प्रशासन ने तय मानकों के अनुरूप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया।

उत्तराखंड में इस प्रशासनिक तत्परता के पीछे जो भी वजहें तलाशी जाएं, मगर सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण और अवैध निर्माण की कतई हिमायत नहीं की जा सकती और स्थानीय प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्रवाई करने का पूरा अख्तियार है। उसे कार्रवाई करनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्माणों ने हमारे तमाम शहरों-कस्बों में एक अराजक स्थिति बना दी है। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, जब केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड सरकार को आगाह किया था कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन, अतिक्रमण व गैर-कानूनी निर्माण उसकी कुदरती आपदा की विभीषिका को बढ़ा रहे हैं और इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। जाहिर है, अधिकारियों की मिलीभगत से ही लोगों ने पहाड़ी इलाकों में ऐसे निर्माण किए हैं, मगर खामियाजा सिर्फ उन्हें ही भुगतना पड़ता है, जबकि अधिकारी प्रायः बच निकलते हैं।

नहीं भूलना चाहिए कि अतिक्रमण के आरोपी भी देश के नागरिक हैं और कंपकंपाती सर्दी या बरसात में उनके घरों पर बुलडोजर का इस्तेमाल कभी मजबूत आधार नहीं पा सकता।

उत्तराखंड ही नहीं, बिहार में भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और सरकारी भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। ऐसी किसी भी कार्रवाई में प्रशासनिक सख्ती के साथ संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दिशा-निर्देश में साफ कहा था कि यदि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाता है, तो इसके क्रियान्वयन से पहले 15 दिन का समय दिया जाए, जिससे संपत्ति के मालिक को अवैध ढांचे को हटाने या ध्वस्तीकरण के आदेश को अदालत में चुनौती देने का मौका मिल सके। तंत्र में बैठे लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अतिक्रमण के आरोपी भी इसी देश के नागरिक हैं और कंपकंपाती सर्दी या बरसात में उनके घरों पर बुलडोजर का इस्तेमाल कभी मजबूत नैतिक आधार नहीं पा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा-निर्देश में यह भी कहा था कि यदि सिर्फ एक इमारत को ध्वस्त किया जाता है, जबकि समान हालात के दूसरे ढांचों को अछूता छोड़ दिया जाता है, तो इसका अर्थ यही होगा कि कार्रवाई का उद्देश्य आरोपी को दंडित करना है, न कि अवैध निर्माण को हटाना। उत्तराखंड के आरोपी परिवार की भी यही शिकायत है कि सिर्फ उसे निशाना बनाया गया है, जबकि दूसरे घरों को बख्श दिया गया, जबकि वे भी उसी कथित सरकारी भूमि पर बने हैं। स्पष्ट है, ऐसे मामलों में प्रशासन को अतिरिक्त सवाधानी बरतनी चाहिए।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

17 दिसम्बर, 1950

अशुभ पखवाड़ा

पिछले दो सप्ताह भारत के लिए बहुत ही अशुभ सप्ताह रहे। भारत की एक आध्यात्मिक विभूति श्री अरविन्द के अवसान के बाद ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक अडिग सेनानी तथा देश की एकता के निर्माता सरदार पटेल ऐसे समय में चल बसे, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संकटपूर्ण स्थितियों को देखते हुए उनकी अत्यधिक आवश्यकता थी।

प्रधानमंत्री नेहरूजी ने संसद में अपने शोकोद्गार प्रगट करते हुए कहा: उनके महान जीवन की कहानी समाप्त हो गई। हम सब तथा सारा देश जानता है कि यह एक बड़ी कथा है। इतिहास उसे अपने अगणित पृष्ठों पर अंकित करेगा तथा उन्हें नव भारत का निर्माता और संगठनकर्ता के नाम से पुकारेगा।' इस तरह राष्ट्रपति ने श्मशानभूमि में कहा: 'सरदार के शरीर को अग्नि भस्मीभूत कर रही है, किंतु कोई अग्नि उनके यश को नहीं समाप्त कर सकती।' शारीरिक दृष्टि से सरदार पटेल की मृत्यु हो गई किंतु राष्ट्र के लिए उनकी आत्मा अब भी पथ-प्रदर्शक का कार्य कर सकती है, बशर्ते डा. राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में हम यह समझें कि 'सारा राष्ट्र उनका परिवार है। अतएव हमें देश की सेवा का वैसा ही प्रण करना चाहिए जैसा कि उन्होंने किया था।'

सरदार पटेल के निधन का समाचार पाकर करोड़ों देशवासियों को जो धक्का लगा है तथा देश जिस प्रकार शोकाकुल हो उठा है, वह स्वाभाविक है; किंतु अपने नेता के प्रति वास्तविक श्रद्धा हम तभी प्रगट कर सकते हैं, जब उनके चरण-चिह्नों पर चलें। राजाजी के इन शब्दों को हमें याद रखना चाहिए 'वल्लभभाई महान स्फूर्ति, साहस और आत्म-शक्ति के अवतार थे। हम यह न सोचें कि वह नहीं रहे। हमारे परिचित वल्लभभाई के चले जाने पर भी सच्चे वल्लभभाई सदैव जीवित रहेंगे। मौलाना आजाद का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि एक शानदार इन्कलाब की दास्तान खत्म हो चुकी किंतु 'जिस दुनिया में हम चलते-फिरते हैं, उसमें वह दास्तान खत्म हुई है मगर दिमागों और दिलों की दुनिया में वह दास्तान हमेशा जिन्दा रहेगी और याद की जायेगी।'

संसद का कार्य: सरदार पटेल के निधन से संसद में शुक्रवार को कोई कार्य न हुआ और वह सोमवार के लिए स्थगित हो गई।

भाजपा ने फिर किया नवीन प्रयोग

भारतीय जनता पार्टी में इसे पीढ़ीगत बदलाव कहा जा रहा है। 45 साल के नितिन नवीन पार्टी के साथ ही बड़े हुए हैं, यानी 1980 में जन्मी अपनी पार्टी की उम्र के अध्यक्ष।

यहां स्कैन करें

विजय त्रिवेदी | वरिष्ठ पत्रकार

दिल्ली में दिसंबर की सर्दियों की सुबह कोहरे की चादर में लिपटी रहती है। कई बार तो इतनी धुंध रहती है कि करीब से भी तस्वीर साफ नहीं दिखती। इसका अर्थ यह नहीं कि तस्वीर उजली और बेहतर न हो; भरोसा इतना मजबूत नहीं होता, फिर जैसे-जैसे दिन चढ़ने लगता है, बहुत सी चीजें साफ होने लगती हैं और आपको नजारे साफ-साफ नजर आने लगते हैं।

एक लंबे इंतजार के बाद जब अचानक दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का एलान करती है, तो उस दिन भी राजनीतिक कुहासा गहरा रहता है। ऐसे अचानक कभी हुआ नहीं, पहले कभी होता नहीं था, फिर लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, चर्चाएं चल रही थीं, हर कोई अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। कुछ बड़े विद्वानों को हमेशा की तरह यह चयन पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच उलझे समीकरणों में फंसा हुआ दिख रहा था, ऐसे परिदृश्य में संगठन के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के एलान की विज्ञप्ति जारी होती है राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के दस्तखत के साथ। उसके साथ ही प्रधानमंत्री और पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तीन देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो जाते हैं।

मुझे याद नहीं पड़ता कि पार्टी के सर्वोच्च पद का एलान पहले कभी ऐसे हुआ हो। आमतौर पर नए अध्यक्ष का एलान पुराने अध्यक्ष अपने साथ नए नेता को बुलाकर करते रहे हैं। फिर नाम भी राष्ट्रीय राजनीति के नजरिये से बिल्कुल नया- नितिन नवीन। बिहार सरकार में मंत्री। राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर उन्होंने संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। खैर, इन सब बातों का मतलब नितिन नवीन की योग्यता पर सवाल उठाना नहीं है। उन्हें तो अब अपनी योग्यता साबित करनी है और उन लोगों को मजबूती से जवाब देना है, जो इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नए अध्यक्ष का पहला इम्तिहान तो कुछ महीनों में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही हो जाएगा, लेकिन यह उनके साथ ज्यादती होगी। इतनी जल्दी उनके इम्तिहान की जरूरत नहीं है। कोहरे से भरे दिन को खुलने दीजिए, थोड़ी धूप निकलने दीजिए।

भारतीय जनता पार्टी में इसे पीढ़ीगत बदलाव कहा जा रहा है। 45 साल के नवीन बाबू पार्टी के साथ ही बड़े हुए हैं, यानी 1980 में जन्मी बीजेपी की उम्र के अध्यक्ष। कुछ लोग इस पर ऐतराज कर सकते हैं कि उन्हें 'कार्यकारी अध्यक्ष' की जिम्मेदारी ही मिली है अभी, लेकिन मुझे वह अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष लगते हैं, सिर्फ चुनावी औपचारिकता पूरी होने की देर है। यह पीढ़ीगत बदलाव और दिल्ली की चकाचौंध वाली राजनीति में बिहार से किसी आम कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े नेता को जिम्मेदारी देने का एक साहसिक फैसला माना जा सकता है, जो हिम्मत दूसरी पार्टियां नहीं दिखा पाती। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में तो सिर्फ परिवार ही नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने भी ऐसी कोई पहल नहीं की, जबकि देश में करीब 21 करोड़ नौजवान वोटर हैं।

भाजपा में पीढ़ीगत बदलाव की हवा पिछले दिनों राज्यों में बनाए गए मुख्यमंत्रियों से भी महसूस होती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत, असम में हिमंता बिस्वा सरमा, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, दिल्ली में रेखा गुप्ता जैसे नाम इस लिहाज से गिनाए जा सकते हैं। इसलिए नितिन नवीन की काबिलियत पर सवाल खड़े करना बेमानी-सा है। हो सकता है कि वह पार्टी को किसी दूसरे स्तर पर ले जाएं, जैसे अमित शाह के कार्यकाल में भाजपा न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बल्कि अपने दम पर वह लोकसभा में 303 सांसदों वाली पार्टी भी बन गई। सन् 1984 में दो सांसदों से साल 2019 में 303 सांसदों की ताकत!

बहरहाल, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पिछले छह महीने से 20 युवाओं पर काम कर रही थी, उसमें से पांच को 'शॉर्टलिस्ट' किया गया था और फिर नवीन बाबू के नाम पर मुहर लगी, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ चुनाव में अच्छा काम किया था। कुछ कयासबाजों के मुताबिक, नवीन का चयन उन लोगों को करारा जवाब है, जो बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा नेता न होने की बात करते रहे हैं। इस दलील को मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा ही था, तो फिर सरसंघचालक मोहन भागवत ने क्यों कहा कि हमें अध्यक्ष तय करना होता, तो इतना समय लगता क्या? अगर नवीन बाबू का चयन हो ही गया था, तो महीने भर पहले उन्हें बिहार में मंत्री क्यों बनाया गया, कम से कम उप-मुख्यमंत्री बनाए जाते?

आशंकावीर यह तक संदेह जता रहे कि पीढ़ीगत बदलाव के बहाने क्या मौजूदा नेतृत्व अपने समकालीन ताकतवर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में धकेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ताकि किसी चुनौती का संकट नहीं रहे? वैसे भी, लोकतंत्र का मायने चुनाव होता है, चयन नहीं। यह प्रक्रिया अब दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी में भी लगभग बंद हो गई है। अब सामूहिक नेतृत्व की बात दिखावे के लिए भी नहीं होती, एक ही ब्रह्म है। एक नेता, एक आदेश। संसदीय बोर्ड की बैठकों और संसदीय दल व विधायक दलों की बैठकों में नेता के चुनाव की औपचारिकता को खत्म कर दिया गया है। पार्टी के पर्यवेक्षक बैठक में पर्ची खोलकर आलाकमान के फरमान को सुनाते हैं। कई बार तो शायद पर्ची खोलने वाले को भी उसके भीतर लिखे नाम का पता नहीं होता। यह सच है कि प्रयोगधर्मिता नेतृत्व की ताकत होती है और उसमें गलती की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन गलती पर सवाल उठाने की जगह नहीं बचे, तो अनुशासन और मनमानी के बीच की बारीक रेखा धुंधली हो जाती है।

नए अध्यक्ष नितिन नवीन को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी टीम बनानी है। जाहिर है, यह काम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर ही पूरा करना होगा। क्या वह अपनी टीम में अपने से ज्यादा अनुभवी और बेहतर लोगों को शामिल करेंगे, ताकि पार्टी को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिले? नवीन बाबू के लिए कई बॉस हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह के अलावा जे पी नड्डा और संघ परिवार, क्या इन सबकी परिक्रमा से समय निकाल पाएंगे वह संगठन के लिए? यह हिम्मत और फैसला उनकी जगह तय करेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

उच्च शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने का गंभीर प्रयास

यहां स्कैन करें

बद्री नारायण | कुलपति, टीआईएसएस, मुंबई

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल-2025' पेश कर दिया है। यह बिल अभी संसदीय विमर्श की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, इसलिए इसके प्रभावों पर विचार करने का यही उचित समय है। इसे पेश करते वक्त इसके अनेक सकरात्मक परिणामों की चर्चा की गई, पर शिक्षा जगत में इसे लेकर कुछ उलझनें भी हैं, जिनकी थोड़ी अभिव्यक्ति मीडिया विमर्शों में दिख रही है।

समाज जैसे-जैसे जटिल होता जाता है, शिक्षा के संचालन की प्रक्रियाएं भी जटिल होती जाती हैं, इसलिए जरूरी होता है कि समय-समय पर इसके ढांचों में जरूरी परिवर्तन किए जाएं। गुलाम भारत में शिक्षा संचालन का एक ढांचा था। आजादी के बाद एक नया ढांचा विकसित किया गया, जो एक प्रकार से औपनिवेशिक ढांचे से देश को मुक्त करने की कोशिश थी। मगर यह मकसद एक बार के सुधारों से पाना मुश्किल था, इसलिए समय और जरूरतों के हिसाब से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाते रहे हैं। नई शिक्षा नीति-2020 इसी क्रम में भारतीय शिक्षा को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के एक बड़े प्रयास के रूप में सामने आई।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल-2025 देश में कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं विचार शक्ति, तीनों को विकसित करने में सहायक है।

साफ है, भारत की उच्च शिक्षा अभी कई बड़े रूपांतरणों से गुजर रही है। इसे एक प्रकार से भारतीय युवा वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति-उत्तर के रूप में भी देखा जा सकता है। भारतीय युवा वर्ग की, जिनकी संख्या 37 करोड़ के आस-पास है और जो देश के विकास का सबसे प्रभावी उत्तोलक भी है, क्षमता-वृद्धि और ज्ञान के विकास की जिम्मेदारी हमारी उच्च शिक्षा पर है। यह वर्ग अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहता है, जो त्वरित, आसान और गुणात्मक हो।

दूसरी बात, भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में, हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें प्रक्रियाओं का संजाल न हो और शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं हम तक आसानी से पहुंच सकें। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल- 2025 ऐसी ही व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को भ्रम संजाल, कई जरूरी प्रस्तावों में विलंब की परिपाटी और अनेक खंडों में खंडित संचालन-व्यवस्था से मुक्ति मिल सकेगी।

अभी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें अनेक नियामक संस्थाएं कार्यरत हैं। संचालन, मानकीकरण और गुणात्मकता अवलोकन के लिए कार्यरत संस्थाओं में ऑर्गेनिक संबंधिता की कमी है। लिहाजा, इस बिल से जो ढांचा उभरेगा, उसमें शिक्षा व्यवस्था की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाना संभव हो सकेगा। यूजीसी, एआईसीटीई जैसी कई नियामक संस्थाओं के संजाल से मुक्ति दिलाकर एक अत्यंत पारदर्शी तकनीक-आधारित नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन संभव है। फंडिंग से लेकर उच्च शिक्षा संस्थाओं के मूल्यांकन, नामांकन, संस्थानों को खोलने की अनुमति तक- सबमें अभी जो विलंब होता है, उससे छुटकारा मिल सकेगा।

इस अधिनियम के तहत तीन स्वतंत्र परिषदें बनाने का प्रस्ताव है, जो मानकीकरण, विनियमीकरण और मान्यता देने का काम करेंगी। इन संस्थाओं को फंडिंग, वितरण एवं संचालन जैसे कामों से दूर रखा जाएगा। यह एक सुचिंतित कदम है, क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया है कि यूजीसी का ज्यादा समय वित्त संचालन में जाया होता था। नए बिल से जो व्यवस्था बनेगी, उससे अति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने की आशंका जरूर जताई गई है, पर इससे अनेक स्तरों पर अनुमति के संजाल, शिक्षा के संचालन में निहित भ्रम के तत्व और प्रशासनिक जटिलताओं को सरल बनाने में ही मदद मिलेगी। इससे छात्रों के शैक्षिक जीवन में विलंब तो खत्म होगा ही, डिजिटली शक्तिवान युवाओं के लिए उच्च शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं बिना किसी दोष के सुलभ रहेंगी। यह उन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़ पाएगा।

जाहिर है, यह बिल अगर संवेदनशील और प्रभावी ढंग से व्यवहार में उतारा जाए, तो इससे ऐसी शिक्षा व्यवस्था बन सकेगी, जो देश में कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं विचार शक्ति, तीनों को विकसित करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए यह किया जाना जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

संतुलन से ही शांति

सृष्टि की अभिव्यक्ति तीन स्तरों पर होती है- स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल जगत वह है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जैसे प्रकृति, शरीर और भौतिक वस्तुएं। यह संसार परम पुरुष की ही अभिव्यक्ति है और उनकी मधुरता से परिपूर्ण है। इसके पीछे जो सूक्ष्म जगत है, वह विचार, भावना, संवेदना और चेतना का क्षेत्र है। जो कुछ हमें भीतर से प्रेरित करता है, जो सोचने-समझने और अनुभव करने की शक्ति देता है, वही सूक्ष्म जगत है। यह परम पुरुष के और गहरे माधुर्य की झलक है।

इन दोनों के मूल में कारण जगत स्थित है। यही वह स्तर है, जहां से सृष्टि की सारी संभावनाएं जन्म लेती हैं। कारण जगत में परम पुरुष का रूप अत्यंत कोमल, शांत और आनंदमय है। उनका हंसता हुआ रूप उनकी इच्छा के अनुसार निरंतर परिवर्तनशील रहता है और पूरे ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश और चेतना का प्रसार करता है। परम पुरुष ही तीनों लोकों के मूल कारण और बीज हैं। जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह उसी एक सत्ता से उत्पन्न हुआ है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है।

इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई सत्ता नहीं है, जिसके आगे मनुष्य अपना सब कुछ अर्पित कर सके। जब मनुष्य स्वयं को सिर्फ सांसारिक सुखों के हवाले कर देता है, तो अंत में उसका जीवन खालीपन, अशांति और असंतोष से भर जाता है। सांसारिक उपलब्धियां क्षणिक आनंद तो दे सकती हैं, पर स्थायी सुख नहीं दे सकतीं। स्थायी सुख तभी संभव है, जब मनुष्य स्वयं को परम पुरुष को समर्पित करे। यह समर्पण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य अपने सीमित 'मैं' को छोड़कर विराट सत्ता से जुड़ता है, तभी उसके जीवन में सच्चा संतुलन आता है।

सभी गतियों, प्रयासों और खोजों का अंतिम बिंदु वही परम पुरुष हैं। जीवन की हरेक यात्रा, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, अंततः उसी केंद्र की ओर जाती है। मानसिक और आध्यात्मिक साधना के मार्ग को चार चरणों में समझा जा सकता है- यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकरण। जब मन कभी स्थूल और कभी सूक्ष्म की ओर भटकता रहता है, तब वह यतमान अवस्था में होता है। यह खोज और अस्थिरता की स्थिति है, जहां साधक सही दिशा की तलाश में रहता है।

समर्पण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य अपने सीमित 'मैं' को छोड़कर विराट सत्ता से जुड़ता है, तभी उसके जीवन में सच्चा संतुलन आता है।

जब मनुष्य लाभ-हानि से ऊपर उठकर आंतरिक आनंद की ओर बढ़ने लगता है, तब व्यतिरेक अवस्था में प्रवेश करता है। जब आनंद चांदनी रात की रोशनी की तरह पूरे मन को भर दे और चेतना एक बिंदु पर टिकने लगती है, तब वह एकेंद्रिय अवस्था कहलाती है। जब साधक साधना द्वारा सभी इच्छाओं को शांत कर पूर्णता में स्थित होने के अभ्यास करता है, तो वह वशीकरण अवस्था होती है। वहां जीवन शिवमय हो जाता है।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

एंथनी अल्बनीज | प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया

आतंकवाद के खिलाफ एक साथ आना हम सबके लिए जरूरी है। संघीय और राज्य सरकारें यहूदी लोगों को सुरक्षा देने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। हमारी पुलिस के पास बहुत काम है, लेकिन हम हमेशा उनके साथ रहेंगे।

अनुलोम-विलोम

ऑस्ट्रेलिया में गोलीबारी

जेहादी आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती

ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला केवल एक देश या समुदाय पर हमला नहीं था, बल्कि यह आधुनिक विश्व के लिए एक खौफनाक चेतावनी है कि जेहादी आतंकवाद किसी भौगोलिक सीमा को नहीं मानता। हनुक्का पर्व के अवसर पर जब यहूदी परिवार उत्सव और आस्था के साथ समुद्र तट पर एकत्रित थे, तभी उन पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। हमलावरों की पहचान सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वे कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से प्रेरित थे।

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक घृणा और वैश्विक कट्टरपंथ किस हद तक मानवता के खिलाफ खड़ा हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस हमले को आतंकवादी कृत्य घोषित किया, पर उस पर यह आरोप भी लगे कि उसने पहले से सक्रिय चरमपंथी इस्लामी गुटों को हल्के में लिया। यह हमला गाजा में हमास और इजरायल के बीच चले लंबे संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे साफ होता है कि मध्य-पूर्व की आग अब पश्चिमी देशों की सड़कों तक पहुंच चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि वैश्विक समुदाय आज भी आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा तय नहीं कर पाया है और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि आतंकवादी संगठनों को संरक्षण, फंडिंग और वैचारिक समर्थन देने वाले देशों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे देशों में पाकिस्तान का नाम बार-बार सामने आता है, जहां आतंकवाद को कभी 'रणनीतिक संपत्ति', तो कभी 'राजनीतिक हथियार' के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

आतंकवाद की सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि इसके सहयोगी केवल जंगलों या सीमापार ठिकानों में छिपे नहीं होते, बल्कि समाज के भीतर बैठे रसूखदार लोग, धनदाता, वैचारिक समर्थक और राजनीतिक संरक्षक भी होते हैं। केवल हमलों की निंदा करने से आतंकवाद नहीं रुक सकता। इसके लिए विश्व समुदाय को दिखावटी नैतिकता से बाहर निकलकर ठोस इच्छाशक्ति दिखानी होगी, आतंक को पालने वाले देशों को अलग-थलग करना होगा और उनके खिलाफ वास्तविक आर्थिक व कूटनीतिक कार्रवाई करनी होगी। इतना ही नहीं, जनता को भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कट्टरपंथ की पहली पहचान अक्सर आसपास के व्यवहार, भाषा और सोच में दिखाई देती है। जब तक आतंकवाद के समर्थकों, संरक्षकों और विचारधारात्मक पोषकों को चिह्नित करके कुचला नहीं जाएगा, तब तक ऑस्ट्रेलिया जैसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती रहेंगी।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

आतंकी घटनाओं को धर्म की नजर से न देखें

सिडनी ने अपने हीरो अहमद अल अहमद को सिर्फ सलाम नहीं किया, उसके साहस और इंसानियत की सराहना के लिए कई मिलियन डॉलर भी जुटा लिए। अहमद ने बिना डर के, गोलियों के सामने हमलावर को निहत्था किया और कई जिंदगियां बचाईं। बहादुरी का कोई धर्म नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमला हुआ। हमलावर मुसलमान था। फौरन उसे धर्म से जोड़कर पेश किया गया। मगर अहमद ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे रोका। लोगों को बचाया। वह मुस्लिम नहीं, हीरो बन गया। अगर मुस्लिम अपराध करे, तो उसका धर्म दोष बन जाता है। अगर वही इंसानियत दिखाए, तो धर्म छुप जाता है। अहमद ने डर और नफरत के सामने खड़े होकर जिंदगियां बचाईं। पूरा ऑस्ट्रेलिया जान गया कि बहादुरी का कोई धर्म नहीं। अमेरिका को देखें। स्कूलों में बच्चों को मारने वाले ज्यादातर गोरे पुरुष हैं। गोरों को कभी 'आतंकवादी' नहीं कहा गया। बस 'डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल' कहा गया। यह दोहरा मापदंड है। पिछले दो साल से फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। वे ज्यादातर मुस्लिम हैं। पीड़ित समुदाय आतंकवादी बना दिया जाता है, पर बम गिराने वाले का आतंकी नहीं माना जाता। सोचिए, इन सबसे किसे फायदा होता है? यही खेल है। इस सूरतेहाल में अहमद सिर्फ नाम नहीं, एक जवाब है- नफरत के खिलाफ, झूठे नैरेटिव के खिलाफ, इंसानियत के साथ। सच हमेशा यही रहा है- आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मगर सत्ता हमेशा धर्म चुन लेती है, जिसे दोषी ठहराया जा सके।

अपूर्व भारद्वाज, टिप्पणीकार

अधिकतर मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, फिर भी विश्व में उन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता है, आखिर क्यों? कहीं आतंकी घटना हुई नहीं कि लोग उसमें धर्म के तत्व ढूंढ़ निकालते हैं। यह गलत है। हमें आतंकवादियों को निशाना बनाना चाहिए, न कि आतंकियों के बहाने उसके धर्म को। अगर हम किसी घटना को धर्म के चश्मे से देखेंगे, तो कहीं न कहीं उस धर्म के प्रति समाज में नफरत फैलाने में मददगार माने जाएंगे। इससे समाज में वैमनस्य और बढ़ेगा। अगर इस्लाम आतंकवादी सोच का ही पोषण करने वाला धर्म है, तो ऑस्ट्रेलिया में आतंकियों से सीधे टकराने वाले अहमद का धर्म भी जरा जान लीजिए। वह भी इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक आतंकी से हथियार छीन लिए और कई जिंदगियां बचा ली। हमें यह समझना होगा कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग राह से भटके हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की मानसिकता का इलाज करना है।

प्रतीक कुमार, टिप्पणीकार

हवा पर हावी जहर को जानिए

प्रदूषण का कहर साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि लोग प्रदूषण को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। खराब हवा के प्रति लापरवाही का भाव हर जगह दिखता है। क्या हम हवा में फैले जहर को पहचान या जान नहीं पा रहे हैं? क्या हमें अंदाजा नहीं है कि प्रदूषित हवा हमारे स्वास्थ्य के साथ कैसे-कैसे खिलवाड़ कर रही है? पेश है प्रदूषण का व्यापक जायजा लेती जसजीव गांधीओक की खास रिपोर्ट...

दिल्ली में कम से कम तीन वायु गुणवत्ता मापक केंद्रों पर वायु की गुणवत्ता (एक्यूआई) कई बार 500 के पार तक चली जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी के 39 वायु निगरानी केंद्रों में से 38 या तो गंभीर या अति गंभीर श्रेणी में चल रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा चलाए जा रहे वजीरपुर, रोहिणी और अशोक विहार केंद्रों पर 24 घंटे की औसत वायु गुणवत्ता इंडेक्स 500 तक पहुंच जा रही है। ध्यान देने की बात है कि कुछ एक्यूआई मापक यंत्र 500 से ज्यादा का माप नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाती है। बीते रविवार की बात करें, तो कम से कम 13 केंद्रों पर रविवार को कई घंटों तक एक्यूआई का स्तर 490 से ऊपर रहा और कई जगहों पर तो यह लगभग सर्वोच्च स्तर पर बना रहा।

यहां यह दोहरा देना चाहिए कि 51 से 100 तक एक्यूआई को संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब और 400 से ज्यादा को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग बताते हैं कि हवा घने कोहरे जैसी लग रही है और बाहर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 16 में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के 53 वर्षीय अध्यक्ष नवीन गर्ग बताते हैं कि घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में लोग सुबह जल्दी बाहर निकलने के बजाय सुबह करीब 9-10 बजे टहलने के लिए घरों से निकल रहे हैं।

एनवायरोकैटाल्टि्सस नामक थिंक टैंक के संस्थापक और प्रमुख विश्लेषक सुनील दहिया बताते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि लंबे समय तक 5 ग्राम/ प्रतिमीटर से ज्यादा पीएम2.5 स्तर के संपर्क में रहने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अभी हम जो सांस ले रहे हैं, वह 500 ग्राम/ प्रतिमीटर से ज्यादा पीएम2.5 स्तर है। इससे तरह-तरह के रोगों को बढ़ने का मौका मिलता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के कार्यक्रम प्रमुख मोहम्मद रफीउद्दीन ने चेतावनी दी है कि ऐसे बुरे प्रदूषण स्तर के संपर्क में थोड़े समय तक भी रहना खतरनाक हो सकता है। लोगों को हर हाल में मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे वायु प्रदूषण स्तर के संपर्क में थोड़ा समय भी रहने से परेशानियां हो सकती हैं।

हवा में कितना जहर है, इसका सही आकलन जरूरी है, लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली एक बार फिर राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति का सही अनुमान लगाने में विफल हो रही है। इससे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की समय पूर्व कार्रवाई करने की क्षमता में रुकावट आ रही है। प्रदूषण को लेकर चेतावनी और पूर्वानुमान को सुधारने की जरूरत है, ताकि लोगों के शरीर में प्रदूषण का जहर कम से कम पहुंचने पाए। तमाम विशेषज्ञ यह मानते हैं कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई बहुत लंबी है और इसके लिए बड़ी योजनाओं की जरूरत है।

सही पूर्वानुमान के आधार पर ही सीएक्यूएम तीन दिन पहले तक ग्रैप चरण 2, 3 और 4 के तहत उपाय लागू कर सकता है, जिससे प्रदूषण के चरम स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पूर्वानुमान गलत है, तो ग्रैप लागू करने में बहुत देर हो जाएगी। उदाहरण के लिए, सीएक्यूएम ने ग्रैप-4 को शनिवार देर रात ही लागू किया, जब स्थिति पहले ही नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में, दिल्ली में रविवार को प्रदूषण खतरनाक रूप से ज्यादा रहा। यह एक बड़ा सवाल है कि हम सही अनुमान लगाने में क्यों नाकाम हो रहे हैं?

अब प्रदूषण संबंधी आंकड़ों को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। सही आंकड़ों के आधार पर ही सही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हवा में यह देखना जरूरी है कि किस तरह के जहर ज्यादा घुल रहे हैं। पहले ज्यादा जहरीले तत्वों के उत्सर्जन को रोकने की जरूरत है।

हवा में जो ज्यादा जहरीले तत्व हैं, उन्हें पनपने से रोकना और एक बार हवा में घुलने के बाद उनका यथोचित समाधान करना जरूरी है। सीपीसीबी एयर प्रयोगशाला के पूर्व अध्यक्ष दीपांकर साहा बताते हैं कि मॉडल पर फिर से गौर करने की जरूरत है। मापांकन ठीक करने और उत्सर्जन सूची को भी अपडेट करने की जरूरत है। दूसरे कारणों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे, पानी छिड़कने से हवा में नमी आती है और आखिर में हवा भारी हो जाती है। तेज हवा न चलने पर ऐसी जहर भरी भारी हवा सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन क्या इस मोर्चे पर हम पर्याप्त जागरूक हैं?

Hindustan Times

फोटो : अरविंद यादव

80 लाख से ज्यादा लोग हर साल दुनिया में वायु प्रदूषण जनित बीमारियों की वजह से जान गंवाते हैं।

40 लाख से ज्यादा लोग हर साल अकेले भारत में वायु प्रदूषण जनित बीमारियों की वजह से जान गंवाते हैं

बच्चों को सबसे अधिक खतरा

छोटे बच्चों के फेफड़े अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वे वयस्कों की तुलना में दोगुनी गति से सांस लेते हैं, जिससे वे हानिकारक प्रदूषकों की अधिक मात्रा ग्रहण करते हैं। आठ वर्ष से कम आयु के बच्चों के फेफड़ों को इससे सर्वाधिक नुकसान होता है, क्योंकि उनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे होते हैं।

दिमाग पर सबसे ज्यादा मार

आज तन ही नहीं, हमारा मन भी खतरे में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क के लोगों के एक समूह पर 2022 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया था कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से अवसाद, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और व्यक्तित्व विकार सहित मानसिक विकारों का खतरा काफी बढ़ जाता है।

हवा में ये जहर

जहरीले कण (एसपीएम)

हवा में घुले सूक्ष्म जहरीले कण फेफड़ों व रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। 2.5 से 10 माइक्रोन आकार के ये कण दिल्ली की वायु में प्राथमिक प्रदूषक हैं।

सेहत पर मार : आंखों में जलन, नाक में जलन, गले में खराश, फेफड़े, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ऊतकों को नुकसान, गुर्दे, यकृत को नुकसान, हृदय रोग। ये भारी कण शरीर के अंदर पहुंचकर कैंसर का भी कारण बन सकते हैं।

नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स)

यह एक तरह से अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैसों का समूह है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हवा में शामिल हो जाता है, तब वातावरण में लाल-भूरा धुंध बना देता है। इस जहरीले तत्व का मुख्य स्रोत – ईंधन दहन और लकड़ी जलाना है। सर्दी में यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है।

सेहत पर मार : फेफड़ों को नुकसान, सांस लेने की क्षमता में कमी और श्वसन मार्ग में सूजन। त्वचा का कैंसर और तंत्रिकाओं को क्षति।

सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2)

यह एक रंगहीन जहरीली गैस है, जो जल वाष्प में घुल कर अम्ल बनाती है। इस गैस – सल्फर डाइऑक्साइड के मुख्य स्रोत ईंधन दहन, विद्युतीय उपकरण और औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं।

सेहत पर मार : इस जहरीली गैस का फेफड़े पर गहरा असर पड़ता है, खांसी, घरघराहट, श्वसन मार्ग में तरह-तरह की समस्या, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।

ओजोन (ओ3)

यह हल्के नीले रंग की गैस है, जिसकी गंध तीखी होती है। यह सूर्य के प्रकाश में अन्य प्रदूषकों की प्रतिक्रिया से बनती है। ऐसे जहरीले तत्व का मुख्य स्रोत ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सफाई का काम होता है।

सेहत पर मार : आंखों पर असर, आंखों से पानी आना, गले में जलन, फेफड़े संबंधी बीमारियां, अस्थमा, सूखी खांसी, फेफड़ों की क्षमता में कमी, दीर्घकालिक श्वसन रोग, श्वसन मार्ग में संक्रमण, सीने में जकड़न इत्यादि।

कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ)

यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, जिसे लंबे समय तक लगातार सांस के जरिए अंदर लेने पर जानलेवा साबित हो सकती है। इसके मुख्य स्रोत वाहनों और इंजनों से ईंधन दहन से निकलने वाले घातक तत्व हैं।

सेहत पर मार : इस जहरीले तत्व का असर आंखों पर पड़ता है। दृष्टि धुंधली हो जाती है। सुनने की क्षमता कम होने लगती है। चक्कर आना, सिरदर्द, सीने में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है।

उत्तर प्रदेश

लखनऊ में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बहुत चिंता नहीं

राजधानी लखनऊ में प्रदूषण की स्थिति जानने के लिए छह केंद्र बने हुए हैं। कुकरैल स्थित केंद्र से इंदिरा नगर और आसपास के प्रदूषण का आकलन हो रहा है। यह केंद्र वन्य क्षेत्र के बीच है। नतीजतन यहां पीएम 2.5 या पीएम 10 का स्तर ज्यादातर ग्रीन जोन में रहता है। अन्य पांच केंद्रों के आसपास सर्दियों के दौरान पानी का छिड़काव भी होता रहता है। बावजूद इसके इस सीजन में लालबाग और तालकटोरा में प्रदूषण का उच्चतम स्तर 500 के ऊपर पहुंच चुका है।

प्रदूषण में आगे
- गाजियाबाद
- नोएडा
- मेरठ

साफ हवा में आगे
- मुरादाबाद
- झांसी
- बरेली

प्रदूषण के खिलाफ प्रयास : नगर निगम 8 एंटी स्मोकगन और 20 वाहनों से मुख्य मार्गों पर पानी का छिड़काव करा रहा है, जिससे लाभ हो रहा है।

> सर्दियों में तापमान में गिरावट, नमी और हवा के धीमे बहाव से प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ जाती है। कई शहरों में ऐसा सिस्टम नहीं है, जिससे प्रदूषण रोका जा सके। मनुष्य, पशु-पक्षियों, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
>
> -**प्रोफेसर श्याम नारायण पांडेय**, लखनऊ विश्वविद्यालय

झारखंड

राजधानी रांची की हवा में नहीं है ज्यादा जहर

झारखंड की राजधानी रांची में वायु प्रदूषण का स्तर फिलहाल स्वीकार्य श्रेणी में बना हुआ है। सोमवार को यहां पीएम-10 का स्तर 125 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जबकि पीएम-2.5 का स्तर सामान्य सीमा (60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम) के भीतर रिकॉर्ड किया गया। रांची का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अधिकतम 125 तक रहा। धनबाद में इस समय औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं जमशेदपुर में पिछले तीन दिनों के दौरान एक्यूआई करीब 150 के आसपास बना हुआ है। झारखंड में कुछ शहर प्रदूषित हैं, तो अनेक शहर बहुत अच्छे भी हैं।

प्रदूषण में आगे
- झरिया
- धनबाद
- जमशेदपुर

साफ हवा में आगे
- सिमडेगा
- गुमला
- नेतरहाट

> राज्य में वायु प्रदूषण की स्थिति फिलहाल चिंताजनक नहीं है। अभी झारखंड के अधिकांश शहरों में एक्यूआई 150 से कम पर बना हुआ है, जिसे मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। बोर्ड प्रदूषण स्तर को कम रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
>
> -**राजीव लोचन बक्शी**, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद

बिहार

यहां पटना सहित किसी बड़े शहर की हवा ठीक नहीं

बिहार में पटना सहित 23 शहरों की हवा सोमवार को बहुत प्रदूषित रही। पटना में दानापुर क्षेत्र की हवा खराब श्रेणी की रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 224 दर्ज किया गया। 15 शहरों में वायु प्रदूषण मध्यम श्रेणी (101-200) में हैं। इनमें अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, बिहारशरीफ, बक्सर, गयाजी, हाजीपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, राजगीर, सहरसा, समस्तीपुर व सासाराम शामिल हैं। राज्य में हवा की सबसे बेहतर स्थिति पश्चिमी चंपारण के मंगौराहा में रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। इस राज्य में लगातार वायु प्रदूषण की स्थिति बने रहने से लोगों की सांस पर सांसत है।

प्रदूषण में आगे
- बेगुसराय
- पूर्णिया
- हाजीपुर

साफ हवा में आगे
- औरंगाबाद
- सासाराम
- गया

> शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण से बुरा असर पड़ रहा है। धूल, धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से श्वसन- रोग, एलर्जी, अस्थमा, फेफड़े में संकुचन, हृदय संबंधी समस्या और कैंसर का जोखिम बढ़ता है। सेहत पर खर्च बढ़ता है।
>
> -**डॉ प्रकाश सिन्हा**, सांस व छाती रोग विशेषज्ञ, पटना

उत्तराखंड

पहाड़ पर पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं लोग

मैदानों में जब पदूषण बढ़ता है, तब लोग पहाड़ों में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। आंकड़ों को अगर देखें, तो राजधानी देहरादून सहित उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक है। देहरादून में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया, जबकि रविवार देर रात अधिकतम एक्यूआई 200 तक पहुंच गया था। काशीपुर का एक्यूआई 94, ऋषिकेश का 59 और हरिद्वार का 80 रिकॉर्ड किया गया, ये शहर संतोषजनक श्रेणी में गिने जाते हैं, यहां आकर लोगों को राहत का एहसास होता है। वैसे, क्रिसमस व नववर्ष पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से 24 दिसंबर के बाद प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।

साफ हवा वाले कुछ शहर
- अल्मोड़ा
- नैनीताल
- मसूरी
- ऋषिकेश
- हरिद्वार
- पिथौरागढ़

> उत्तराखंड में रात में पड़ने वाली ओस, सुबह-शाम और दिन में चलने वाली हवाएं वायु को शुद्ध रखने में सहायक हैं। पेड़-पौधों को बचाकर ही प्रदूषण से लड़ा जा सकता है। जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, वह भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।
>
> -**डॉ विजय श्रीधर**, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विभाग, दून विश्वविद्यालय

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास भरपूर तो रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। कारोबार के प्रति सचेत रहें। परेशानी आ सकती है।

वृष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार की समस्या परेशान कर सकती है। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। सेहत का भी ध्यान रखें। खर्च में वृद्धि होगी।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा।

सिंह : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ में वृद्धि होगी। यात्रा पर भी जा सकते हैं।

कन्या : कारोबारी कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित हो सकता है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है।

तुला : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। कारोबार में लाभ बढ़ेगा।

वृश्चिक : आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ में भी वृद्धि होगी। कला व संगीत में रुचि बढ़ सकती है।

धनु : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। आय बढ़ेगी।

मकर : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा।

कुंभ : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार बढ़ेगा। परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

मीन : आत्म संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। नौकरी में कार्यक्षेत्र के विस्तार के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

17 दिसंबर, बुधवार, **शक संवत् :** 26 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग :** 03 पौष मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम :** 25 जमादि-उल्सानी, 1447, **विक्रमी संवत :** पौष कृष्ण त्रयोदशी रात्रि 02.33 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, विशाखा नक्षत्र सायं 05.12 मिनट तक पश्चात अनुराधा नक्षत्र, गर करण। चंद्रमा तुला राशि में प्रात: 10.26 मिनट तक उपरांत वृश्चिक राशि में। **सूर्य दक्षिणायन।** सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 02.33 मिनट से। प्रदोष व्रत।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हम जिस घर में पच्चीस साल से रहते हैं, उसमें हमने बहुत उन्नति की। उस घर में अब कई सालों से स्वास्थ्य तथा अन्य चीजों को लेकर बहुत परेशान हैं। कृपया कोई उपाय बताएं।
-**नरेश कुमार**, लखनऊ

- आप का घर पूर्व उत्तर मुखी है, जो बहुत शुभ है। आपने घर में घुसते ही सेप्टिक टैंक बनवा रखा है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या का बहुत बड़ा कारण है। इस सेप्टिक टैंक को यहां से हटाकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बनवाएं। यदि नहीं कर सकते तो फिर उपाय के तौर पर इसकी ब्लॉकिंग करवाएं तथा वर्चुअल शिफ्टिंग करवाएं। घर में फर्श एवं दीवारों में जगह-जगह दरारें हैं, उन्हें ठीक करवाएं।

वर्ग पहेली : 8181

बाएं से दाएं

3. एक पवित्र स्थल जहां यज्ञ करते हैं; यज्ञ करने के लिये बनाया हुआ मंडप (5)
6. आवश्यकता; प्रयोजन (4)
8. काम न आने वाला टूटा-फूटा सामान; निरर्थक वस्तु; बेकार चीजें (3)
9. जिसमें दाने हों; दरदरा; दाने वाला; रवादार (4)
10. गति; चाल; प्रवाह; संवेग; चलने का ढंग (3)
11. अवरोधक; बाधा उत्पन्न करने वाला; रुकावट डालने वाला; कष्टदायक (3)
12. वर्षा; बारिश (4)
13. चिह्न दूर करना; नष्ट करना; न रहने देना; पोंछना; लुप्त करना (3)
15. भीषण ध्वनि; बहुत घना; भयावना (4)
16. नाम रखा जाना; नाम रखने का काम (5)

ऊपर से नीचे

1. कोई समाचार न आना; हालचाल न मिलना (2,3,1,3)
2. जिसमें कई परतें हों; परतों वाला (5)
4. मेंढक; एक प्राचीन ऋषि; एक प्रकार का नृत्य; घोड़े की एक जाति (3)
5. अत्यधिक शोक के कारण खड़े-खड़े अचानक बेसुध होकर गिर पड़ना; विह्वल होने के कारण खड़े-खड़े गिर जाना (3,3,3)
7. क्रय विक्रय करना; सामान खरीदना बेचना (2,3)
11. इज्जत होना; काम ठीक होना; काम बनना (2,3)
14. जिसे ईश्वर में विश्वास न हो; 'आस्तिक' का विलोम; धर्महीन (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8180

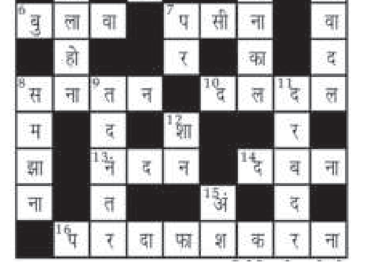

सुडोकू : 8163

* कठिन

	7	2	6					
		5	8		9	2		6
							7	
8		9		2				
1								4
				1		7		9
	5							
2		3	1		7	6		
					5	1	4	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8162

4	2	6	7	5	8	9	3	1
8	5	9	4	3	1	6	2	7
3	7	1	6	9	2	8	4	5
1	9	4	2	6	7	5	8	3
6	3	2	8	4	5	7	1	9
7	8	5	3	1	9	4	6	2
5	6	7	1	8	3	2	9	4
2	1	8	9	7	4	3	5	6
9	4	3	5	2	6	1	7	8

स्तुति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है–आह्लादन भाव। यह एक कठिन भाव है। भक्ति रस का अर्थ ही प्रमोद है। मन में ईश्वर के स्वरूप की कल्पना और उससे उत्पन्न आह्लाद। बिना आह्लद के तन्मयता नहीं आती।

स्तुति ही भक्ति का मार्ग

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

स्तुति व्यक्ति को सकारात्मक भाव देती है। गुणों की प्रशंसा करना सिखाती है। स्तुति आराध्य के साथ एकात्म भाव पैदा करती है।

स्तुति एकमात्र वह अभ्यास है, जो व्यक्ति को गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्तुति व्यक्ति को सकारात्मक भाव देती है। गुणों की प्रशंसा करना सिखाती है। स्तुति आराध्य के साथ एकात्म भाव पैदा करती है। स्तुति में कुछ काल के लिए व्यक्ति आराध्य के स्वरूप से तादात्म्य स्थापित कर सकता है। उसके मन में आराध्य के गुण धारण करने की इच्छा प्रबल होती है। व्यक्ति आराध्य जैसा बनने की कल्पना करता है। कई द्वंद्व उसके मन में उठते हैं। अपने बिम्ब का एक प्रतिबिम्ब उसको दिखाई देता है। अपनी कमजोरियां दिखाई पड़ती हैं, उन्हें मिटाने का भाव पैदा होता है।

विकास के लिए सदा सकारात्मक भाव चाहिए। दूसरों में अच्छे गुण देखने का अभ्यास अपने आप में दुर्लभ हो गया है। जबकि गुण देखना, गुणों की प्रशंसा करना और बार-बार दोहराते हुए उन गुणों को आत्मसात कर लेना सुखी जीवन के लिए हर दृष्टि से वांछित है। जीवन में व्यक्ति प्रायः स्वयं को कमजोर पाता है। कई बार आपदाओं से संघर्ष करना पड़ता है, बाधाएं आती हैं, जूझना पड़ता है। कमजोरी उसका मनोबल तोड़ देती है। वह सहारा ढूंढता है। सबसे आसान लगता है, ईश्वर का सहारा। बात किसी को पता भी नहीं लगती और व्यक्ति ईश्वर की स्तुति कर स्वयं को आश्वस्त भी कर लेता है।

स्तुति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है- आह्लादन भाव। यह एक कठिन भाव है। भक्ति रस का अर्थ ही प्रमोद है। मन में ईश्वर के स्वरूप की कल्पना और उससे उत्पन्न आह्लाद। बिना आह्लाद के तन्मयता नहीं आती। हम एकाकार नहीं हो सकते, पूर्ण मनोयोग नहीं बनता। व्यक्ति के जीवन में उस आह्लाद के प्रवेश करने पर वह स्वतः ही साम्य-योग में चला जाता है। किसी भी प्रकार की स्थिति में जीना पड़े वह इस आह्लाद से बाहर नहीं होता। भोग के जीवन में भी वह अकिंचन हो जाता है। समेटने का भाव त्याग में बदल जाता है। उसके सुख की अनुभूति का धरातल भी बदल जाता है। यह आह्लादन-शक्ति इन्द्रियों और बुद्धि से परे होती है। सही अर्थों में तो यह मन के भी आगे निकल जाती है। आह्लादन-शक्ति के प्राप्त होने पर ही स्तुति भक्ति में परिवर्तित होती है। स्तुति व्यक्ति में शक्ति का संचार करती है। उसके सोए आत्मबल को जगाती है। स्वामी समर्थ है तो सेवक भी समर्थ हो जाता है, यही सोचकर ईश्वर भी सामर्थ्य को बढ़ाता है। उस सामर्थ्य से व्यक्ति अपने भावों को परिष्कृत करता है, अपने मन पर नियंत्रण करता है, अपने विवेक को जागृत करता है। स्तुति करता है।

हमें हमारी स्तुति के शब्दों को पढ़कर पहले उसके भावों को समझना चाहिए। ये भाव चाहे प्रशंसा के हों, ईश्वर के सौंदर्य की व्याख्या करते हों अथवा उसकी शक्तियों की, हमें उनको समझकर अपने स्तुति गान में शामिल कर लेना चाहिए। यदि भाव शब्दार्थ से जुड़ जाते हैं और आप पूर्ण मनोयोग से उसकी अभिव्यक्ति कर लेते हैं, तो आराध्य के साथ तादात्म्य स्थापित करना सरल हो जाता है। आपका संदेश ईश्वर तक पहुंच जाता है। आपको स्तुति का फल मिलना भी निश्चित हो जाता है। आप स्तुति करते रहें और मन में भाव कुछ अन्य हों, तो आप कैसे जुड़ेंगे, अपने आराध्य से? भक्ति में भाव जुड़े होते हैं। भाव ही भक्ति का प्रवेश द्वार है। भक्ति गुणों को देखती है, दिव्य स्वरूप को भी देखती है, प्रकाश में भी देखती है, सामाजिक परिवेश को भी देखती है। भक्ति इन सभी परिवेशों के साथ-साथ जीवन के अनेक प्रकार के भय या प्रभावों को भी देखती है। इन प्रभावों से मुक्त होने के लिए शक्ति का आह्वान करती है।

कृष्ण तो भक्ति के लिए ही जाने जाते हैं। गीता में आम आदमी के लिए भक्ति योग प्रधानता से बताया गया है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त बन जाओ। अन्त में यह भी कहते हैं कि 'मामेक शरणं व्रज' में ही तुम्हें पापों से मुक्त करा दूंगा।

भक्तिभाव व्यक्ति सोच समझ कर पैदा करता है। पहले अपना इष्ट तैयार करता है, फिर धीरे-धीरे उसकी भक्ति में डूबता चला जाता है। नृसिंह अवतार इस भक्ति का चरम है, जहां भक्त प्रहलाद के स्तवन से भगवान नृसिंह यथानुरूप, यथासमय खम्भा तोड़कर प्रकट हो गये थे। प्रहलाद का अभय स्वरूप उसकी भक्ति के कारण ही समझ में आता है। जहां वह अपनी मृत्यु के भय से आक्रान्त नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर में जो सामर्थ्य है, वह स्तुति करने से भक्त में आ जाता है। ईश्वर भक्त को अपने जैसा बना लेता है। भक्त ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करता है। भक्त है तो ईश्वर है। स्तुति ही साधारण व्यक्ति को भक्त बनाती है।

gulabkothari@epatrika.com

काव्यांजलि...

प्रेम में पराजित लड़की

दिलखुश मीना

प्रेम में कई बार पराजित हुई
लड़की से कभी
प्रेम मत करना
वह हर प्रेम आयाम को
शंकित छलावे की
दृष्टि से देखती है

उसे डर रहता है कि
इस बार भी
वह कहीं प्रेम में
पराजित न हो जाए
जिस प्रेम में कलुष भाव
उपजते हों
वह प्रेम कभी फलीभूत
नहीं हो सकता
उस प्रेम की दीर्घायु
एक भ्रम मात्र है
वह सिर्फ दो दिलों के बीच
का वायवीय छलावा है

दूध की जली लड़की सदैव
अपने नव प्रेमी की
हर चेष्टा को
छाछ की तरह फूंकती है
हर बात पर इतना संदेह
करती है कि
कभी किसी से प्रेम ही
नहीं कर पाती
यूं ही रीत जाता है
उसका यौवन

उसके शंकित प्रेम की ताबीर
उस भावभूमि को
कभी नहीं छू पाती
जो प्रेम की
अंतिम सीढ़ी होती है
विरह पीड़ा में
रात-दिन जल कर
घुटन से मेरी रूह
कांप उठी है
कि बहुत भयावह होता है
प्रेम में पराजित हुई लड़की से
प्रेम किया जाना।

कहानी...

उस रात अनिरुद्ध ने सोचा-परिवार वही है, जहां दर्द बोझ नहीं बनता, वह जगह बनाता है। जहां यादें सर्द नहीं करतीं, बल्कि दिसंबर की धूप की तरह धीरे-धीरे दिल पर उतरती हैं। और कई महीनों बाद पहली बार, उसे दिसंबर ठंडा नहीं लगा।

दिसंबर

ज्योति कटेवा
@patrika.com

दिसंबर हमेशा से अनिरुद्ध का प्रिय महीना रहा है। बचपन से ही उसके लिए यह महज कैलेंडर की आखिरी पंक्तियां नहीं था- यह एक अहसास था। दिसंबर आते ही घर में कुछ बदल जाता था। हवा में हल्की-सी घुली लकड़ी के धुएं की महक, रसोई में तिल और गुड़ की खुशबू, और मां की गूंजती हुई आवाज-सब मिलकर घर को एक गर्माहट भरी दुनिया बना देते थे। लेकिन इस बार दिसंबर अलग था। मां को गुजरे अब दो पूरे साल हो चुके थे, पर अनिरुद्ध के लिए यह समय अभी भी अटका हुआ-सा लगता था। जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ चुकी हों, लेकिन दिल वहीं ठहरा रह गया हो। घर में सबकुछ पहले जैसा था-दीवार की घड़ी, खिड़की के पास का पौधा, लिविंग रूम में रखा पुराना हीटर- पर एक चीज गायब थी और उसी एक के बिना घर की धड़कन धीमी पड़ गई थी।

दिसंबर की एक दोपहर, जब धूप आंगन में धीरे से सरक रही थी, अनिरुद्ध अकेले कमरे में बैठा था। बाहर हवा में ठंड का पहला असली डंक उतर आया था। वह चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था, जहां नीम के पत्तों के बीच से आते उजाले में धुंध तैर रही थी। अचानक ही उसके मन में एक पुरानी याद उठी-मां उसे हर दिसंबर में स्वेटर पहनाते हुए कहती थीं, 'ठंड मौसम की नहीं होती बेटे, अकेलेपन की होती है।' उसके होंठों पर हल्की-सी मुस्कान आई, पर आंखें नम हो गईं। उसने उठकर अलमारी खोली और धीरे से वह लकड़ी की पेटी निकाली, जिसमें मां की कुछ चीजें रखी रहती थीं। वह पेटी अनिरुद्ध के लिए सिर्फ सामान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दरवाजा थी, जिससे गुजरते ही वह मां की दुनिया में चला जाता था। ढक्कन खोलते ही एक जानी-पहचानी खुशबू उसके चेहरे से टकराई-हल्दी, कपूर, किसी पुराने इत्र की हल्की खुशबू। उसने भीतर हाथ डाला और एक-एक करके सब देखा- मां की पुरानी चूड़ियां, रंगीन धागों का एक गुच्छा, और सबसे ऊपर रखी वही नीली शॉल। वह शॉल, जिसको ओढ़कर मां बरामदे में बैठकर ऊन कातती थीं। उसके किनारे घिसे हुए थे, लेकिन अनिरुद्ध के लिए वही सबसे कीमती थे- क्योंकि उन्हीं किनारों में बसे थे अनगिनत स्पर्श, अनगिनत लम्हें। उसने शॉल को कंधों पर रख लिया। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से हल्के से उसे ढक दिया हो- धीरे, प्यार से, बिलकुल वैसे, जैसे मां करती थीं। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसका छोटा भाई ऋत्विक खड़ा था। 'भैया अंदर आ सकते हैं?' ऊंगली चबाते हुए उसने पूछा, जैसे कुछ कहना चाहते हुए भी हिचक रहा हो। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। ऋत्विक कमरे में आया, उसकी नजर नीली शॉल पर जाकर रुक गई। वह कुछ क्षण चुप रहा। शायद वह भी उसी महक में अपना बचपन ढूंढ रहा था। उसने धीरे से कहा, 'आज मां वाला गाजर का हलवा बनाया। पता नहीं, वैसा बना है या नहीं, पर कोशिश की है।' अनिरुद्ध उसकी आवाज में छिपी नर्मी पहचान गया।

दोनों भाइयों के बीच दो साल से जो खामोशी जमा थी, वह मानो शॉल की खुशबू से पिघलने लगी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, 'चलो।' और दोनों रसोई की ओर चल पड़े। रसोई में हलकी भाप उठ रही थी। गैस के पास रखे बर्तन में गाजर का हलवा गर्म था- वैसा ही लाल, वैसा ही खुशबूदार। अनिरुद्ध ने एक चम्मच लिया और चखा। स्वाद ठीक वैसा तो नहीं था- लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मां की याद दूर लगती हो। बल्कि स्वाद में एक नई बात थी- दो भाइयों की खामोश कोशिश, अपनी दुनिया फिर से जोड़ने की। 'ठीक है?' ऋत्विक ने पूछा। अनिरुद्ध ने चम्मच रखते हुए कहा, 'यह बहुत अच्छा है। सच में... बहुत अच्छा।' और यह कहते समय उसकी आवाज भर्रा गई। वे दोनों रसोई के फर्श पर बैठ गए- जैसे बचपन में बैठते थे। हीटर की हल्की गर्माहट कमरे में फैल रही थी। ऋत्विक ने धीरे से कहा, 'भैया आपको लगता है कि मां हमें देख रही होंगी?' अनिरुद्ध ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह सवाल सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऋत्विक के भीतर जमा हुआ दर्द था। उसने भाई के कंधे पर हाथ रखा। 'मुझे लगता है, मां कभी कहीं नहीं गईं। बस... हमारी जिंदगी के बाहर से अंदर चली गईं। जहां यादें रहती हैं, जहां हम उन्हें महसूस करते हैं। देखना, हर दिसंबर वे यहीं होती हैं- बस हमें महसूस करना होता है।' ऋत्विक की आंखें भर आईं। यह पहली बार था, दो साल में, जब दोनों भाई एक ही दुख को एक साथ महसूस कर रहे थे- भागकर नहीं, छुपाकर नहीं, बल्कि बांटकर। रात को दोनों भाई मां की शॉल में बैठकर पुरानी फोटो एलबम देखकर हंसते और रोते रहे। कभी उस तस्वीर पर, जिसमें मां उन्हें डांट रही थीं। कभी उस पर, जहां दोनों की नाक पर मलाई लगी थी। कभी उस पर जहां मां खिलखिलाकर हंस रही थीं और दोनों लड़के शर्म से मुड़े हुए थे। धीरे-धीरे घर की दीवारें फिर गर्म लगने लगीं। हीटर की आवाज, भाप, रसोई की महक-सबने मिलकर वह कमी थोड़ी कम कर दी। उस रात अनिरुद्ध ने सोचा- परिवार वही है, जहां दर्द बोझ नहीं बनता, वह जगह बनाता है। जहां यादें सर्द नहीं करतीं, बल्कि दिसंबर की धूप की तरह धीरे-धीरे दिल पर उतरती हैं। और कई महीनों बाद पहली बार, उसे दिसंबर ठंडा नहीं लगा। वह फिर से लौट आया था- अपनी असली गर्माहट में, अपनी खोई हुई रोशनी में, ठीक वैसे जैसे मां हर साल घर को उजाला करके जाती थीं।

क्लासिक पुस्तक...

उर में बसी उर्वशी!

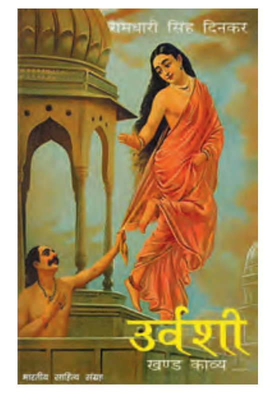

समाज के समस्त संवर्ग साहित्य में प्रवाहमान हैं। इसी प्रवाह में वर्ष 1961 में रामधारीसिंह दिनकर ने श्रेष्ठ काव्यनाटक 'उर्वशी' रची। नाटकीय काव्यकथा पूर्णरुपेण पौराणिक है, पर जमीन आधुनिक है। उर्वशी के आसपास प्रेम, सौंदर्य, कामना और मानवीय संघर्ष की गहन दुनिया विराजती है। नाटकीय संवादशैली के महाकाव्य परंपरा में वाल्मीकि, कालिदास और जॉन मिल्टन के समदृश्य उर्वशी चार खंड में विभाजित है।

उर्वशी की दृष्टि-शैली 'मेघदूत' और 'रघुवंश' स्मृति का दस्तावेज है। उर्वशी नेह में दो-ढाई दशक बीत गए। फिर भी यह काव्यात्मक उपन्यास उर में बसी है, क्योंकि इसके किरदार कालजयी है।

पुरुरवा,रेखाचित्र, सुकन्या, रंभा, मेनका, अपाला सहित सब अनूठी हैं। बेशक कविता का सुनिश्चित भौगोलिक प्रांत न होकर मानव हृदय चेतना का अंतर्महासागर है, जहां शुद्ध संवेदन भाव तरंगित हैं। जहां धुंधले समय की रेखाएं रोशन हो उठती हैं।

उर्वशी की कामुकता सिहराती है, तो पुरुरवा की व्यथा नेत्रों के कोर भिगोते जाते हैं। व्यथा के चुभन से बेशोर तेज पीर उठती है। उत्थान-पतन के पेट में प्रच्छ्न बीज वक्त का शिनाख्त करने बारिश के बाद अनाम रूहों में उगते हैं। सौंदर्य मीमांसा, कामुकता का मनोविश्लेषण, स्त्रीवाद और सार्वभौमिक प्रेम की थाह मिलती है। पुरातन-आधुनिक सौंदर्य सम्मिश्रण में समूचे संसार का विमर्श संगम सहज परिलक्षित है। उर्वशी ग्रीक काव्य की हेलेन और शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा के समकक्ष है।

ठीक वैसा ही शिल्प का अंदाज फ्रायडियन मनोविश्लेषण 'लिबिडो' के करीब। जेंडर समानता विमर्श की अवधारणा नवाकार प्रासंगिक है। रूपक में प्रतीक चमत्कार सरीखे हैं। जिससे बहुस्तरीय रचना का शाश्वत सच 'अंतर्द्वंद्व' संवाद दर्पण बन पड़े हैं। प्रेम में दर्शन है, दर्शन में स्त्री और स्त्री में मौजूद प्रेम सृष्टि का प्रकाश है। उजला-अंधेरा ही सत्य है, शेष मिथ्या ही है।

डॉ. सुनीता, लेखक व आलोचक

लघुकथा...

नीली रोशनी

रुपया-पैसा, कपड़े-गहने, सब चल जाता है, पर पत्नी को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है पति के साथ की। उसके विश्वास की। उसी बात पर आज फिर पल्लवी रूठ गई। सुधाकर धीरे से पास आया। पल्लवी की बिखरी लटें संवारते हुए बोला, भाग्यवान, तुम्हारी बात सौ फीसदी सही है। पर क्या तुमने महसूस किया है कि नया फोन आने के बाद तुम मुझसे ज्यादा फोन के साथ रहने लगी हो? काम से लौटकर जब भी तुम्हारे पास बैठता हूं, तुम स्क्रीन में खोई रहती हो। और मैं? मैं बस तुम्हें देखता रह जाता हूं। सुधाकर की आवाज़ नम हो गई। पल्लवी ने धीरे से फोन उठाया और उल्टा करके मेज पर रख दिया। सच कहते हो जी, आज से जब हम साथ होंगे, तो हमारे बीच कोई स्क्रीन नहीं आएगी। वह धीमे से बोली।

मोबाइल की नीली रोशनी धीमे-धीमे बुझने लगी और उनके बीच वर्षों पुरानी, गर्माहट भरी प्यार की रोशनी फिर से जाग उठी।

- विजय सिंह चौहान

माइंड गेम...

उपसर्ग बताइए

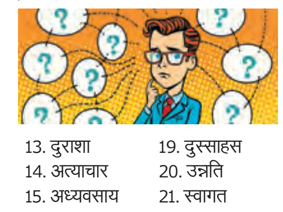

नीचे दिए शब्दों में उपसर्ग बताइए। उत्तर अंत में हैं।

1. उत्कृष्ट	7. औघड़	13. दुराशा	19. दुस्साहस
2. परिवार	8. अत्यधिक	14. अत्याचार	20. उन्नति
3. अनिष्ट	9. अध्यक्ष	15. अध्यवसाय	21. स्वागत
4. बेईमान	10. निष्फल	16. उ–म	
5. अत्युक्ति	11. निराशा	17. अनुपयुक्त	
6. प्रत्युपकार	12. उपाध्यक्ष	18. संबंध	

1.उत्, 2.परि, 3.अन्, 4.बे, 5.अति, 6.प्रति, 7.औ, 8.अति, 9.अधि, 10.निस्, 11.निर्, 12.उप, 13.दुर्, 14.अति, 15.अधि, 16.उत्, 17.अन्, 18.सम्, 19.दुस्, 20.उत्, 21.सु।

भारत की पहली महिला साइबर क्राइम अन्वेषक...

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान

पट्टाथील धान्या मेनन

पट्टाथील धान्या मेनन का नाम देश की पहली महिला साइबर क्राइम अन्वेषक के रूप में दर्ज है। मेनन ने देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। मूल रूप से केरल के त्रिशूर की रहने वाली मेनन के पिता पूर्व बैंकर थे। उनका तबादला अक्सर दूसरे शहरों में होता रहता था।

प्रारंभिक शिक्षा और स्नातक के बाद धान्या ने ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (एप्टेक के माध्यम) से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। बाद में, उन्होंने पुणे के एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ से साइबर लॉ और साइबर स्पेस में बौद्धिक संपदा अधिकारों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। अपने कॅरियर की शुरुआत धान्या ने एक कार्यशाला में भाग लेने से की। उन्हें यह फील्ड पसंद आ गया, तो उन्होंने साइबर कानून में कॅरियर बनाने का फैसला किया। उस समय यह क्षेत्र भारत में नया था। करीब 15 वर्ष पहले उन्होंने कोच्चि में अपनी खुद की साइबर सुरक्षा समाधान फर्म की स्थापना की। उन्होंने फर्जी प्रोफाइल, विजुअल मॉर्फिंग, अश्लीलता, पहचान की चोरी और साइबर स्टॉकिंग से संबंधित हजारों मामलों की जांच की है और सफलतापूर्वक समाधान किया है। मेनन ने केंद्र सरकार के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया है। केरल सरकार के 'निर्भया' प्रोजेक्ट के लिए साइबर क्राइम सलाहकार भी नियुक्त की गई थीं। उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्घाटन 'प्रथम महिला अचीवर्स अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया था। मेनन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला 2006 में केरल का एक मामला था, जब तीन स्कूली छात्राओं ने कक्षा में आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि एक दूसरे सरकारी स्कूल के लड़के मोबाइल फोन पर खींची गईं तस्वीरों से उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। हालांकि इस मामले को सुलझाने के बाद वे पहली महिला साइबर अपराध अन्वेषक बनीं, लेकिन अश्लीलता, टेलीफोन तकनीक के दुरुपयोग, पोर्नोग्राफी और पोर्न साइट्स से फर्जी प्रोफाइल बनाने के लिए विजुअल मॉर्फिंग, आंतरिक और गोपनीय जानकारी का अनाधिकृत प्रकटीकरण, और बौद्धिक संपदा की चोरी या व्यापार से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या ने उन्हें परेशान किया।

फील्ड एक्सपर्ट के तौर पर उनका कहना है कि वयस्क भी निजता के भ्रम में जीते हैं और उतने ही असुरक्षित हैं।

बोधकथा...

बादल और बरसात

वर्षा ऋतु आई और आकाश में काले-घने बादलों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। लोग आशा भरी नजरों से आसमान की ओर देखने लगे। यह देख बादलों को घमंड हुआ। 'देखा, लोग हमें कितना मानते हैं!' दूसरा बोला, 'हम ऊंचे तैरते रहेंगे। झुकना हमारी शान के खिलाफ है।' पास ही तैर रही छोटी-छोटी जल-बूंदों ने कहा, 'डराने से क्या होगा? धरती की प्यास बुझाने के लिए हमें बरसना चाहिए।' बड़े बादल हंस पड़े, 'हम आसमान के राजा हैं, नीचे क्यों झुकें?' दिन बीतते गए। कुएं खाली हो गए। एक छोटे बच्चे ने मासूमियत से हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, 'हे भगवान, बारिश भेज दो। मेरी मां के खेत सूख रहे हैं।' उस मासूम आवाज ने छोटे बादल का दिल पिघला दिया। उसने कहा, 'महान वह है, जो झुककर किसी की प्यास बुझाए।' वह झुक गया और धरती पर बरस पड़ा। जैसे ही बूंदें गिरीं, सूखी धरती में भीनी खुशबू फैल गई, पौधे मुस्कुरा उठे और बच्चे नाचने लगे। यह देखकर बाकी बादलों को भी शर्म आई और वे भी झुककर बरस पड़े। पूरा गांव खुशियों से भर गया।

डॉ. अलका जैन 'आराधना'

संपादकीय

दोस्ती कुणाची? कुस्ती कुणाशी?

भवति-न-भवति करीत अखेर महापालिका निवडणुकांवरील अनिश्चिततेचे सावट दूर झाले आहे. राज्यातील सर्व २९ महापालिकांच्या रणधुमाळीचा बिगुल वाजला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्याचा म्हणजे २८८ नगरपालिका-नगरपंचायतींचा निकाल लागल्यानंतर पुढच्या मंगळवारी महापालिकांच्या दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू होईल. जवळपास साडेतीन कोटी मतदार नव्या वर्षात १५ जानेवारीला २ हजार ८६९ नगरसेवक निवडून देण्यासाठी मतदान करतील. १६ जानेवारीला जनमताचा कौल स्पष्ट होईल. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई, शेजारचे ठाणे, आर्थिक व औद्योगिक प्रभाव असलेले पुणे व पिंपरी-चिंचवड तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय व दीक्षाभूमी असलेले नागपूर या मोठ्या महापालिकांमध्ये कोणाला कौल मिळतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असेल आणि नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या शहरांकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. सामान्य कार्यकर्त्यांचे जाळे ते मतदार याद्या अशा सर्वच बाबतीत महापालिका निवडणूक हे राजकीय पक्षांसाठी मोठी कसोटी असेल. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीतील ऐतिहासिक यश केवळ योगायोग नव्हता, फ्लूक नव्हते हे दाखवून देण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष तसेच शिंदे सेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी या महायुतीमधील घटकपक्ष कंबर कसून मैदानात उतरतील. मुंबई वगळता या प्रमुख महापालिकांमध्ये सध्या तरी राज्यातील सत्ताधारी महायुतीपुढे विरोधी पक्षांचे आव्हान मोठे नाही. त्यामुळेच बहुतेक ठिकाणी विरोधकांची जागा बळकावण्यासाठी महायुतीमधील घटकपक्षच एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढतील, असे दिसते. पुणे व ठाणे ही अशा मैत्रीपूर्ण लढतीची ठळक उदाहरणे म्हणता येतील. नागपूरमध्ये भाजप स्वबळावर लढून सलग चौथ्यांदा महापालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करील. उद्धव व राज हे ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे मुंबईत मात्र महायुतीला एकजूट होऊन लढण्याशिवाय पर्याय नाही. मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानीच आहे असे नाही. देशातील अनेक छोट्या राज्यांपेक्षा मोठे बजेट असणारी ही धनवान महापालिका आहे. म्हणून ती ताब्यात ठेवण्याचा सगळेच प्रयत्न करतील. शिवसेनेच्या फुटीनंतर भाजप व उद्धवसेनेमध्ये निर्माण झालेली कटुता, संकटसमयी ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे म्हणून उभा राहिलेला कार्यकर्ते व जनतेचा रेटा, ठाकरे घराण्याची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी भिडलेले एकनाथ शिंदे, त्यांना नारायण राणे व पूर्वाश्रमीच्या शिवसेना नेत्यांची साथ आणि या सगळ्यातून राजकीय लाभ-हानीचे डावपेच लढविणारा भाजप अशा रंजक वळणावर मुंबईचा महासंग्राम पोहोचला आहे. मराठी माणसांसाठी आम्ही लढत आहोत, असे ठाकरे बंधू व त्यांचे पक्ष म्हणत असले तरी केवळ मराठी मतांवर मुंबई जिंकणे शक्य नाही. अशावेळी अन्य भाषिक तसेच इतर मतदारांना ते आपल्याकडे कसे वळवितात हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी या अन्य विरोधी पक्षांची ताकद सध्या दिसत नसली तरी मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर अशा बहुतेक सर्व शहरांमध्ये काँग्रेस तर पुणे व अन्य काही ठिकाणी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी जिवंत आहे. लोकसभा निवडणुकीत या पक्षांना चांगले यश मिळाले. आता महापालिका निवडणुकीत ती ताकद कसे दाखवून देतात हे पाहावे लागेल. असो. या निवडणुका प्रदीर्घ प्रशासकीय राजवटीच्या पार्श्वभूमीवर होत आहेत. काही शहरांमध्ये पाच वर्षांपासून, तर बहुतेक ठिकाणी तीन-साडेतीन-चार वर्षांपासून संपूर्ण प्रशासन, कारभार प्रशासकांच्या म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. आता या निवडणुकांनंतर लोकनियुक्त नगरसेवक सभागृहात असतील. विविध समित्या, विशेषत: खजिन्याची चावी म्हणविली जाणारी स्थायी समिती स्थापन होईल. महापौरपद मानाचे तर स्थायी सभापतिपद कामाचे. म्हणून दोन्ही पदे आपल्या ताब्यात असावीत यासाठी स्पर्धा असेल. तत्पूर्वी, नगरसेवकांच्या निवडीत खरा कस लागेल तो नागरिकांचा. वाहतूक कोंडी, हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन ही प्रमुख आव्हाने सगळ्याच शहरात आहेत. मुंबई, पुणे, ठाण्यात तर ती अधिकच कठीण आहेत. ती पेलणारी, समस्या सोडविणारी, राहणे आणि जगणे सुखकर बनविणारी नगरसेवकांची टीम निवडून देणे हे नागरिकांपुढील प्रमुख आव्हान आहे. राजकीय थिल्लरपणा, आरोप-प्रत्यारोप, हडेलहप्पी यापलीकडे जाऊन विचार करण्याची, वॉर्डा-वॉर्डातून कामाची माणसे निवडून देण्याची आणि त्यांच्या माध्यमातून नागरी प्रश्न सोडवून घेण्याची हीच वेळ आहे.

प्रदूषणावरून संसदेत राजकीय 'युद्धबंदी'!

विषारी प्रदूषणाने देशाला लपेटले आहे, याबद्दल संसदेत राहुल गांधींनी वाचा फोडली आणि संसदेच्या इतिहासात घडले नव्हते असे काहीतरी घडले.

प्रभू चावला
ज्येष्ठ पत्रकार

अतिशय दाट आणि घातक विषारी हवेच्या चादरीने देशाला आज लपेटले असून, या हवेचा दैनंदिन जीवनावर परिणाम होतो आहे. सकाळी आकाश न दिसणे, हवामान सांगणाऱ्या ॲप्सवर धोक्याचे इशारे, कुठलीही साथ नसली तरी धूलिकणापासून वाचण्यासाठी मास्क वापरण्याच्या सूचना या गोष्टी आता नित्याच्या झाल्या आहेत. दूषित हवेच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक जगात खूप वरती लागतो ही शरमेची गोष्ट होय. जगातल्या २० अत्यंत प्रदूषित शहरात भारतातील १४ शहरे आहेत. त्यात दिल्ली, गाझियाबाद, बेगुसराई, नोइडा, फरीदाबाद, कानपूर आणि लखनऊ यांची गणना वारंवार होत असते. दिल्ली तर नागरी ऱ्हासाचे प्रतीक होऊन बसले आहे. अतिप्रदूषित शहरांची यादी ते सोडायला तयार नाही.

हवेचा दर्जा निर्देशांक नेहमी ४५० या पातळीच्या वर असतो. अशा हवेत श्वास घेणेही मुश्कील होऊन बसते. मुंबई शहराला सागरी हवेचा दिलासा मिळाला तरी आता तेही वारंवार ३००ची पातळी ओलांडते. कोलकाता २०० ते ३०० यादरम्यान हेलकावे खात असते. याचा अर्थ कोणतेही शहर प्रदूषणापासून अलिप्त राहिलेले नाही. एकामागून एक शहरात धूलिकणांची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमाणकापेक्षा २० ते २५ पट अधिक असते.

अशा संकटग्रस्त परिस्थितीत संसदेत यावेळी प्रदूषणाची सामूहिक अस्वस्थता पाहायला मिळाली. अविश्वसनीय वाटावी अशी संख्याशास्त्रीय आकडेवारी समोर घेऊन सभागृहात प्रदूषण या विषयावर चर्चा सुरू झाली. विरोधी बाकांनी उत्तर मागितले. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आधीच कडक निवेदने काढलेली आहेत. नागरिक आशा, निराशा, थकवा अशा स्थितीत काहीतरी घडेल याची वाट पाहत आहेत. या वळणावर संसदेच्या अलीकडे इतिहासात घडले नव्हते असे काहीतरी घडले. राजकीय कारकिर्दीत राहुल गांधी कधी पर्यावरण या विषयावर बोलले नव्हते; पण यावेळी ते कळकळीने, संतप्त भावनेने आणि त्याचवेळी सामंजस्याचा स्वर उमटवत बोलले. ताजा जागतिक हवा निर्देशांक उद्धृत करून त्यांनी असे जाहीर केले की वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. हा ऋतुमानानुसार उद्भवणारा त्रास नसून एक राष्ट्रीय आणीबाणी आहे अशा दृष्टीने सरकारने त्याकडे पाहावे, अशी मागणी राहुल यांनी केली.

काही वर्षांत प्रथमच विरोधी पक्षनेत्याने संपूर्ण सहकार्य देऊ केले. हवा स्वच्छ करण्यासाठी कोणतेही कठोर पाऊल उचलले तरी आपण सहकार्य करायला तयार आहोत, असे ते म्हणाले. एक व्यवहार्य, कालबद्ध अशी योजना पंतप्रधानांनी सभागृहापुढे

ठेवावी सर्व पक्षांनी तिला पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. श्वास घ्यायला स्वच्छ हवा मिळावी यासाठी राजकीय पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.

संसदेच्या सभागृहात त्याचे पडसाद उमटले. आज सभागृहात दंगा करायचा या तयारीने आलेले सदस्यही गप्प राहिले. सभागृहात एकप्रकारे आश्चर्यकारक अशी राजकीय युद्धबंदी झाली. पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी तत्काळ प्रतिसाद दिला. सरकार या विषयाच्या बाबतीत काहीच करत नाही हा आरोप त्यांनी फेटाळला. औद्योगिक क्षेत्रात निर्बंध कडक करण्यात आले आहेत. वाहनांनी होणाऱ्या प्रदूषणाविषयीची प्रमाणके बदलली आहेत. बांधकामाच्या ठिकाणी पाहणी केली जाते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विरोधक निवडक मुद्दे उचलून प्रदूषणाचे राजकीय भांडवल करत आहेत असा आरोप त्यांनी केला. मात्र संसदेच्या प्रांगणाबाहेरही प्रदूषण याच विषयावर सर्वजण बोलत राहिलेले दिसले. दम्याचा त्रास वाढत असल्याबद्दल बालरोगतज्ज्ञ इशारा देतात, तर शिक्षक वर्गाबाहेरचे उपक्रम रद्द करतात. रस्त्याने जाताना टॅक्सी ड्रायव्हर खोकत राहतात तर वयोवृद्धांना सकाळचा फेरफटका मारण्यासाठी घराबाहेर पडता येत नाही अशी स्थिती सगळीकडे दिसते आहे. इतकेच नव्हे तर न्यायालयेही या विषयामुळे अस्वस्थ झाली आहेत.

या विषयाच्या बाबतीत गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष होत आहे अशा शब्दात विविध राज्यांतील न्यायालयांनी सरकारला फटकारले. अधिकारी सतत काही ना काही कारणे पुढे करतात. त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव असून, अतिशय संथगतीने ते काम करतात असे न्यायालयाने ऐकवले. सार्वजनिक आरोग्य विषयाचे तज्ज्ञ आणि पर्यावरणवाद्यांनी सरकारवर राग काढला. यात अनपेक्षित असे काही नव्हते. वर्षानुवर्षे प्रदूषण नियंत्रणासाठी अर्थसंकल्पात केली गेलेली तरतूद पूर्णपणे किंवा अंशतः पडून आहे. या क्षेत्रातील कार्यकर्ते क्लेशदायी आकडेवारी समोर ठेवतात. राजकीय नेत्यांनी प्रदूषणाला युद्धपातळीवर हाताळण्याचा मुद्दा म्हणून स्वीकारले नाही तर काहीही बदल होणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रायः माणसांनी उभे केलेले हे संकट आहे. धोरण लकवा आणि प्रशासकीय बेपर्वाई याने त्यात भर टाकली आहे.

अर्थव्यवस्था वाढत आहे हे नक्की पण त्याचबरोबर प्रत्येक फुप्फुसात, प्रत्येक घराच्या छतावर धुळीचे थरही साचत आहेत. पण या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन भारताला गरज आहे ती प्रामाणिकपणाची ! हे संकट किती गंभीर आहे ते मान्य केले पाहिजे. आधीच्या चुका कबूल करून बदल स्वीकारला पाहिजे. कदाचित राहुल गांधींनी सहकार्याची भूमिका घेतली ती एकदम वेगळी वाटली याचे कारण हेच असावे. हे संकट आता भस्मासुरासारखे उभे राहिले आहे, हेच राहुल यांच्या देकाराने दाखवून दिले.

अन्वयार्थ

कोवळ्या वयात मित्राला संपवण्याची मानसिकता येते कुठून?

स्क्रीनशी नातं सांगणाऱ्या आजच्या मुलांची सहनशीलता कमी झाली आहे. किरकोळ वाद टोकाला जातात. यासाठी मुलांच्या भावनिक बदलांकडे लक्ष द्यावे लागेल.

सचिन कापसे
वृत्तसंपादक, लोकमत, पुणे

राजगुरुनगर येथे सोमवारी शिकवणी वर्गात दहावीच्या एका विद्यार्थ्याकडून दुसऱ्याचा खून झाल्याची घटना घडली. हा केवळ स्थानिक पातळीवरील गुन्हा नसून ती संपूर्ण समाजाला अस्वस्थ करणारी घटना आहे. शिक्षण ही प्रगती, सुरक्षितता, सकारात्मकता आणि उज्ज्वल भविष्यासाठीची प्रक्रिया मानली जाते. मात्र, अशाच शिकवणी वर्गात घडलेली ही हिंसक घटना मुलांच्या बदललेल्या भयावह मानसिकतेचे दर्शन घडवते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सर्वांत जास्त काम शाळकरी मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर करावे लागणार आहे. अगदी किरकोळ वाद मनात ठेवून एखाद्याला संपवण्याचा विचार कोवळ्या वयात गडद होत जातो, हे गंभीर आहे. ही घटना शिक्षणव्यवस्था, समाज आणि पालकांना गंभीर विचार करायला लावणारी आहे.

स्पर्धेच्या युगात आता शिकवणी वर्ग हे विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचे अविभाज्य भाग बनले आहेत. शाळा किंवा महाविद्यालयातून मिळणारे शिक्षण अपुरे आहे, अशा भावनेपोटी पालकच मुलांना शिकवणी वर्गात पाठवतात. परिणामी, हे वर्ग केवळ अभ्यासाचेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक आणि भावनिक आयुष्याचेही केंद्र बनतात. तिथे मुलांमध्ये मैत्री जुळते आणि शाळांच्या पलीकडे जाऊन पुन्हा एक नवी स्पर्धाही निर्माण होते.

विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा, परीक्षांचा, करिअरचा आणि अपेक्षांचा प्रचंड दबाव असतो. या दबावातून राग, नैराश्य, असुरक्षितता आणि हिंसक प्रवृत्ती वाढू लागते. शिकवणी वर्गामध्ये अनेकदा विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा तीव्र असते. गुण, तुलना, थट्टा-मस्करी किंवा अपमान यातून वैयक्तिक संघर्ष निर्माण होतात. योग्य समुपदेशन, संवाद आणि भावनिक आधार नसल्यास असे संघर्ष टोकाला जाऊन हिंसक वळण घेतात. राजगुरूनगरमध्येही नेमकं हेच घडलं.

तीन महिन्यांपासून शिकवणी वर्गातील मित्राबद्दल मनात ठेवलेला राग हिंसेत परावर्तित झाला आणि

अवघ्या १६ वर्षांच्या पुष्कर शिंगाडेला आपला जीव गमवावा लागला. कोवळ्या वयातील त्या मारेकरी मुलाला एवढं क्रूर बनवलं ते फक्त त्याच्या रागानं आणि रागाला कंट्रोल कसं करायला हवं, हे न शिकवणाऱ्या व्यवस्थेनं. ही खरेच काळजी करण्याची गोष्ट आहे.

स्क्रीनशी नातं सांगणाऱ्या आजच्या शाळकरी मुलांची सहनशीलता कमी आहे. किरकोळ वाद, गैरसमज किंवा अहंकाराचे प्रश्न या पिढीला अस्वस्थ करतात. त्यातून पुढे हिंसेच्या घटना घडतात. देशात २०२२ मध्ये १ लाख ६० हजारांपेक्षा जास्त शाळकरी मुलांवर गंभीर गुन्हे नोंदवले गेले होते. २०२३ मध्ये हे प्रमाण वाढून १ लाख ७७ हजारांपेक्षा जास्त वर गेले. ज्यात महाराष्ट्र अग्रस्थानी होते.

अनेक पालक मुलांच्या शैक्षणिक यशावरच लक्ष केंद्रित करतात; पण त्यांच्या मानसिक स्थितीकडे, मैत्रीच्या नात्यांकडे किंवा दैनंदिन अडचणींकडे दुर्लक्ष करतात. मुलांशी संवाद न साधणे, त्यांच्या भावना समजून न घेणे आणि अडचणी आल्यास योग्यवेळी हस्तक्षेप न करणे, यामुळे मुलं एकाकी पडतात. पालक, शिक्षक आणि शिक्षणव्यवस्था यांच्यात समन्वय नसेल, तर विद्यार्थ्यांची वाट चुकण्याचीच जास्त शक्यता असते.

या घटनेनंतर समाज म्हणून आपली जबाबदारी काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. केवळ आरोपी मुलाला शिक्षा देणे पुरेसे नाही, तर अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी योग्य उपाय करणे आवश्यक आहे. शाळा आणि शिकवणी वर्गामध्ये समुपदेशकांची नेमणूक, मानसिक आरोग्यावर कार्यशाळा, तणाव व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण आणि मूल्याधारित शिक्षणावर भर देणे गरजेचे आहे. तसेच हिंसाचाराविरोधात शून्य सहनशीलतेची भूमिका स्पष्टपणे रुजवली गेली पाहिजे. शिक्षणव्यवस्था, समाज, पालक आणि प्रशासन या चारही घटकांनी आत्मपरीक्षण करून ठोस पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात अशा घटना वाढू शकतात. प्रत्येक शाळा, शिकवणी वर्गात सुरक्षित, संवेदनशील आणि मानवतावादी वातावरण निर्माण करण्यासाठी यंत्रणेने पुढाकार घ्यायला हवा. पालकांनीही मुलांच्या भावनिक बदलांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. समुपदेशन, मानसोपचार तज्ज्ञ, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि खुला संवाद यांचा समन्वय साधल्याशिवाय अशा घटना थांबवता येणार नाहीत.

sachin.kapse@lokmat.com

जगभर

इमरान, जेमिमा गोल्डस्मिथ आणि इलॉन मस्क

इमरान खान यांनी केलेल्या प्रत्येक विवाहाची चर्चा झाली. पण सर्वात जास्त चर्चा झाली ती जेमिमा गोल्डस्मिथ यांच्यासोबत केलेल्या विवाहाची. ब्रिटिश टेलिव्हिजनवरील लेखक आणि निर्माता असलेल्या जेमिमा यांनी वयाच्या २१ व्या वर्षी आपल्यापेक्षा २० वर्षांनी मोठ्या असलेल्या इमरान यांच्याशी लग्न केलं. लग्नानंतर त्या पाकिस्तानात आल्या. तेथील माध्यमांनी जेमिमा यांच्यावर भरपूर टीका केली. सांस्कृतिक भेदामुळे जेव्हा नात्यामध्ये जुळवून घेणं अगदीच अशक्य झालं तेव्हा २००४ मध्ये इमरान आणि जेमिमा यांचा घटस्फोट झाला.

घटस्फोटानंतर त्या पुन्हा आपल्या दोन मुलांसोबत इंग्लंडमध्ये परतल्या. पाकिस्तानात पाकिस्तानी नसलेल्यांना जगणं किती अवघड असतं या विषयावर त्या सार्वजनिक पातळीवर अनेकदा नीडरपणे बोलल्या. जेमिमा यांचा हाच नीडरपणा राजकीय कैदेत असलेल्या इमरान खान यांच्यासाठी पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे. आता तर त्यांनी थेट इलॉन मस्क यांनाच त्यांनी दिलेल्या वचनाला जागण्याचं आवाहन केलं आहे.

२०२२ मध्ये इमरान खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात आले. त्यांना राजकीय कैदी बनवून एकांतवासात टाकण्यात आलं. तेव्हापासून इमरान यांच्याबद्दलची कोणतीही माहिती त्यांच्या नातेवाइकांना, समर्थकांना, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेली नाही. जेमिमा आणि इमरान यांना दोन मुलं आहेत. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून मुलांना आपल्या वडिलांना भेटायचं आणि पाहायचं आहे; पण त्यांना ते शक्य होत नाहीये. जेमिमा यांनी आपल्या पूर्वाश्रमीच्या पतीसाठी समाजमाध्यमांचा आधार घेतला. 'एक्स'वर इमरान यांना तुरुंगात न्याय्य वागणूक आणि मानवी हक्क

मिळण्यासाठी पोस्ट्स लिहिल्या. कालांतरानं त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांचा आवाज जगभरात जाऊ द्या, खुद्द पाकिस्तानातही पोहोचत नाहीये. 'एक्स'वर जेमिमा यांच्या इमरान यांच्यावरील पोस्टचा 'रिच' मर्यादित करून टाकला आहे. एक्सवरील या छुप्या मुस्कटदाबीमुळे जेमिमा यांनी इलॉन मस्क यांना थेट सार्वजनिरीत्या आवाहन केलं आहे.

त्यात त्यांनी म्हटलं आहे, 'इलॉन मस्क, मी जेमिमा खान. इमरान खान यांची पूर्वाश्रमीची पत्नी. आपण एकमेकांना भेटलोही आहोत. ट्विटर ताब्यात घेताना तुम्ही एक्सवर लोकांचं बोलण्याचं, अभिव्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपलं जाईल असं म्हणाला होतात. किमान त्या वचनाची तरी आठवण ठेवा आणि एक्सवरील माझ्या पोस्टचा रिच मर्यादित करण्याची जी मुस्कटदाबी सुरू आहे ती थांबवा'!

जेमिमा यांनी केवळ भावनेच्या भरात हे आवाहन केलेलं नाही. त्यासाठी त्यांनी एक्सचं एआय टूल 'ग्रोक'द्वारे मिळवलेली याबाबतची तपशीलवार आकडेवारीच मस्क यांना सादर केली आहे. २०२३-२४ मध्ये जेमिमा यांच्या पोस्टचा रिच ४०० ते ९०० मिलियन होता. पण जेव्हापासून त्यांनी इमरान यांच्या न्याय्य हक्कांबद्दल पोस्ट्स टाकायला सुरुवात केली तेव्हापासून त्यांच्या पोस्टचा रिच २८. ६ मिलियन इतका घसरला! त्यांचे १७ टक्के फॉलोअर्स कमी झाले.

आपल्या दुसऱ्या एका पोस्टमधून जेमिमा यांनी 'एक्स'सारखी मुक्त अभिव्यक्तीची जागा जिवंत राहायला हवी, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. जेमिमा यांची ही आशा जिवंत राहील किंवा नाही, याचं उत्तर येणारा काळच देणार आहे.

जनमन

शेतकरी महिलांच्या योगदानाचा सन्मान

संयुक्त राष्ट्र संघ दरवर्षी 'विशेष' वर्ष जाहीर करते. २०२६ हे वर्ष महिला शेतकऱ्यांचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. याचा मुख्य उद्देश शेतीत महिलांचे महत्त्वाचे योगदान अधोरेखित करणे, त्यांच्या समस्यांवर लक्ष वेधणे आणि अन्नसुरक्षा व आर्थिक स्वावलंबनात त्यांच्या भूमिकेची दखल घेणे हा आहे. महिला शेतकरी अन्नसुरक्षा, पोषण आणि आर्थिक लवचीकतेसाठी केंद्रस्थानी आहेत. महिला शेतकरी वर्ष त्यांच्या कार्याची जागरूकता वाढवेल आणि जगभरातील महिलांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि लिंगभेद कमी करण्यासाठी कृतींना प्रोत्साहन देईल.

या व्याख्येत औपचारिक आणि अनौपचारिक कामात महिलांचा समावेश आहे, जमिनीची मालकी किंवा रोजगाराची स्थिती काहीही असो, त्यांचे योगदान मान्य केले आहे. कृषी अन्नप्रणाली टिकवून ठेवण्यात नेतृत्व, काळजी, घरगुती काम यांसारख्या विविध आणि आवश्यक भूमिकांमध्ये महिलांचे योगदान मोठे आहे. लैंगिक असमानता कमी करण्यासाठी आणि कृषी अन्न प्रणालींमध्ये ग्रामीण महिलांना सक्षम करण्यासाठी सामाजिक संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची संधी म्हणून २०२६ हे वर्ष महिला शेतकरी आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. कृषी अन्नप्रणालींमध्ये महिला शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडथळ्यांना आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रभावी धोरणे आणि कृती स्वीकारण्यासाठी, तसेच लिंग समानता आणि शेतीमध्ये सर्व महिलांच्या सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेल.

- विजय देवधर, पुणे

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

दृष्टिक्षेप

डेटा सेंटर्सचा जगातला दादा कोण?

आज जवळपास प्रत्येक जण इंटरनेटचा वापर करतो, पण त्यासाठी महत्त्वाचे असतात डेटा सेंटर्स. डेटा सेंटर म्हणजे इंटरनेटचे 'बॅकएंड', जिथे तुमच्या सगळ्या ऑनलाइन गोष्टी जसं की, फोटो, व्हिडीओ, ई-मेल, बँकिंग माहिती.. सुरक्षित ठेवली जाते. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे डेटा सेंटर्स. यात सध्या तरी अमेरिका दादा आहे. जगात सर्वाधिक ४,१६५ डेटा सेंटर्स अमेरिकेत आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावरील ब्रिटनमध्ये केवळ ४९९ डेटा सेंटर्स आहेत!

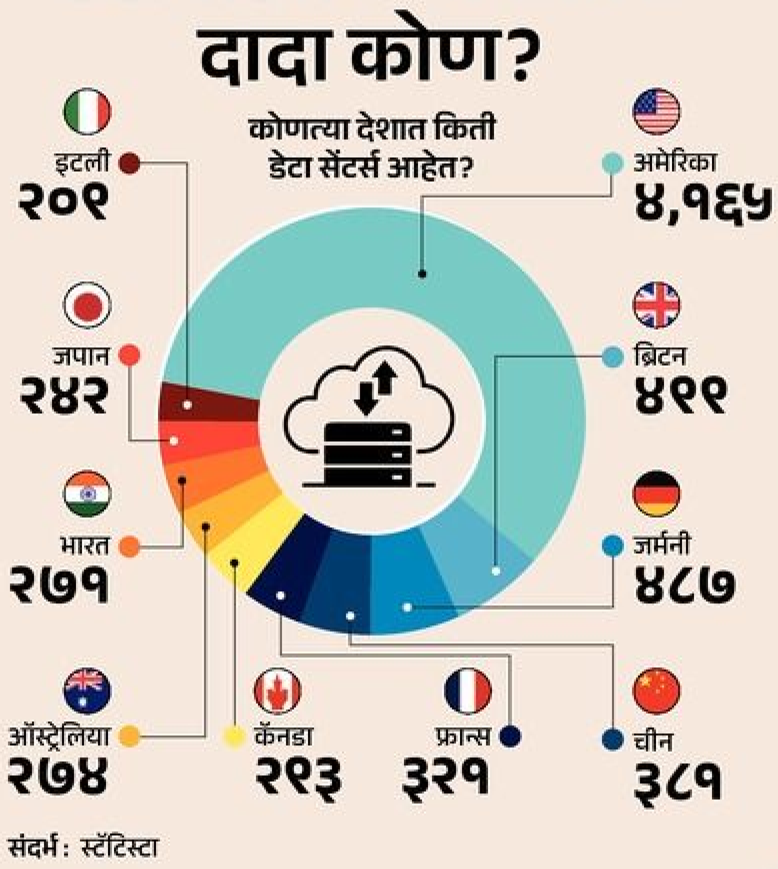

संदर्भ : स्टॅटिस्टा

हार-जीत

जन्मत:च जायबंदी असलेला ग्रीन नावाचा धुरंधर!

'मी जन्माला आलो तेव्हाच डॉक्टरांनी माझ्या आई-वडिलांना सांगितलं होतं की हे मूल १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ जगेल असं नाही, त्याला जन्मत:च किडनीचा आजार आहे. औषधं दिली तरी फार काळ जगणं-जगवणं अवघडच असेल! आता मी वयाच्या पंचविशीत पोहोचलोय, जे काही मला मिळतं आहे ते मी बोनस समजतो आणि आनंदाने जगतो!'

ऑस्ट्रेलियन ऑल राऊंडर कॅमेरॉन ग्रीनने एका मुलाखतीत ही गोष्ट सहज सांगितली. तो जितका बेडरपणे बॅटिंग-बॉलिंग करतो, तितकाच मनसोक्त खळखळून हसतो, त्याला कशाचीच भीती वाटत नसावी असा वागतो. यंदाच्या आयपीएल लिलावाची सुरुवात होण्यापूर्वीच चर्चा होती की ग्रीन कुणाकडे जाणार, कितीला जाणार? त्याला घेण्यासाठी सगळेच संघ आतुर झालेले होते.

कमालीच्या फॉर्ममध्ये असणारा हा खेळाडू. गेल्यावर्षी पाठीच्या दुखण्यामुळे, त्यात त्याचं ऑपरेशन झालं त्यामुळे तो आयपीएल खेळला नव्हता. यंदा मात्र आयपीएलमधला 'हाय डिमांड' खेळाडू म्हणून सगळे संघ आपले खिसे सावरत लिलावात उतरले. केकेआरनं तब्बल २५.२ कोटी रुपये मोजत त्याला ताफ्यात घेतलं.

पैसा, प्रसिद्धी त्याच्याकडे कमी नव्हतीच,

लोकप्रियताही भरपूर, पण असं ग्रीनकडे काय आहे की अन्य ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंपेक्षा त्याच्याचकडे डोळे लावून संघ आणि चाहते बसलेत?

तो धडाकेबाज ऑलराऊंडर आहे. मॅच फिरवू शकतो. पण त्याहून मोठी आहे त्याच्या जिद्दीची गोष्ट. जन्मत: किडनीचा आजार असल्याने त्याच्या खाण्यापिण्यावर अनेक बंधनं आहेत. त्याच्या किडनी जेमतेम ६० टक्के काम करतात. आजार बळावू नये म्हणून खाणंपिणं, व्यायाम सगळं सांभाळून खेळणं हे त्याच्यासाठी कायमच आव्हान होतं, आजही आहे. प्रवास, खाण्यापिण्याच्या वेळा, अमूकच पदार्थ खाणं, काही पदार्थ कधीच न खाणं हे सगळं त्याला सांभाळावं लागतं. आपल्याला दुर्धर आजार आहे, जो बराच होणार नाही हे माहीत असून एखाद्या खेळाडूनं खेळणं आणि उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून पत कमावणं सोपं नसतं.. ते जमलं तर तो कॅमेरॉन ग्रीन होतो.

- अनन्या भारद्वाज, मुक्त पत्रकार

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय** : लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५१३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय** : वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय** : पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

धुक्यात थांबला होता 'काळ' : ७ बस, ३ कार एकमेकांना धडकून १३ जण खाक

मथुरा : पहाटेचे साडेचार वाजले होते... दाट धुक्यात यमुना एक्स्प्रेस-वे गायब झाला होता.. याच धुक्यात जणू 'काळ' वाट पाहात होता... पुढचे काहीच दिसत नसल्याने वेगात येणाऱ्या ७ बस आणि ३ कार एकमेकांवर धडकल्या. त्यानंतर भीषण आगीचा भडका उडला आणि त्यात १३ जण जळून खाक झाले. ३५ जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत.

आग्रा - नोएडा मार्गावरील बलदेव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मंगळवारी (दि. १६) पहाटे हा अपघात झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आग इतकी भीषण होती की अनेक प्रवाशांना बसमधून बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. घटनास्थळावरून समोर आलेल्या दृश्यांमध्ये जळून खाक झालेल्या बसेसचे सांगाडे दिसत होते.

मदत जाहीर

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २ लाख रुपये, जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपये आर्थिक मदत जाहीर केली.

आगीनंतरचे दृश्य भयंकर

१. अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी अखेर आगीवर नियंत्रण मिळवले. त्यानंतर तेथील दृश्य भयंकर होते. बसमधून जळालेल्या अवस्थेतील सापळे आणि अर्धवट जळालेले मृतदेह बाहेर काढण्यात आले.

२. **आग इतकी प्रचंड होती की एक्स्प्रेसवेवरील पांढऱ्या रेषाही पूर्णपणे वितळून नष्ट झाल्या. काही मृतदेह बसच्या सिटांना चिकटलेल्या अवस्थेत आढळले. पोलिसांनी हे मृतदेह बसमधून बाहेर काढून १७ पिशव्यांत ठेवून शवविच्छेदनगृहात पाठवले.**

दाट धुक्यामुळे २५ जणांचा मृत्यू : उत्तर प्रदेशातील पाच जिल्ह्यांत दाट धुक्यामुळे झालेल्या वेगवेगळ्या रस्ते अपघातांत २५ जणांचा मृत्यू झाला असून, सुमारे १०९ जण जखमी झाले आहेत.

'गांधीजी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान'; विरोधकांचा तीव्र आक्षेप

२० वर्षे जुनी मनरेगा योजना बदलणारे विधेयक व्हीबी-जी राम जी लोकसभेत केले सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : दरवर्षी १२५ दिवस ग्रामीण रोजगाराची हमी देणारे आणि २० वर्षे जुनी मनरेगा योजना बदलण्याचा प्रस्ताव असलेले एक विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. मात्र, त्यामधून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकल्याबद्दल विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) म्हणजे व्हीबी-जी राम जी विधेयक, २०२५ असे या नव्या विधेयकाचे नाव असून, ते सादर करताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, केंद्र सरकार महात्मा गांधींवर केवळ विश्वासच ठेवत नाही, तर त्यांच्या तत्त्वांचे पालनही करते.

चौहान यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने केंद्रातील मागील सरकारांपेक्षा ग्रामीण विकासासाठी अधिक काम केले आहे. ते व्हीबी-जी राम जी विधेयक सादर करत असताना विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. हे विधेयक सखोल तपासणीसाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.

विरोधी पक्ष खासदारांची निदर्शने

मनरेगा योजनेच्या जागी व्हीबी-जी राम जी हे नवे विधेयक आणताना त्यातून महात्मा गांधी यांचे नाव वगळल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मंगळवारी संसद भवन परिसरात निदर्शने केली. तसेच 'गांधीजी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' अशा घोषणाही दिल्या.

केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे नाव बदलल्यावरून मंगळवारी काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे, कुमारी शैलजा यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेच्या गॅलरीत आंदोलन केले. हे प्रथमच घडले.

गरिबांच्या रोजगाराच्या हक्कावर गदा : प्रियांका

काँग्रेसच्या सरचिटणीस व खासदार प्रियांका गांधी यांनी सांगितले की, व्हीबी-जी राम जी हे नवे विधेयक गरिबांच्या रोजगाराच्या हक्कांवर गदा आणत असून, हे कृत्य घटनाविरोधी आहे. मनरेगा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार या योजनेंतर्गत होणाऱ्या कामांसाठी ९० टक्के निधी देते. आता तो ६० टक्क्यांवर आणला जाणार आहे.

'देखो ओ दीवानो... राम का नाम बदनाम ना करो'

काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी व्हीबी-जी राम जी विधेयकाबाबत एका हिंदी गाण्याचा आधार घेऊन टीका केली. 'देखो ओ दीवानो (तुम) ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो' या १९७१ साली गाजलेल्या गाण्याचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, नवे विधेयक म्हणजे मनरेगावरच घाव घालण्यात आला आहे.

काँग्रेसने काढला व्हिप : लोकसभेत येत्या काही दिवसांत महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा आणि मंजुरी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काँग्रेसने मंगळवारी व्हिप जारी केला. पक्षाने आपल्या सर्व खासदारांना पुढील तीन दिवस सभागृहात अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे व्हीबी-जी राम जी विधेयकात?

ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल स्वरूपाचे काम करण्यास स्वेच्छेने तयार असतील, त्या कुटुंबाला दर आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी या विधेयकाद्वारे दिली जाईल.

व्हीबी- जी राम जी कायदा लागू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, राज्यांना नव्या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत अशी योजना तयार करावी लागेल.

चार मुख्य उद्दिष्टे व्हीबी-जी राम जी योजनेद्वारे साध्य करण्यात येतील.

गरिबांच्या उपजीविका संपविण्याचा डाव

व्हीबी-जी राम जी हे नवे विधेयक हा महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा अपमान आहे, अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केली. केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील गरिबांची उपजीविका सुरक्षित राखणारी योजना संपविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही केला.

उच्चशिक्षणासाठी एकच नियामक मंडळ असेल तर...

लोकमत इन्फो स्टोरी

नवी दिल्ली : देशातील उच्चशिक्षणावर एकच नियामक मंडळ स्थापन करण्यासंदर्भातील 'विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक' मंगळवारी १३ जणांच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या संदर्भातील प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. त्याला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली.

अहवाल कधी येणार? : सोमवारी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. आता हे विधेयक लोकसभा व राज्यसभेतून निवडलेल्या २१ जणांच्या समितीकडे विचाराधीन पाठवण्यात आले आहे. ही समिती या संदर्भातील आपला अहवाल पुढील वर्षी अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या सत्राच्या अखेरच्या दिवशी सरकारला सादर करणार आहे.

या विधेयकामुळे नेमके काय बदल होणार आहेत?

१. यूजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई, पीसीआय बरखास्त केले जातील. पण नॅशनल मेडिकल कौन्सिल अंतर्गत येणारे वैद्यकीय शिक्षण आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया अंतर्गत येणारे कायद्याचे शिक्षण यात बदल केला जाणार नाही. इतर सर्व उच्चशिक्षण एकाच छत्राखाली येईल.

२. **नव्या विधेयकानुसार एकच राष्ट्रीय अध्यक्ष असेल. त्याच्या अधीन नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी कौन्सिल, नॅशनल ॲक्रिडिटेशन कौन्सिल, हायर एज्युकेशन ग्रँट्स कौन्सिल, जनरल एज्युकेशन कौन्सिल अशा चार परिषद असतील. प्रत्येकाचा स्वतंत्र प्रमुख असेल. तसेच नियमन, मानांकन, निधी आणि अभ्यासक्रम हे सर्व आता एकमेकांपासून वेगळे असतील.**

३. इंजिनीअरिंग, फार्मसी, आर्किटेक्चर, बिझनेस मॅनेजमेंट-बिझनेस स्कूल, हॉटेल मॅनेजमेंट व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांचे मानांकन सुरूच राहील.

मानांकन कसे होणार?

इंजिनीअरिंगचे मानांकन वॉशिंग्टन अकॉर्डशी संलग्न असेल. गुणांकनावर आधारित मानांकन सुरूच राहील.

निधीवाटपाबाबत उच्चशिक्षण आयोग नियम व प्रक्रिया ठरवेल. निधी प्रत्यक्ष शिक्षण खात्याकडून वितरित होईल.

एनएएसी (नॅक) आणि एनबीए बरखास्त होऊन नॅशनल ॲक्रिडिटेशन कौन्सिलमध्ये विलीन केल्या जातील.

मूल्यांकन आता तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणार

कागदपत्रे, भेटी आणि व्यक्तिनिष्ठ निर्णयांवर अवलंबून असलेले मूल्यांकन आता तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहील. मानांकने पूर्णतः डिजिटल असेल प्रत्यक्ष तपासण्या होणार नाहीत. डेटा व डॅश बोर्डवर आधारित मूल्यांकन होईल. याने पारदर्शकता वाढेल, मनमानी होणार नाही, व्यवस्था अधिक लोकोपयोगी बनले.

लोकमत संसदीय पुरस्काराचा दिमाखदार सोहळा आज दिल्लीत

(पान १ वरुन) उपस्थित राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची खास उपस्थिती राहणार आहेत. लोकमत मीडिया समुहाचे चेअरमन डॉ. विजय दर्डा आणि लोकमतचे एडिटर-इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडणार आहे.

याशिवाय, लोकमत कॉन्क्लेव्हमध्ये दोन विषयांवर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे. पहिले चर्चासत्र दुपारी तीन वाजेपासून सुरू होईल. 'फ्रीबिज बिफोर पोल्स – अ बून ऑर बेन' या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे आणि राज्यसभेचे खासदार प्रो. मनोजकुमार झा आपले मत व्यक्त करतील. तर दुसरे चर्चासत्र सव्वा चार वाजेपासून सुरू होणार आहे. 'चॅलेंजस बिफोर कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज' या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई, माजी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी आणि राज्यसभेचे खासदार डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी आपले मत मांडतील. यंदाच्या ज्युरी मंडळामध्ये माजी केंद्रीय उड्डाण मंत्री प्रफुल्ल पटेल (अध्यक्ष), लोकसभेचे खासदार प्रो. सौगत राय, भतृहरी मेहताब, डॉ. निशिकांत दुबे, कनिमोझी करूणानिधी, राज्यसभेचे खासदार डॉ. सस्मित पात्रा, जया बच्चन, डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त, लोकमत मीडिया समुहाचे चेअरमन डॉ. विजय दर्डा आणि नॅशनल संपादक हरिश गुप्ता यांचा समावेश होता.

गोवा अग्निकांड : लुथरा बंधूंचे प्रत्यार्पण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : गोव्यातील नाइट क्लबमध्ये झालेल्या अग्निकांड प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि क्लबचे सहमालक असलेले गौरव लुथरा (४४) आणि सौरभ लुथरा (४०) या दोन्ही भावांना अखेर भारतात आणण्यात आले.

ते दिल्लीत उतरताच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना दिल्ली न्यायालयाने दोन दिवसांचा ट्रान्झिट रिमांड दिला आहे. ६ डिसेंबर रोजी उत्तर गोव्यातील आर्पोरा येथील 'बर्च बाय रोमिओ लेन' या नाइट क्लबमध्ये भीषण आग लागून २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. गोवा पोलिसांनी लुथरा बंधूंविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

विजय दिवसानिमित्त शूरांना आदरांजली

१९७१च्या युद्धात पाकिस्तानवर मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयानिमित्त आज देशभर 'विजय दिवस' साजरा केला जात आहे. यानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेत्यांनी भारतीय सशस्त्र दलांच्या शौर्याला सलाम केला असून शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. तर उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज येथे लहान मुलांनी सैनिकांचा वेश परिधान करून विजय दिवसानिमित्त शहिदांना आदरांजली वाहिली.

विमानांना धुक्याचा फटका; दिल्लीतील १३१ उड्डाणे रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दाट धुक्यामुळे निर्माण झालेल्या कमी दृश्यतेचा फटका मंगळवारी दिल्ली विमानतळावरील विमानसेवेला बसला. या परिस्थितीमुळे ४९ विमानांचे उड्डाण आणि ७७ विमानांचे लँडिंग रद्द करण्यात आले, अशी माहिती दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. एकूण १३१ उड्डाणे रद्द झाली.

इंडिगोनेही खराब हवामानामुळे ११० उड्डाणे रद्द केल्याचे जाहीर केले. दिल्ली विमानतळावरील धुक्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.

रेल्वेंच्या वेगाला ब्रेक, अनेक गाड्या विलंबाने

थंडी आणि धुक्यामुळे उत्तर भारतात, विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली राजधानी क्षेत्रात वाहतुकीवर परिणाम झाला असून उत्तर प्रदेशात अनेक रेल्वेचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे या गाड्या विलंबाने धावत आहेत.

दरम्यान, उत्तर प्रदेशात राजधानी एक्स्प्रेससह अनेक रेल्वे १०-१० तास उशिराने धावत आहेत. दाट धुक्याचा परिणाम रेल्वेसह रस्ते वाहतुकीवरही झाला आहे. बिहारमध्ये पारा सातत्याने उतरत असून एक आठवड्यानंतर गोठवणारी थंडी पडेल, असा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. शिवाय या राज्यात सकाळ-संध्याकाळी दाट धुक्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

✔ फॅक्टCheck

सानियाच्या मुलाला नागरिकत्व नाही

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असा दावा केला जात आहे की, सानिया मिर्झा व शोएब मलिक यांच्या घटस्फोटानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी ट्वीट केले की, "सानिया मिर्झा व तिच्या 'पाकिस्तानी मुलाला' कोणत्याही परिस्थितीत भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार नाही. कोणाच्या मूर्खपणाचे परिणाम भारत भोगणार नाही." या व्हायरल पोस्टची सत्यता पडताळली असता सरमा यांच्या नावावर खोटे विधान पसरवून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. सानिया किंवा तिच्या मुलाच्या नागरिकतेबाबत सरमांनी असे कोणतेही वादग्रस्त विधान केलेले नाही.

सोशलViral

महिला फक्त मुलं जन्माला घालण्यासाठी

केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर एका ज्येष्ठ माकपा नेत्याने महिलांबद्दल अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन विधान केले आहे. माकपाचे माजी स्थानिक सचिव सय्यद अली मजीद यांनी मुस्लीम लीगने महिला उमेदवार उभे केल्याबद्दल टीका केली. ते म्हणाले, "मते मिळविण्यासाठी किंवा वॉर्ड जिंकण्यासाठी आम्ही आमच्या महिलांना दुसऱ्या पुरुषांसमोर परेड करायला लावत नाही. आमच्याकडेही विवाहित महिला आहेत; पण, त्या पतीसोबत राहण्यासाठी आणि मुले जन्माला घालण्यासाठी आहेत."

सोशलTrending

पॅलेस नव्हे 'पत्रिके'मुळे चर्चेत आलं लग्न

सध्या सोशल मीडियावर एका लग्नाच्या पत्रिकेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या लग्नात ना भव्य सजावट चर्चेचा विषय ठरली, ना मोठा गाजावाजा. चर्चा रंगली ती लग्नाच्या पत्रिकेवर छापलेल्या आडनावाची – 'मोहम्मद खालिद दुबे'. या कुटुंबाचा इतिहास १६६९ पासूनचा आहे. त्यांचे पूर्वज आझमगडचे जमीनदार लालबहादूर दुबे होते. काळाच्या ओघात कुटुंबाचा धर्म बदलला, पण त्यांनी आपली मूळ ओळख आणि पूर्वजांचे 'दुबे' हे आडनाव कायम ठेवले. "धर्म बदलू शकतो, पण पूर्वज बदलत नाहीत," असे कुटुंबातील सदस्य नौशाद अहमद दुबे अभिमानाने सांगतात.

स्टॅच्यु ऑफ लिबर्टीची ब्राझिलमधील प्रतिकृती कोसळली

गुआइबा : अमेरिकेतील स्टॅच्यु ऑफ लिबर्टीची ब्राझिलमधील एका रिटेल स्टोअरच्या पार्किंगमध्ये उभारलेली २४ मीटर उंचीची प्रतिकृती वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याच्या तडाख्यामुळे कोसळली. ही घटना रिओ ग्रांडे दो सुल या राज्यातील पोर्टो अलेग्रेजवळील गुआइबा शहरात घडली. सोमवारी घडलेल्या या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, यासंदर्भातील व्हिडीओत ही प्रतिकृती वाऱ्याच्या तडाख्यामुळे झुकताना व नंतर जमिनीवर कोसळताना दिसते. मात्र, त्यावेळी आजूबाजूला माणसांची वर्दळ नसल्याने कोणालाही इजा झाली नाही. सोमवारी या भागात ताशी ९० किमीपेक्षा जास्त वेगाने वारे वाहत होते.

मस्ट READ

ब्रिटनमध्ये 'नो एन्ट्री' : व्हिसाचे नियम कडक; ६७ टक्क्यांची मोठी कपात, आयटी, हेल्थ प्रोफेशनल्सना मोठा झटका!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : ब्रिटन सरकारने आपल्या इमिग्रेशन (स्थलांतर) धोरणात केलेल्या आमूलाग्र बदलांमुळे भारतीयांना जारी करण्यात येणाऱ्या वर्क व्हिसामध्ये तब्बल ६७ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

या कपातीचा सर्वाधिक परिणाम आरोग्य सेवा क्षेत्रावर झाला आहे. नर्सिंग क्षेत्रातील भारतीयांना मिळणाऱ्या व्हिसामध्ये ७९ टक्क्यांची विक्रमी घट झाली असून, ही संख्या केवळ २,२२५ वर आली आहे.

प्रमुख क्षेत्रांतील व्हिसा कपात

क्षेत्र/पेशा	घट (%)	जारी व्हिसा
आरोग्य सेवा	६७%	१६,६०६
नर्सिंग	७९%	२,२२५
आयटी	२०%	१०,०५१

व्हिसाच्या कडक नियमांचा परिणाम काय?

१. भारतीयांच्या व्हिसा संख्येत झालेल्या या मोठ्या घसरणीमागे २२ जुलै २०२५पासून ब्रिटनने लागू केलेल्या नवीन इमिग्रेशन (स्थलांतर) सुधारणा कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे.

२. **किमान वेतन मर्यादेत वाढ :** 'स्किल्ड वर्कर व्हिसा'साठी आवश्यक असलेल्या किमान पगाराच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यम स्तरावरील व्यावसायिकांसाठी व्हिसा मिळवणे आता कठीण झाले आहे.

३. **पात्र व्यवसायांच्या यादीत कपात :** स्किल्ड वर्कर आणि 'हेल्थ अँड केअर वर्कर' व्हिसाअंतर्गत येणाऱ्या पात्र व्यवसायांची यादी आता मर्यादित करण्यात आली आहे.

४. **डिपेंडंट व्हिसात बदल :** कुटुंबीयांना सोबत नेण्याबाबतचे (डिपेंडंट व्हिसा) नियम अधिक कडक केले आहेत, ज्यामुळे आता सहकुटुंब स्थलांतर करण्याचे पर्याय मर्यादित झाले आहेत.

मोबिलिटी करार आणि एफटीए अद्याप प्रभावी

ब्रिटनने व्हिसा नियम कडक केले असले तरी मे २०२१मध्ये झालेला 'मायग्रेशन अँड मोबिलिटी पार्टनरशिप' हा करार आजही लागू आहे.

या करारांतर्गत १८ ते ३० वयोगटातील भारतीय तरुणांना दोन वर्षांसाठी ब्रिटनमध्ये राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळते.

याशिवाय, नुकत्याच स्वाक्षरी झालेल्या मुक्त व्यापार कराराला (एफटीए) सध्या ब्रिटिश संसदेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. - त्यानंतर भारतीय व्यावसायिकांना काही दरवाजे पुन्हा उघडण्याची शक्यता आहे.

हमेशा किसी को खुश करने के मौके ढूंढते रहें और रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अच्छा करते रहें। - रॉय टी बेनेट

केंद्र सरकार की नई 'विकसित भारत-जी-राम-जी' योजना में मनरेगा की उन कमियों को दूर करने की कोशिश दिखती है, जो संप्रग काल से ही बहस का मुद्दा बनी हुई हैं। अब जरूरी है कि सरकार व विपक्ष मिलकर यह सुनिश्चित करें कि नई योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण का माध्यम बने।

मनरेगा से आगे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या वीबी-जी-राम-जी नामक नई योजना लाने की केंद्र सरकार की तैयारियों ने नीति, राजनीति और समाज, तीनों स्तरों पर बहस को तेज कर दिया है। संदेह नहीं कि दो दशकों से भी अधिक समय से मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए सुरक्षित आय का साधन तो रहा ही है, इसके साथ ही इसने पलायन रोकने, ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और सामाजिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इसकी पुष्टि खुद ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मनरेगा के महत्व को स्वीकारने से भी होती है। ऐसे में, किसी नए कानून की पहल तभी सार्थक मानी जाएगी, जब वह मनरेगा की उपलब्धियों को संरक्षित करते हुए उसकी कमियों का समाधान करे। मनरेगा के लंबे अनुभव से पता चलता है कि हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों के रोजगार का मूल वादा कई बार कागजों पर ही सीमित रह जाता है। इसमें भुगतान में देरी, मांग-आधारित रोजगार की अनदेखी और बजट आवंटन में कटौती जैसी चुनौतियां भी सामने आईं। ऐसे में, प्रस्तावित विधेयक में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रावधान सराहनीय है। इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी से लेकर एआई जैसी तकनीकों तक के उपयोग के प्रावधान भी स्वागतयोग्य हैं। जो प्रमुख बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें कृषि के चरम मौसमों के दौरान योजना को रोकना और इसे केंद्र द्वारा वित्तपोषित मॉडल से हटाकर राज्यों के साथ लागत-साझाकरण व्यवस्था में बदलना भी शामिल है। कांग्रेस समेत विपक्ष इसके लिए सरकार की आलोचना कर तो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मुद्दे संप्रग काल में भी बहस के केंद्र में रहे थे। संप्रग के दूसरे कार्यकाल में 2011 में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने मनरेगा कार्यों को बुआई व कटाई के वक्त रोकने की मांग की थी, क्योंकि इससे खेतों में जरूरत पड़ने पर मजदूर नहीं मिल पाते थे। इसी तरह मनरेगा के बजट का कुछ हिस्सा राज्यों द्वारा वहन किए जाने का सुझाव भी संप्रग के भीतर से ही निकला था। लागत में साझेदारी से निस्संदेह राज्यों में जवाबदेही बढ़ेगी और दुरुपयोग भी कम होगा। लिहाजा प्रस्तावित विधेयक पहले से दिए जा रहे इन्हीं सुझावों का विस्तार ही अधिक दिखता है। विकसित भारत के सपने के पूरा होने के लिए जरूरी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत और समावेशी बने। उतना ही जरूरी यह भी है कि राजनीतिक द्वंद्व से ऊपर उठकर सरकार और विपक्ष मिलकर इस दिशा में काम करें।

मास्क, मुस्कुराहट और नया साल

क्या नए साल पर मास्क के साथ मुस्कुराना सीखना होगा? सभी को समझना होगा कि दिल्ली और एनसीआर सिर्फ मास्क, वैक्सीन तथा एयर प्यूरीफायर से ही नहीं बचेंगे। इसके लिए सबकी मुस्कुराहट व खुशी को बचाना होगा, जिसके लिए जरूरी है कि हर स्तर पर कोशिशें हों।

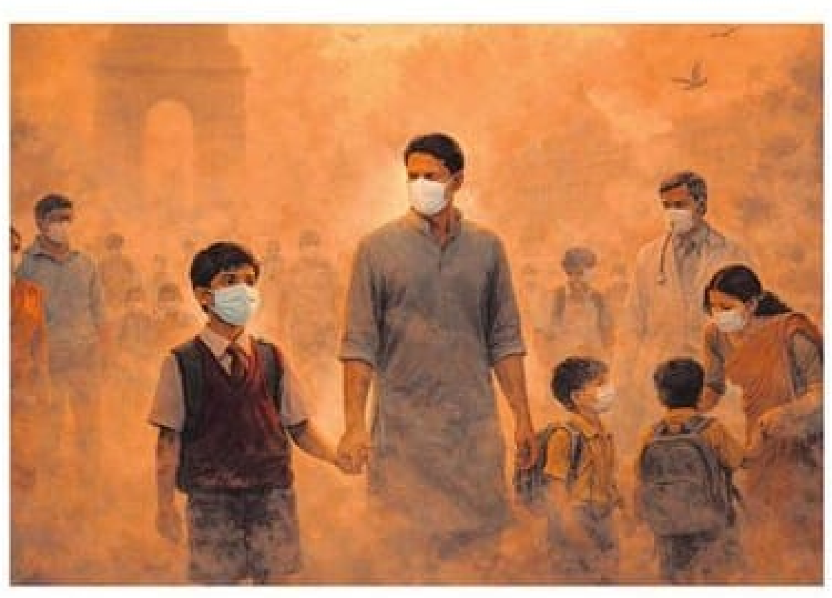

लेख की शुरुआत उस शेर से, जो इस शहर का हाल बयां करता है और उन रहगुजर की भी, 'चेहरे पे सारे शहर के गर्द-ए-मलाल है, जो दिल का हाल है, वही दिल्ली का हाल है!' दिसंबर से लेकर जनवरी तक यह गर्द-ए-मलाल हमारी मुस्कुराहट पर धुंध लगाने जा रही है। ऐसा लगता है, मानो नए साल में हमें मास्क संग फिर से मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और संसद में सभी दल एकजुटता के साथ अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उधर डर से लोग दिल्ली और एनसीआर छोड़ भी रहे हैं। तो क्या फिर से कोविड की तरह यह शहर मास्क में कैद हो जाएगा? क्या दिल्ली की सड़कें और दीवारें फिर से सूनी हो जाएंगी? फिर उन संघर्षों की कहानी कौन लिखेगा, जिसकी गवाही दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा बनेगी?

नन्दितेश निलय
स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

मुझे लगता है कि वह कहानी लिखी जाएगी, हर उस व्यक्ति द्वारा, जो इस शहर में फिर से मास्क लगाना सीख रहा है। लेकिन यह भी कम चिंता की बात नहीं है कि फेफड़ों को बचाते-बचाते वह व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट भी खोता चला जाएगा। ऐसा लगता है, जैसे कि कोविड के बाद फिर से इस दुनिया को उस मास्क से अपने चेहरे को छिपाना सीखना पड़ेगा, जिससे इस दमघोंटू हवा में फेफड़ा बच सके। महामारी के बाद प्रदूषण में फंसा यह शहर मानो सबसे कह रहा है कि मुस्कराने के दिन चले गए! आखिर चेहरे पर मास्क जो आ गया है। तो फिर उस मानवीय सभ्यता की मुस्कुराहट का क्या होगा? आखिर फिर मुस्कराया कैसे जाएगा?

जिस दुनिया में साफ पानी खरीदने की होड़ लगी है, उस दुनिया में एयर प्यूरीफायर कितनों की मुस्कान वापस ला पाएगा? और इन सबके बीच मास्क में हजारों स्कूल जाते बच्चे अपनी मुस्कुराहट कैसे साझा करना सीखेंगे? वह पिता, वह मां, वह मनुष्य, कहां से वह मन, वह जीवन जीने की जिजीविषा लाएगा, जिसमें थोड़ी हंसी और मुस्कुराहट एक आशा बन जाती है। तो फिर क्या किया जाए, जिससे इस जहरीली हवा में कैद एनसीआर का हर बच्चा, हर व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट न भूल जाए?

कोविड ने हमें जीवन का दर्शन दिया और अकेले रहने के लिए मजबूर किया। मनुष्य को परिवार से दूर कर दिया। मास्क से ढके चेहरों को यह महसूस हुआ कि कोई मास्क समाज में ऑक्सीजन का काम तो करता है, लेकिन वह हंसी भी छीन लेता है। अपने परिवार, साथी और किसी बेहद खूबसूरत परिदृश्य को देखकर लोगों का मुस्कुराना, खिलखिलाना मास्क में ही कैद हो जाता है। प्रदूषण के स्तर को कम करने की बातें, तो कई वर्षों से चल रही हैं, लेकिन अगर मास्क ही असली चेहरा बन जाएगा, तो फिर खुशी की इस अभिव्यक्ति का क्या होगा, जो जीवन की उम्मीद है!

मुझे लगता है कि यह वक्त आत्मचिंतन का है और यह भी कि अगर हम सभी उस हंसी, उस मुस्कुराहट को मानवीय समाज में बचाए रखने के लिए प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका समझें। आखिर दुनिया यह सोचकर हंसने के क्लब में जाती है कि दिन भर की भाग-दौड़ के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, मन खुश होगा। पर मास्क तो सब पर प्रतिबंध लगा देगा। बस सांस चलती रहेगी! और दुनिया दूसरों के जीवन में जो आशा व संचार उस मुस्कुराहट से देती आई है, वह तो कहीं अदृश्य-सा हो जाएगा।

यह कल्पना से परे होगा कि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को हंसते हुए न देखे, मुस्कुराते हुए अभिवादन न कर सके। भले ही सांसें उस प्रदूषण से बचती रहें, लेकिन जब एक हारा हुआ मरीज अपने डॉक्टर की ओर देखेगा, तो मास्क में कैद डॉक्टर उससे कुछ कह नहीं पाएगा। स्कूल में, पार्क में, दौड़ते-चिल्लाते बच्चे कैसे उस वॉल्ट डिज्नी को मुस्कुराकर याद कर पाएंगे, जिसकी कल्पना बच्चों की मुस्कुराहट को महसूस करके ही की गई थी। वे चाहते थे कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां बच्चे खिलखिलाकर हंस सकें।

जो भी हो, पर इस डरावने प्रदूषण में अपने चेहरे को मास्क से छिपाकर तो रखना होगा, मुस्कुराने की आदत को बचाए रखना होगा। जरूरत होगी उस भाव को मन में समेटने की, जो जीवन को सिर्फ जीवन ही मानता है और मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। हम निःस्वार्थ सेवा और प्रेम के मानवीय मूल्य से भले मास्क में ही सही, पर मुस्कुरा सकते हैं, और उनको भी मुस्कुराना सिखा सकते हैं।

कोविड के बाद कई देशों में ऐसा हुआ कि मास्क हटते ही लोग मुस्कुराना भूल गए। जापान समेत कई देशों में उन शिक्षकों की खोज होने लगी, जो मुस्कुराना सिखा सकें। इसलिए दुनिया सिर्फ शहर छोड़ने, एयर प्यूरीफायर लगाने या मास्क में कैद होने भर से तो नहीं बच सकती। मनुष्य दूसरों को अपनी उपस्थिति से जो खुशी और उत्साह देता है, वही जीवन-दर्शन बन जाता है। इसलिए भले ही चेहरा मास्क से ढका हो, लेकिन मास्क के अंदर कैद उस मुस्कुराहट को परिवार के संग ज्यादा बांटने की जरूरत है। अगर एक-दूसरे के लिए, शहर और समाज के लिए कुछ ज्यादा जिम्मेदारी का भाव आ जाए, तो मास्क में अदृश्य मुस्कुराहट भी किसी को उस खुशी का एहसास दे सकती है।

इसलिए हमें मास्क में दमघोंटू हवा के बीच मुस्कुराते रहना सीखना होगा। यह मुश्किल भरा क्षण है और हमें आत्मचिंतन और बोध के भाव से कभी शिक्षक, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी नौकरशाह, कभी जज, तो कभी आम नागरिक बनकर इस शहर में जीना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए उनके पास कोई रामबाण नहीं है, यानी हर स्तर पर कोशिश होनी चाहिए। और एक कोशिश मास्क और चेहरे के बीच फंसी उस मुस्कान को बचाने की होनी चाहिए।

कोई भी खुशी या मुस्कुराहट उस प्रेम और सेवा से ही वापस आ सकती है, जो इस पोस्ट-कोविड दुनिया में अब बढ़ते प्रदूषण में कहीं खो चुकी है। सभी को समझना होगा कि दिल्ली और एनसीआर सिर्फ मास्क, वैक्सीन और एयर प्यूरीफायर से ही नहीं बचेगा, बल्कि सबकी मुस्कुराहट और खुशी को बचाकर बचेगा। तभी मास्क के पीछे उन चेहरों में जीवन की संभावनाएं रह जाएंगी।

नए साल के स्वागत में मास्क संग ही सही, पर मुस्कुराना और शुभकामनाओं का दौर जारी रहेगा। मत भूलिए कि हंसना-मुस्कुराना इन्सानी अभिव्यक्ति है। चाहे वह मुस्कुराहट मास्क में छिपी हो या शहर की धूल में! जीवन रुकना नहीं चाहिए और न मुस्कुराना।

सफर जारी रहे... edit@amarujala.com

जीवन धारा

सिमोन बोलिवर

हर मनुष्य के भीतर एक क्रांतिकारी आत्मा सोई रहती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जब यह जागृत होती है, तब असफलताएं सबक बन जाती हैं, संघर्ष साधना बन जाता है व जीवन आत्मविश्वास से भरी यात्रा।

मन की आवाज सुनने वाला ही विजेता होता है

हर युग में कुछ ऐसे विचार जन्म लेते हैं, जो मशाल बनकर रास्ता दिखाते हैं। वे बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी हथियार से नहीं, बल्कि अडिग संकल्प और निर्भीक आत्मविश्वास से हासिल की जाती है। जब मनुष्य अपने भीतर की स्वतंत्र चेतना को पहचान लेता है, तब कोई भी ताकत उसे लंबे समय तक बांध नहीं सकती। स्वतंत्रता कोई सहज वरदान नहीं, बल्कि वह संघर्ष की भूमि में ही पुष्पित होती है। उसके लिए त्याग चाहिए, श्रम चाहिए और वह साहस चाहिए, जिससे इन्सान चुनौतियों से भागे नहीं, बल्कि उसे सहज रूप से स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे।

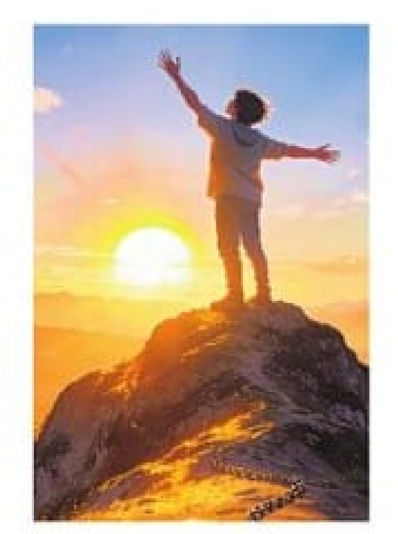

जो बिना कोशिश या चुनौती स्वीकार किए सफलता पाना चाहते हैं, वे जीवन के सबसे खूबसूरत अर्थ को खो देते हैं। इसलिए हमें अपने भय, संदेह और सीमाओं से परे जाना होगा, क्योंकि वास्तविक जीत हमारी सोच की आजादी में ही छिपी होती है। जीवन हमें बार-बार यह सिखाता है कि जो कुछ पाने योग्य है, उसके लिए कुछ छोड़ने का साहस भी रखना पड़ता है। स्वतंत्रता का असली अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी सोच, कर्म और सपनों को खुली उड़ान देना भी है।

बेशक हर बदलाव पीड़ादायक होता है, पर वही पीड़ा मनुष्य को मजबूत सांचे में ढालती है। जो इन्सान अपने भीतर परिवर्तन ला सकता है, वही दूसरों के हृदय में भी आशा का संचार कर पाता है। सच्चा नेतृत्व आदेश से नहीं, बल्कि प्रेरणा से जन्म लेता है और जो किसी दूसरे के मन में उम्मीद का दीप जला देता है, असली मायने में वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जब परिस्थितियां इन्सान को तोड़ने लगें, तब उसे अपने मन की दृढ़ता को ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र बना लेना चाहिए। समय हमें नए विचार, नई चेतना और नए विवेक की ओर बुला रहा है। इस राह पर शिक्षा और ज्ञान ही वह शक्ति हैं, जो अज्ञान और अन्याय, दोनों प्रकार की गुलामी से मुक्ति दिलाती हैं। सीखने की आग और सोचने का साहस ही विकास की असली नींव है।

हर मनुष्य के भीतर एक क्रांतिकारी आत्मा सोई रहती है, बस उसे जगाने के लिए केवल एक उद्देश्य की चिंगारी चाहिए। जब यह चेतना प्रज्वलित होती है, तब असफलताएं सबक बन जाती हैं, संघर्ष साधना बन जाता है और जीवन आत्मविश्वास से भरी यात्रा में बदल जाता है। स्वतंत्रता कोई एक दिन में मिलने वाला उपहार नहीं, यह रोज अर्जित होने वाली साधना है-हर निर्णय में, हर प्रयास में, हर निर्भीक कदम में। जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, वह केवल अपना नहीं, कई जीवनों का मार्ग आलोकित कर देता है। आज की पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि अपने सपनों पर भरोसा रखो, अपने विचारों को निर्भय उड़ान दो और आत्मा की स्वतंत्रता से संसार में नई ऊर्जा का संचार करो। जो अपने जीवन के उद्देश्य को जान लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त और विजयी होता है।

सोच को पंख दें

सूत्र

जीवन का सच यही है कि जीत हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति और संकल्प की दृढ़ता से होती है। जब इन्सान अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है, तब कोई अंधकार उसे रोक नहीं पाता। स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की सोच की उड़ान से जन्म लेती है। हर चुनौती सीखने और बदलने का अवसर है।

दूसरा पहलू

तेहरान में एक मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें एक रोमन सम्राट को फारसी राजा के सामने घुटनों पर झुका हुआ दिखाया गया है।

अतीत को वर्तमान से जोड़ती एक मूर्ति

ईरान की राजधानी तेहरान के एंघेलाब स्क्वायर में हाल ही में एक मूर्ति का अनावरण किया गया। इसका शीर्षक 'नीलिंग बिफोर ईरान (ईरान के सामने घुटनों पर)' है। इसमें एक रोमन सम्राट को फारसी राजा शापुर प्रथम (लगभग 242-270 ईस्वी) के सामने घुटनों के बल झुका हुआ दिखाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह मूर्ति आई कहां से? और यह अभी ही क्यों लगाई गई है?

पीटर एडवेल

इसका शीर्षक 'नीलिंग बिफोर ईरान (ईरान के सामने घुटनों पर)' है। सवाल यह है कि यह मूर्ति आई कहां से और अभी ही क्यों लगाई गई?

कुछ लोग इसे ईरान के प्रतिरोधी व गौरवशाली अतीत को वर्तमान से जोड़ने का प्रतीक मान रहे हैं। जून में ईरान पर हुई अमेरिकी बमबारी के बाद इसे राष्ट्रीय प्रतिरोध के रूप में भी देखा जा रहा है।

तीसरी शताब्दी ईस्वी में प्राचीन ईरान में सासानी वंश सत्ता में आया। इसके पहले राजा अर्दशीर प्रथम ने मेसोपोटामिया में रोमन क्षेत्रों को चुनौती दी। रोमनों ने यह क्षेत्र पार्थियन से छीना था, जो सासानियन के पूर्वज थे। अर्दशीर इन क्षेत्रों को पुनः हासिल करना चाहता था। इसमें उसे कुछ हद तक सफलता भी मिली। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी शापुर प्रथम इस संघर्ष को निर्णायक स्तर तक ले गया। 250 के दशक में शापुर ने इराक, सीरिया और तुर्किये के रोमन इलाकों पर आक्रमण किए। दो बड़ी रोमन सेनाएं पराजित हुईं। 253 ईस्वी में शापुर ने एंटिओक पर अधिकार पा लिया, जो रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर था। उस समय तीरों की ऐसी भयानक वर्षा हुई थी कि थिएटर में मौजूद नागरिक भयभीत होकर भाग गए थे।

एडेसा (आज का दक्षिणी तुर्की) के युद्ध के बाद रोमन सम्राट वैलेरियन को जीवित बंदी बना लिया गया। यह इतिहास में पहली और एकमात्र बार था, जब किसी रोमन सम्राट को दुश्मन ने जिंदा पकड़ा था। वैलेरियन को हजारों बंदियों के साथ फारस ले जाया गया। उसे लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हुईं। एक के अनुसार, उसे शुश्तर में करुण नदी पर पुल निर्माण के लिए मजबूर किया गया, जिसके अवशेष आज भी बंद-ए-कैसर (सम्राट का पुल) के रूप में मौजूद हैं। दूसरी कथा में कहा जाता है कि शापुर ने वैलेरियन को घुटनों के बल झुकाकर अपने घोड़े पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया था। शापुर ने रोम पर अपनी विजय को पूरे साम्राज्य में शिल्पों व शिलालेखों के माध्यम से दर्शाया। दक्षिणी ईरान के नक्श-ए-रुस्तम का प्रसिद्ध शिलालेख तीन भाषाओं में इन विजयों का वर्णन करता है। तेहरान की नई मूर्ति इन्हीं सासानी शिल्पों से प्रेरित मानी जाती है। हालांकि, घुटनों पर बैठा व्यक्ति फिलिप प्रथम माना जाता है, पर आधिकारिक रूप से इसे वैलेरियन बताया गया है। नगर सुंदरीकरण संगठन के प्रमुख मेहदी मजहबी के अनुसार, यह मूर्ति ईरान के प्रतिरोधी इतिहास और उसके गौरवशाली अतीत को वर्तमान से जोड़ने का प्रतीक है। जून में ईरान पर हुई अमेरिकी बमबारी के बाद मूर्ति को राष्ट्रीय प्रतिरोध के रूप में भी देखा जा रहा है। शापुर की विजयगाथा 1,700 वर्ष से भी पुरानी है, जबकि ईरान अभी भी उसका जश्न मनाता है।

- द कन्वर्सेशन से

आंकड़े

विमानों की खरीद

पिछले दो वर्षों (2023 व 2024) में, भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस, इंडिगो और एअर इंडिया ने नागरिक उड्डयन उद्योग में सबसे ज्यादा विमान खरीदे हैं।

एअर इंडिया	570
इंडिगो	540
अमेरिकन एयरलाइंस	170
एमिरेट्स	166
साउथवेस्ट एयरलाइंस	156

आंकड़े बोइंग व एयरबस से सबसे ज्यादा विमान खरीदने वाली एयरलाइंस के | स्रोत : बोइंग और एयरबस

मार्कण्डेय शिव भक्ति में लीन थे, तभी यम उनके प्राण हरने वहां आ पहुंचे। महादेव प्रकट हुए और मार्कण्डेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया।

शिव कृपा से बदली नियति

अंतर्यात्रा
संकलित

मृकण्डु मुनि अपनी तपस्या, ज्ञान और भोलेनाथ के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम मरुध्वती था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और वरदान देने से पूर्व एक शर्त रखी कि वे दीर्घायु, लेकिन गुणहीन पुत्र चाहते हैं या अल्पायु, पर गुणवान पुत्र।

मृकण्डु मुनि ने गुणवान पुत्र की कामना की। कुछ समय बाद उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कण्डेय रखा गया। उसे केवल सोलह वर्ष की आयु ही प्राप्त थी। जैसे-जैसे मार्कण्डेय का सोलहवां वर्ष निकट आता गया, माता-पिता शोक में डूबने लगे। मार्कण्डेय ने इसका कारण पूछा। सच जानने के बाद मार्कण्डेय ने मृत्यु पर विजय पाने के लिए शिवजी की आराधना करने का निश्चय किया।

माता-पिता की अनुमति पाकर उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और तपस्या करने लगे। एक दिन वह शिव भक्ति में पूर्णतः लीन थे, तभी यम उनके प्राण हरने वहां आ पहुंचे। उस समय मार्कण्डेय की साधना अधूरी थी, इसलिए उन्होंने शिवलिंग से लिपटकर महादेव का स्मरण किया। शिवजी प्रकट हुए और मार्कण्डेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस घटना के कारण भगवान शिव कालांतक, यानी काल (मृत्यु) का अंत करने वाले कहलाए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 17 दिसंबर, 1959

अंतरराष्ट्रीय कम्युनिज्म का ध्येय नहीं बदला

अंतरराष्ट्रीय कम्यूनिज्म का ध्येय बदला नहीं
रूस शांति का इच्छुक : श्री हर्टर का भाषण

उत्तरी अटलांटिक रक्षा संगठन (नाटो) की मंत्रिपरिषद की बैठक में भाषण देते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री क्रिश्चियन हर्टर ने यह स्वीकार किया कि रूस शांति चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कम्युनिज्म का ध्येय नहीं बदला है।

संस्थानों को जवाबदेह बनना होगा

भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि हर उच्च शिक्षण संस्थान को अपने विकास की योजना सार्वजनिक करनी होगी।

डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल | **नीति**

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां उससे केवल डिग्रियां प्रदान करने की नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण, नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा व सामाजिक समावेशन की अपेक्षा की जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक और संरचनात्मक परिवर्तन का दस्तावेज है। यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों को कानूनी रूप प्रदान करता है और देश को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने में मानव संसाधन की भूमिका को सुदृढ़ करता है ।

कई दशकों से विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को शैक्षणिक नवाचार के बजाय अनुपालन पर अधिक समय व संसाधन खर्च करने पड़ते रहे। परिणामस्वरूप, पाठ्यक्रम समयानुकूल नहीं हो पाए, संस्थागत स्वायत्तता सीमित रही, गुणवत्ता में असमानता बढ़ी और छात्र हितों की प्रभावी सुरक्षा नहीं हो सकी। नया विधेयक इन चुनौतियों को देखते हुए स्पष्ट करता है कि नियमन का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि गुणवत्ता और विश्वास स्थापित करना होना चाहिए। इस विधेयक के अंतर्गत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) की स्थापना की गई है, जो उच्च शिक्षा के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसके अंतर्गत तीन स्वतंत्र परिषदों का गठन किया गया है- नियमन, प्रशासनिक अनुपालन और संस्थागत निगरानी के लिए विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद, मान्यता तथा गुणवत्ता आश्वासन के लिए विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद एवं शैक्षणिक मानक, पाठ्यक्रम ढांचे व अधिगम परिणाम के लिए विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद। यह संरचना पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करती है तथा हितों के टकराव को खत्म करती है। अब संस्थानों का मूल्यांकन केवल भवन, स्टाफ संख्या या प्रक्रियाओं के आधार पर नहीं, बल्कि छात्र अधिगम परिणाम, शैक्षिक गुणवत्ता, सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता व सामाजिक योगदान के आधार पर भी किया जाएगा।

हर उच्च शिक्षण संस्थान को अपनी संस्थागत विकास योजना सार्वजनिक करनी होगी, जिसमें उसके सभी लक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख होगा। इससे संस्थान परिणामों के प्रति जवाबदेह बनेंगे। विधेयक के प्रावधान के अनुसार, अब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं हो सकेंगे। इससे छात्रों को न्यूनतम गुणवत्ता मानकों की कानूनी गारंटी मिलेगी, कमजोर और भ्रामक संस्थानों से सुरक्षा होगी तथा डिग्रियों की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता बढ़ेगी। विधेयक उच्च शिक्षण संस्थानों को बाध्य करता है कि वे संकाय की योग्यता और संख्या, पाठ्यक्रम व अधिगम परिणाम, अवसंरचना, शुल्क संरचना, व मान्यता स्थिति जैसी प्रमुख जानकारियां सार्वजनिक करें। इससे शिक्षा के व्यावसायीकरण पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त व बहुविषयक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाता है। उच्च प्रदर्शन करने वाले महाविद्यालयों को चरणबद्ध रूप से डिग्री प्रदान करने की स्वायत्तता दी जाएगी। इससे छात्रों को आधुनिक और उद्योग-संगत पाठ्यक्रम, नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियां और तेज व लचीली अकादमिक प्रक्रियाओं जैसे लाभ मिलेंगे। विधेयक में कहा गया है कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रतिकूल प्रभाव छात्रों पर नहीं पड़ेगा। यदि किसी संस्थान पर जुर्माना, स्वायत्तता में कटौती या बंदी जैसी कार्रवाई होती है, तो छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी, उनकी डिग्रियों व प्रमाणपत्रों की वैधता सुरक्षित रहेगी एवं आर्थिक नुकसान से उन्हें बचाया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में मजबूत, निष्पक्ष व पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य होगी।

विधेयक के तहत प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित कर सकेंगे और उच्च प्रदर्शन वाले भारतीय विश्वविद्यालय विदेश में परिसर खोल सकेंगे। इससे छात्रों को देश में ही वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध होगी और भारतीय डिग्रियों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ेगी। मानक परिषद को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषाओं और कलाओं को समाहित करे, साथ ही वैश्विक मानकों से सामंजस्य बनाए रखे।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भारतीय उच्च शिक्षा को नियंत्रण आधारित व्यवस्था से निकालकर विश्वास, गुणवत्ता और परिणाम आधारित प्रणाली की ओर ले जाता है। यह छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सूचित चयन की स्वतंत्रता, लचीले शैक्षणिक मार्ग, वैश्विक अवसर और कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यह विधेयक भारत की युवा शक्ति को सशक्त बनाकर, देश को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। *- लेखिका भारतीय विश्वविद्यालय संघ (नई दिल्ली) की महासचिव हैं।*

पूंजी निकासी और रुपये में रिकॉर्ड गिरावट से सेंसेक्स 533 अंक लुढ़का

घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट, 22 कंपनियों के शेयर नुकसान में

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी और डॉलर के मुकाबले रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरने से घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स 533 अंक टूट गया, जबकि एनएसई निफ्टी 26,000 के नीचे बंद हुआ।

वैश्विक बाजारों में सुस्त रुख के बीच सेंसेक्स 533.50 अंक का गोता लगाकर 84,679.86 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में एक समय यह 592.75 अंक टूटकर 84,620.61 पर आ गया था। निफ्टी 167.20 अंक की गिरावट के साथ 25,860.10 पर बंद हुआ। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी 3.38 लाख करोड़ घटकर 467.64 लाख करोड़ रुपये (5.14 ट्रिलियन डॉलर) रह गई। सेंसेक्स की 30 में 22 कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे। एक्सिस बैंक सर्वाधिक 5.03 फीसदी नुकसान में बंद हुआ। टाइटन, एयरटेल समेत आठ शेयर 1.60 फीसदी तक बढ़त में रहे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, विदेशी निवेशकों की बिकवाली करने और कमजोर वैश्विक धारणा के बीच रुपये में रिकॉर्ड गिरावट ने घरेलू शेयर बाजारों को नकारात्मक दायरे में धकेल दिया।

84,679.86 के स्तर पर सेंसेक्स बंद

26,000 के नीचे निफ्टी बंद 167.20 अंक गिरा

3.38 लाख करोड़ घट गई पूंजी

ये शेयर सर्वाधिक टूटे

एक्सिस बैंक	5.03 फीसदी
इटरनल	4.69 फीसदी
एचसीएल टेक	1.90 फीसदी
टाटा स्टील	1.74 फीसदी
बजाज फिनसर्व	1.65 फीसदी

सेक्टोरल इंडेक्स भी गिरे

रियल्टी	1.36 फीसदी
बैंकेक्स	1.03 फीसदी
कमोडिटी	0.91 फीसदी
आईटी	0.90 फीसदी
वित्तीय सेवाएं	0.83 फीसदी

बीएसई मिडकैप में 0.78 फीसदी और स्मॉलकैप सूचकांक में 0.69 फीसदी की गिरावट।

2,382 करोड़ की बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को घरेलू बाजार में शुद्ध रूप से 2,381.92 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,077.48 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। एफआईआई ने सोमवार को भी 1,468.32 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।

■ बीएसई पर सूचीबद्ध 2,582 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 1,603 शेयरों में तेजी रही।

■ 139 कंपनियों के शेयर 52 सप्ताह के अपने निचले पर बंद हुए, जबकि 103 शेयर एक साल के शीर्ष पर पहुंच गए।

दुनियाभर के बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग तेज गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के प्रमुख बाजारों में मिलाजुला रुख था। अमेरिकी बाजार नुकसान में बंद हुए थे।

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से 1,700 रुपये सस्ता, चांदी भी फिसली

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों की मुनाफावसूली से सोने में लगातार चार कारोबारी सत्रों से जारी रिकॉर्ड तेजी मंगलवार को थम गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से 1,700 रुपये सस्ता होकर 1,35,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ। चांदी भी 1,000 रुपये सस्ती होकर 1,98,500 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई। सोमवार को सोना 4,000 रुपये महंगा होकर 1,37,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया था।

एलकेपी सिक्योरिटीज के रिसर्च उपाध्यक्ष (जिंस-मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा, वैश्विक बाजारों में सोने में मुनाफावसूली और अस्थिरता देखी गई, जिससे इसकी कीमतें 4,275 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर की ओर फिसल गईं एवं दबाव में रहीं। इसका असर घरेलू सराफा बाजारों में भी देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 27.80 डॉलर की कमजोरी के साथ 4,277.42 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही सोने में पांच सत्रों से जारी तेजी पर विराम लग गया।

न्यूज डायरी

बी साईराम कोल इंडिया के चेयरमैन बने

नई दिल्ली। कोल इंडिया ने बी. साईराम को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नियुक्त किया है। यह ऐसे समय में हुआ है जब घरेलू ऊर्जा की बढ़ती मांग के बीच कोल इंडिया ने रिकॉर्ड उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। साईराम ने कोयला क्षेत्र के अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा का स्थान लिया है। वे 31 अक्टूबर को पीएम प्रसाद की सेवानिवृत्ति के बाद 1 नवंबर से अंतरिम सीएमडी थे। एजेंसी

एचडीएफसी बैंक बढ़ाएगा इंडसइंड बैंक में हिस्सेदारी

नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंगलवार को इंडसइंड बैंक में हिस्सा बढ़ाकर 9.5 फीसदी तक करने की मंजूरी मिल गई है। इंडसइंड बैंक ने मंगलवार को कहा, बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों के 9.50 प्रतिशत तक की कुल हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। आरबीआई की ओर से मंजूरी एचडीएफसी बैंक द्वारा दिए गए आवेदन के संदर्भ में दी गई है। एजेंसी

आईओबी में सरकार तीन फीसदी बेचेगी हिस्सा

नई दिल्ली। सरकार बुधवार से शुरू होने वाले ऑफर फॉर सेल के जरिये इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में 3 फीसदी हिस्सा बेचेगी। इससे 2,100 करोड़ जुटाने की उम्मीद है। सरकार 38.51 करोड़ शेयर या 2 प्रतिशत हिस्सा बेचने का प्रस्ताव कर रही है। इसमें अतिरिक्त 19.25 करोड़ शेयर बेचने का विकल्प भी शामिल है। यह बैंक की कुल जारी और भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का एक फीसदी है। एजेंसी

एनसीएलटी की वेदांता के डिमर्जर को मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने वेदांता के डिमर्जर योजना को मंजूरी दे दी है। इससे समूह को एल्युमीनियम, तेल और गैस, बिजली और लोहा एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट इकाइयों में विभाजित करने में मदद मिलेगी। वेदांता प्रवक्ता ने कहा, यह मंजूरी वेदांता के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एजेंसी

ओला के प्रमोटर अग्रवाल ने बेचे 2.6 करोड़ शेयर

नई दिल्ली। ओला के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने मंगलवार को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 34.99 रुपये के भाव से 2.6 करोड़ शेयर बेचकर 92 करोड़ रुपये जुटाए हैं। अग्रवाल की सितंबर तक इस कंपनी में कुल हिस्सेदारी 30.02 फीसदी थी। मंगलवार को कंपनी का शेयर 8.5 फीसदी गिरकर 34.20 रुपये पर बंद हुआ। 9 दिसंबर को यह एक साल के निचले स्तर 33.20 रुपये तक चला गया था। एजेंसी

रुपये में गिरावट का सिलसिला जारी, अन्य एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब रहा प्रदर्शन

रुपये ने पहली बार छुआ 91 से नीचे का स्तर, इस साल 6 फीसदी से अधिक टूटा

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का सिलसिला जारी है। मंगलवार को इसने दिन के कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 36 पैसे टूटकर पहली बार 91 से नीचे का स्तर छुआ और 91.14 के अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, अंत में 15 पैसे गिरकर 90.93 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही, रुपये में 31 दिसंबर, 2024 के बाद से अब तक 6.17 फीसदी गिरावट आ चुकी है, जो एशिया की अन्य मुद्राओं के मुकाबले सबसे खराब प्रदर्शन है।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में सफलता नहीं मिलने और लगातार विदेशी पूंजी निकासी से रुपये में गिरावट आई है। चिंता की बात यह है कि डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी के बावजूद रुपये में गिरावट को रोका नहीं जा सका।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 90.87 के स्तर पर खुला। दिन में 91.14 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। अंत में कुछ सुधार के साथ 90.93 पर बंद हुआ। सोमवार को भी रुपया 90.78 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था।

90.93 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ 15 पैसे लुढ़ककर

पांच सत्र में एक फीसदी गिरावट

रुपया 10 कारोबारी सत्र में 90 से गिरकर 91 पर आ गया। यह पिछले पांच सत्र में ही डॉलर के मुकाबले एक फीसदी टूट चुका है। 3 दिसंबर, 2025 को पहली बार 90 के स्तर से नीचे बंद हुआ था।

■ इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 फीसदी की गिरावट के साथ 98.23 पर रहा।

इसी माह 92 से नीचे जाने की आशंका

फिनरेक्स ट्रेजरी सलाहकार एलएलपी के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हस्तक्षेप के अभाव में विदेशी संस्थागत निवेशक घरेलू शेयर बाजार से लगातार पूंजी निकालते रहेंगे, सट्टेबाज अमेरिकी मुद्रा/भारतीय रुपये को ऊपर ले जाते रहेंगे। केंद्रीय बैंक के पास कोई अन्य योजना होने या किसी समझौते के अंतिम रूप लेने तक रुपये के इसी महीने 92 के स्तर से नीचे जाने की आशंका है।

रुपये का एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन

मुद्रा	गिरावट/तेजी
रुपया	-6.17%
जापानी येन	-3.7%
वियतनाम डॉंग	-3.26%
फिलीपीन पेसो	-2.6%
इंडोनेशियाई रुपिया	-2.5%
द. कोरियन वॉन	-0.4%
चाइनीज युआन	3.42%
सिंगापुर डॉलर	5.14%
थाईलैंड बात	7.90%
मलयेशियाई रिंगिट	8.5%

(आंकड़े : 31 दिसंबर, 2024 से अब तक के)

2018 से रुपया में सालाना गिरावट जारी

वर्ष	टूटा	वर्ष	टूटा
2018	8.5%	2022	10.2%
2019	2.3%	2023	0.6%
2020	2.3%	2024	2.8%
2021	1.7%	2025	6.27%

गिरावट की प्रमुख वजहें

■ **व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता :** भंसाली ने कहा, ऐसी खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के नए व्यापार प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। दोनों के बीच व्यापार समझौते पर जारी अनिश्चितता और देरी से घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों का भरोसा प्रभावित हो रहा है।

■ **लगातार पूंजी निकासी :** विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस साल 16 दिसंबर तक घरेलू शेयर बाजार से 1,60,917 करोड़ की भारी निकासी की है। सिर्फ दिसंबर में ही 17,242 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं।

■ **आरबीआई का सीमित हस्तक्षेप**

आरबीआई आक्रामक रूप से हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहा है और रुपये की गिरावट को थामने के बजाय आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रहा है। केंद्रीय बैंक के सीमित हस्तक्षेप से विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार में जोखिम लेने से बच रहे हैं।

■ **घरेलू बाजार की धारणा कमजोर**

रुपये की लगातार कमजोरी शेयर बाजार पर असर डाल रही है। नवंबर में रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचने के बाद से एनएसई निफ्टी-50 1.7 फीसदी गिरा है, क्योंकि निवेशकों में घबराहट बढ़ रही है। यह गिरावट घरेलू शेयर बाजार में तेजी की रफ्तार थाम सकती है, जिसमें हाल ही में सुधार होना शुरू हुआ था।

मोबाइल पर बात करना होगा महंगा, 20% तक बढ़ेगा टैरिफ

■ कमाई बढ़ाने के लिए कंपनियों की अप्रैल-जून से तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। नए साल से मोबाइल पर बात करना महंगा हो जाएगा। कमाई और निवेश बढ़ाने के लिए दूरसंचार कंपनियां मोबाइल टैरिफ की दरों में इजाफा कर सकती हैं। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि कंपनियां अप्रैल-जून तिमाही से 4जी और 5जी प्लान की कीमतों में 16 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी करेंगी। यह पहले के अनुमान से कहीं अधिक तेजी से और जल्द बढ़ोतरी है। इसके पहले 15 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया था।

मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों ने 15 दिसंबर की एक रिपोर्ट में कहा, हमारा अनुमान है कि 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के 4जी एवं 5जी प्लान की कीमतों में तेज वृद्धि होगी। सस्ते प्लान को बंद करने और स्ट्रीमिंग सेवाओं को केवल प्रीमियम प्लान के साथ ही जोड़ने जैसे हालिया कदम यह संकेत देते हैं कि कंपनियां ग्राहकों को बढ़ी कीमतों के लिए तैयार कर रही हैं।

आठ वर्षों में यह चौथी बड़ी मूल्य वृद्धि होगी। इससे पहले कंपनियों ने 2024 में 15 फीसदी, 2021 में 20 फीसदी व 2019 में 30 फीसदी वृद्धि की थी। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, हर बार जब एयरटेल जैसी मजबूत कंपनियों ने अधिक राजस्व अर्जित किया, तो कमजोर प्रतियोगी पीछे रह गए।

कम कीमत वाले प्लान हुए बंद

हाल में दूरसंचार कंपनियों ने कम कीमत वाले प्लान हटा दिए हैं या ओवर-द-टॉप (ओटीटी) जैसी कुछ सुविधाओं को अधिक कीमत वाले प्लान में स्थानांतरित कर दिया है। इससे ग्राहकों को अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रभावी रूप से प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू) में वृद्धि हो रही है। विश्लेषकों ने कहा, हमने देखा है कि अतीत में जब भी टैरिफ में वृद्धि हुई है, भारती एयरटेल प्रमुख लाभार्थियों में से एक रही है। इसने कमजोर कंपनियों की तुलना में राजस्व में असमान रूप से अधिक वृद्धि दिखाया है।

7 वर्षों में हर ग्राहक से कंपनियां कमाएंगी 390 रुपये...एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने हाल के वर्षों में तीन बार प्रीपेड टैरिफ बढ़ाए हैं। ब्रोकरेज फर्म के मध्यम अवधि के संभावित अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2031-32 तक एआरपीयू 370 और 390 के बीच रहेगा।

एयरटेल 400 रुपये तक कमाएगी

ब्रोकरेज फर्म ने एयरटेल के संदर्भ में कहा, तीन से पांच वर्षों में कंपनी के एआरपीयू में 5-6 फीसदी की वृद्धि के लिए डाटा मोनेटाइजेशन महत्वपूर्ण कारक होगा। वह 2026 के बाद बिना टैरिफ वृद्धि के भी 400 रुपये तक कमाएगी।

एआई पर नियंत्रण के लिए जरूरी होने पर ही लाएंगे नए कानून

आईटी सचिव ने कहा, उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए देश के पास कई कानून

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सचिव एस. कृष्णन ने मंगलवार को कहा, सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए नए कानून या नियम लाने से बचना चाहती है, जब तक यह बेहद आवश्यक न हो। उन्होंने कहा, उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनी ढांचे का इस्तेमाल किया जाएगा।

उद्योग संघ एसोचैम की एआई लीडरशिप मीट में कृष्णन ने कहा, सरकार का नियामक दृष्टिकोण विचारशील एवं सावधानीपूर्वक है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यह उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार में बाधा न डाले। वैसे भी, हमारे देश में कई कानून हैं, इसलिए जब तक जरूरी न हो, कोई नया कानून या नियम न बनाया जाए। पहले यह देखने की कोशिश करें कि मौजूदा कानूनों के साथ क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा, बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिनियम और हाल ही में अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के प्रावधानों में एआई के उपयोग से जुड़े काफी मुद्दे पहले से ही शामिल किए गए हैं। एजेंसी

एआई बदलाव को संभालने के लिए देश बेहतर स्थिति में

एस. कृष्णन

सचिव ने एआई के कारण होने वाले नौकरियों के विस्थापन से संबंधित चिंताओं पर कहा, कुछ नौकरियां भले ही समाप्त हो जाएं, लेकिन अन्य नौकरियां सृजित होंगी। उन्होंने तर्क दिया कि सैद्धांतिक एआई से वास्तविक अनुप्रयोगों और कार्यान्वयन की ओर बदलाव में भारत को एक विशिष्ट लाभ मिलता है। हमारा मानव संसाधन भी अन्य कई देशों की तुलना में एआई बदलाव को संभालने के लिए बेहतर स्थिति में है और उनका वितरण भी बेहतर है।

एआई के युग में भारत की विविधता ताकत

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा, एआई के युग में भारत की भाषाई एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता एक ताकत है। उन्होंने एक कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय बदलाव का रणनीतिक चालक बताते हुए कहा, अनुमानों से संकेत मिलता है कि एआई 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 1,700 अरब डॉलर का योगदान दे सकता है।

धर्मेंद्र प्रधान

चीन को निर्यात बढ़ने से व्यापार घाटा कुछ हद तक कम करने में मिली मदद

भारत चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों यानी अप्रैल-नवंबर में चीन को निर्यात बढ़ाकर उसके साथ अपने भारी-भरकम व्यापार घाटे को कम करने में कुछ हद तक सफल हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, चीन को निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों का योगदान सर्वाधिक रहा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और समुद्री उत्पादों का स्थान रहा। ब्यूरो

निर्यात में 32.83% का भारी उछाल

12.22 अरब डॉलर का निर्यात किया भारत ने चीन को अप्रैल-नवंबर में

9.20 अरब डॉलर था यह आंकड़ा अप्रैल और नवंबर, 2024 में

व्यापार घाटे में आई कमी

6.64 अरब डॉलर रह गया चीन के साथ व्यापार घाटा कम होकर नवंबर में, 17.06 अरब डॉलर था एक साल पहले की समान अवधि में, 99.2 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2024-25 में

90.12% बढ़कर 2.20 अरब डॉलर पहुंच गया चीन को निर्यात नवंबर में

चीन शीर्ष-5 निर्यात गंतव्यों में शामिल

■ भारत ने नवंबर में जिन पांच देशों को सर्वाधिक निर्यात किया है, उनमें अमेरिका के साथ चीन भी शामिल है। इनके अलावा, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात और तंजानिया को निर्यात में भी भारी उछाल देखा गया।

39.96% बढ़ गया इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात नवंबर में

11.65% की वृद्धि रही पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में

भारतीय निवेशक हुए चतुर, विदेशी बाजारों में बढ़ा रहे निवेश का दायरा

नई दिल्ली। भारतीय निवेशक चतुर बनते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, ये निवेशक अब केवल एक ही शेयर में निवेश करने के बजाय अमेरिकी शेयर बाजार, इंडेक्स और थीमेटिक ईटीएफ, निजी बाजार के अवसरों और वैश्विक फंडों में भी निवेश कर रहे हैं।

वेस्टेड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार, यह पोर्टफोलियो निर्माण के अधिक सुनियोजित दृष्टिकोण और वैश्विक बाजार में भागीदारी को लेकर बढ़ती सहजता को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, शोध, डिजिटल साधनों और शिक्षा तक पहुंच ने इस बदलाव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर महानगरों से बाहर के शहरों में। रुपये की कीमतों में गिरावट ने वैश्विक निवेश को और भी प्रासंगिक बना दिया है। लगातार अवमूल्यन से दीर्घकालिक परिणाम ऐसे बदलते हैं जिन्हें अक्सर मुख्य आंकड़े पूरी तरह नहीं दर्शा पाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी इक्विटी और डेट में निवेश 2018-19 के 42.2 करोड़ डॉलर से चार गुना बढ़कर 2024-25 में 1.7 अरब डॉलर हो गया। एजेंसी

बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से 4.1 फीसदी घट गई एटीएफ की बिक्री

नई दिल्ली। घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानें इस महीने की शुरुआत में बड़ी संख्या में रद्द होने से दिसंबर के पहले पखवाड़े में विमान ईंधन (एटीएफ) की बिक्री चार फीसदी से अधिक घट गई। कोविड महामारी से पैदा हुए व्यवधानों से उबरने के बाद पिछले दो वर्षों से विमान ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही थी।

इंडिगो पायलट के नए कार्य अवधि नियमों, चालक दल की कमी और सर्दियों में धुंध जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। एयरलाइन ने कुल मिलाकर लगभग 5,000 उड़ानें रद्द कीं। उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक, एटीएफ की बिक्री 1-15 दिसंबर तक 3,31,400 टन रही, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 3,45,400 टन था। मासिक आधार पर बिक्री में 7.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे अन्य प्रमुख ईंधन की बिक्री बढ़ी। डीजल की बिक्री सालाना आधार पर करीब पांच फीसदी बढ़कर 33 लाख टन हो गई। पेट्रोल की बिक्री 7.7 फीसदी बढ़कर 13.3 लाख टन रही। एलपीजी की बिक्री में 15.1 फीसदी तेजी रही। एजेंसी

स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के एआई केंद्रों को 80 लाख डॉलर की वित्तीय सहायता देगा गूगल

नई दिल्ली। गूगल ने भारत के स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सस्टेनेबल शहरों के लिए बने एआई उत्कृष्टता केंद्रों को 80 लाख डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही, स्वास्थ्य फाउंडेशन मॉडल के विकास में सहयोग के लिए 4 लाख डॉलर देगा। भारतीय भाषाओं के समाधान प्रदान करने वाले मॉडल बनाने के लिए ग्नानी.एआई, कोरोवर.एआई व भारतजेन को 50,000 डॉलर का अनुदान भी दे रहा है।

गूगल की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस बयान के अनुसार, वह स्वास्थ्य और कृषि के लिए बहुभाषी एआई संचालित एप्लिकेशन का समर्थन करने के लिए वधवानी एआई को 45 लाख डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। कंपनी ने कहा, ये घोषणाएं एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गूगल की ओर से किए गए नए सहयोगों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की शृंखला को दर्शाती हैं। एजेंसी

चार लाख डॉलर की फंडिंग की घोषणा

गूगल ने भारत के स्वास्थ्य फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए मेडगेम्मा का लाभ उठाने वाले नए सहयोगों का समर्थन करने के लिए चार लाख डॉलर की फंडिंग की घोषणा की है।

■ गूगल के इन मॉडलों का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की दक्षता बढ़ाना और रोगियों के उपचार परिणामों में सुधार करना है।

■ गूगल ने कहा, अजना लेंस अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स) के विशेषज्ञों के साथ मिलकर वह नए मॉडल को विकसित करेगा।

सेबी बोर्ड की बैठक आज | अधिकारियों की संपत्तियों के सार्वजनिक करने पर भी चर्चा कर सकता है नियामक

म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकरों के नियमों की होगी समीक्षा

मुंबई। बाजार नियामक सेबी शेयर और म्यूचुअल फंड हाउस के ब्रोकरों के नियमों की समीक्षा करेगा। साथ ही, अनिवासी भारतीयों के लिए केवाईसी जरूरतों में ढील देने और क्लोजिंग ऑक्शन सत्र भी शुरू करने पर चर्चा होगी। बोर्ड की बुधवार को बैठक होगी। इसमें नियामक के चेयरमैन सहित उच्च अधिकारियों की संपत्तियों को सार्वजनिक करने पर भी विचार किया जाएगा।

सेबी बोर्ड एक उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट पर विचार करेगा, जिसमें हितों के टकराव से बचने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्तियों के सार्वजनिक खुलासे की सिफारिश की गई है। बैठक में नियामक पैनल की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसमें सेबी के शीर्ष अधिकारियों के हितों के टकराव को दूर करने के लिए अधिक खुलासे के जरिये पारदर्शिता लाने के लिए सुधारों का प्रस्ताव है। पैनल ने नवंबर में पांडे को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुरक्षित व गुमनाम व्हिसलब्लोअर प्रणाली स्थापित करने, महंगे उपहारों पर प्रतिबंध लगाने और मुख्य आचार एवं अनुपालन अधिकारी का पद सृजित करने की भी सिफारिश है।

म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर के नियमों के संबंध में पहले ही विनियमों पर परामर्श पत्र जारी किए गए थे। अक्तूबर में म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर परामर्श पत्र जारी किया था। इसमें कुल खर्च अनुपात (टीईआर) की स्पष्ट परिभाषा व ब्रोकरेज शुल्कों पर संशोधित सीमाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और गैर जरूरतों को कम करना और अनुपालन को आसान बनाना है। एजेंसी

0.05% अतिरिक्त खर्च को हटाने की योजना

प्रस्तावित ढांचे के तहत सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) की ओर से म्यूचुअल फंड योजनाओं पर लगने वाले अतिरिक्त खर्च 0.05 फीसदी को हटाने की योजना बनाई है। पहली बार 2012 में 0.20 फीसदी व 2018 में घटाकर 0.05 फीसदी कर दिया गया था। सेबी ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और स्टांप ड्यूटी जैसे सभी करों को टीईआर से बाहर रखने का सुझाव दिया है। साथ ही ब्रोकरेज, एक्सचेंज और नियामक शुल्कों के लिए वर्तमान में मंजूर खर्चों को भी शामिल करने की बात कही है।

PREMIUM NEWSPAPER ACCESS💥

RECRUITING NEW MEMBERS AFTER MANY MONTHS

📚Indian Newspapers:

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

🎈**Access to all this In Just 19 Rupees [lifetime Validity]**

Click below to

Join

📚International Newspapers Channel

📚 Magazine Channel (National & International)